JOTI JOURNAL
SUBJECT-INDEX
FEBRUARY-DECEMBER - 2019

संपादकीय		1
संपादकीय		49
संपादकीय		111
संपादकीय		187
Editorial		277
Editorial		303

PART-I
(ARTICLES & MISC.)

1.	Annual Training Calendar for the Year 2019	43
2.	Appointment of Judges in High Court of Madhya Pradesh	193
3.	Appointment of Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde as Chief Justice of India	305
4.	Appointment of Hon'ble Shri Justice Ravi Shankar Jha as Chief Justice of Punjab and Haryana High Court.	307
5.	Appointment of Hon'ble Shri Justice Jitendra Kumar Maheshwari as Chief Justice of Andra Pradesh High Court	308
6.	Hon’ble Shri Justice Huluvadi G. Ramesh demits office	118
7.	Hon’ble Shri Justice S.K. Seth, Chief Justice of Madhya Pradesh demits office	192
8.	Transfer and Demits Office	53
9.	Transfer of Hon'ble Shri Justice Vivek Agrawal to Allahabad High Court	309
10.	Welcome to Hon'ble the Chief Justice Shri Ajay Kumar Mittal	306
11.	Photographs	3
12.	Photographs	51
13.	Photographs	113
14.	Photographs	189
15.	Photographs	279
16.	Photographs	310-314

17.	Justice Hurried!! Time to Re-think	38
18.	Sexual Offences and Sentencing Policy	5
19.	Trial of Wild Life Offences – An overview	82
20.	अभियुक्त के विशेषतः ज्ञान के तथ्यों के बारे में	25
21.	दाण्डिक पुनरीक्षण	55
22.	इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख : विधि एवं प्रक्रिया–साक्ष्य में ग्राह्यता, साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना, प्रमाण, साक्ष्यिक मूल्य एवं प्रकीर्ण विषय	119
23.	बेल नॉट जेल	195
24.	मोटर यान अधिनियम के अधीन मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण	253
25.	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में योगदायी (Contributory) एवं सम्मिश्र (Composite) उपेक्षा संबंधी विधि	285
26.	धारा 29 एवं 30 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 : वैधानिक स्थिति	315

PART-II
(NOTES ON IMPORTANT JUDGMENTS)

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.)
स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.)

Sections 12 (1) (a), 12 (1) (f), 12 (2), 13 and 23-J – (i) Composite suit for eviction by special category of landlord including ground of *bonafide* requirement and also other grounds specified in the Act is maintainable in Civil Court.
(ii) Where notice sent by counsel directed that arrears of rent should be paid to his client, tenant is required to tender rent to landlord and refusal by counsel to accept rent is valid.
(iii) Plaintiff is entitled to decree of eviction in default in deposit of rent during pendency of proceedings.

धाराएं 12 (1) (क), 12 (1) (च), 12 (2), 13 एवं 23–ञ – (i) विशेष श्रेणी के भवन स्वामी द्वारा सद्भाविक आवश्यकता के आधार सहित तथा अधिनियम में वर्णित अन्य आधारों पर भी निष्कासन के लिए सम्मिश्रित वाद सिविल न्यायालय में प्रचलनीय है।
(ii) जहां अभिभाषक द्वारा प्रेषित सूचना पत्र में यह निर्देश दिया जाता है कि अवशेष किराए का भुगतान उसके पक्षकार को किया जाना चाहिए, वहां किरायेदार को किराए का भुगतान भवन स्वामी को करना चाहिए तथा अभिभाषक द्वारा ऐसा निविदत्त किराया स्वीकार न करना उचित है।
(iii) वाद लंबन के दौरान किराया अदायगी में व्यतिक्रम, वादी को निष्कासन की आज्ञप्ति का अधिकारी बनाता है। **101 179**

Sections 12 (1) (c) and 12 (1) (f) – (i) Tenant is estoppled from raising plea regarding title and liable to be evicted under Section 12(1)(c) where relationship of landlord and tenant is admitted in various documents and duly proved by landlord.
(ii) Age of landlord is not a bar to seek relief of eviction under Section 12(1)(f).
(iii) Assessment of bonafide requirement should be on the basis of subjective satisfaction of the landlord – Once *bonafide* need is established, the suitability of accommodation cannot be interfered by Court.
(iv) Bonafide requirement on the ground of expansion of business cannot be inferred only through statistics and a person with reduced sale over the years can undertake expansion.

धाराएं 12 (1) (ग) एवं 12 (1) (च) – (i) किरायेदार स्वत्व को चुनौती देने के विबंधित है तथा धारा 12 (1) (सी) के अधीन निष्कासन के लिए उत्तरदायी है जब भवन स्वामी और किरायेदार के संबंध विभिन्न दस्तावेजों में स्वीकार किए गए और भवन स्वामी द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए।
(ii) भू–स्वामी की आयु धारा 12(1)(च) के अधीन निष्कासन का अनुतोष मांगने के लिए बाधा नहीं है।
(iii) सदभाविक आवश्यकता का मूल्यांकन भवन स्वामी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर किया जाना चाहिए – एक बार यदि सदभाविक आवश्यकता स्थापित हो जाती है, तो स्थान की उपयुक्तता पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

(iv) व्यवसाय के विस्तार के आधार पर सदभाविक आवश्यकता को केवल आंकड़ों के आधार पर आंकलित नहीं किया जा सकता है तथा कई वर्षों से कम बिक्री वाला व्यक्ति अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकता है। **102** **181**

Section 12 (1) (c) and (f) – (i) Denial of title.

(ii) Insertion of additional ground of eviction during the pendency of suit.

धारा 12 (1) (c) एवं (f) – (i) शीर्षक का खंडन।

(ii) वाद लंबन के दौरान निष्कासन के नए आधार को सम्मिलित करना। **263*** **507**

Section 12 (1) (f) – See Order 6 Rule 17 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 12 (1) (च) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 6 नियम 17।

109* **190**

Sections 12 and 13 – (i) Once defendant's right to defence has been striked out due to non-compliance of Section 13 (1), decree under Section 12 (1)(a) ought to be passed by the Court.

(ii) Accommodation in question given on rent to father without describing nature of business in which father was conducting business of furniture and permitted his son to open mobile shop in a part of the shop – Held, in absence of description of nature of business, it cannot be said that father has sub-let the part of accommodation.

(iii) *Bonafide* denial of title of landlord by the tenant due to pendency of title suit in Court does not come under the category of nuisance.

धाराएं 12 एवं 13 – (i) जब एक बार धारा 13 (1) के अननुपालन के कारण प्रतिवादी की प्रतिरक्षा काट दी गई है, तब न्यायालय को धारा 12 (1)(क) के अंतर्गत आज्ञप्ति पारित करना चाहिए।

(ii) व्यवसाय की प्रकृति का उल्लेख किये बिना प्रश्नगत स्थान पिता को भाड़े पर दिया गया था जिस पर पिता द्वारा फर्नीचर का व्यवसाय चलाया जा रहा था और उसने अपने पुत्र को दुकान के एक भाग में मोबाइल की दुकान खोलने की अनुमति दी – अभिनिर्धारित, व्यवसाय की प्रकृति के उल्लेख के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि पिता ने स्थान के भाग को उपभाड़े पर दिया है।

(iii) स्वत्व से संबंधित वाद के न्यायालय में लंबित रहने के कारण अभिधारी द्वारा भू–स्वामी के स्वत्व को सद्भाविक रूप से इंकार करना न्यूसेंस की श्रेणी में नहीं आता है।

151* **269**

Sections 12 and 17 – (i) *Bonafide* requirement of premises cannot be doubted on son of landlord being engaged in business in the meantime as son cannot be expected to sit idle till decision in eviction suit.

(ii) Evicted tenant can claim re-entry on premises vacated for shop of son of landlord, if business not started – Such shop cannot be held alternative accommodation for another son.

धाराएं 12 एवं 17 – (i) परिसर की सद्भावी आवश्यकता पर भूमि स्वामी के पुत्र का बीच में व्यापार में संलग्न हो जाने के आधार पर इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि निष्कासन के दावे में निर्णय तक पुत्र से खाली बैठे रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

(ii) निष्कासित अभिधारी भूमि स्वामी के पुत्र के लिए कराए गए रिक्त परिसर में पुनः प्रवेश का दावा कर सकता है, यदि व्यवसाय आरंभ नहीं किया जाता है – ऐसी दुकान को अन्य पुत्र के लिए वैकल्पिक स्थान नहीं माना जा सकता है। **51** **117**

Section 13 – Section 13 confers no power on the Court to condone defaults in payment of rent after filing of suit.

धारा 13 – धारा 13 वाद संस्थापन के पश्चात् भाटक के भुगतान में व्यतिक्रम को क्षमा करने की शक्ति न्यायालय को प्रदान नहीं करती है। **52** **118**

ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996
माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996

Sections 7 and 11 – (i) While interpreting arbitration agreement, it must be construed strictly.

(ii) When arbitration clause specifically excludes any dispute where the insurance company had denied the liability, such a dispute is not referable to arbitration and the only remedy is to institute a civil suit.

धाराएं 7 एवं 11 – (i) मध्यस्थता अनुबंध की व्याख्या करते समय, उसका निर्वचन कठोर अर्थ में किया जाना चाहिए।

(i) जब मध्यस्थता खंड विशेष रूप से उन विवादों को अपवर्जित करता था जहां बीमा कंपनी ने दायित्व से इंकार किया था, ऐसा विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित योग्य नहीं है तथा एक मात्र अनुतोष सिविल वाद संस्थित करता है। **103** **183**

Section 47– See Item 12 of Schedule I of the Stamp Act, 1899.

धारा 47 – देखें स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I का मद 12। **47*** **108**

Section 47– See Sections 9, 17 and 29 of the Limitation Act, 1963.

धारा 47 – देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 की धाराएं 9, 17 एवं 29। **36** **81**

ARMS ACT, 1959
आयुध अधिनियम, 1959

Sections 25 (1AA) and 25 (1B)(a) – Mere possession of loaded country-made pistol is punishable under Section 25 (1B)(a) – Section 25 (1AA) is applicable when accused is found involved in manufacture of such pistol.

धाराएं 25 (1कक) एवं 25 (1ख) (क) – भरे देशी कट्टे का मात्र आधिपत्य धारा 25 (1ख)(क) के अधीन दण्डनीय है – धारा 25 (1कक) तब लागू होती है जब अभियुक्त ऐसे कट्टे के निर्माण में संलग्न होना पाया जाता है। **53*** **119**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
BENAMI TRANSACTION (PROHIBITION) ACT, 1988		
बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988		
Section 4 – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 4 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11।	**268**	**515**
CIVIL PRACTICE:		
सिविल प्रथाः		
– See Order 41 Rule 5 of the Civil Procedure Code, 1908.		
– देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 41 नियम 5।	**7***	**14**
– See Section 147 (1) of the Motor Vehicles Act, 1988.		
– देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 147 (1)।	**240**	**466**
– See Section 168 of the Motor Vehicles Act, 1988.		
– देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 168।	**1**	**1**
CIVIL PROCEDURE CODE, 1908		
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908		
Section 9, Order 7 Rule 7 and Order 22 Rules 3, 4 and 11 – (i) Impleadment of legal representatives.		
(ii) Grant of the lesser relief or smaller version of the relief claimed or prayed for.		
(iii) Jurisdiction of Civil Court.		
धारा 9, आदेश 7 नियम 7, आदेश 22 नियम 3, 4 एवं 11 – (i) विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाना।		
(ii) सिविल न्यायालय प्रार्थित या दावाकृत अनुतोष का छोटा या अल्प भाग प्रदान करना।		
(iii) सिविल न्यायालय की अधिकारिता।	**312**	**601**
Sections 21 and 47 – Objection as to territorial jurisdiction and pecuniary jurisdiction cannot be allowed by the Executing Court.		
धाराएं 21 एवं 47 – निष्पादन न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारिता और आर्थिक अधिकारिता के संबंध में आपत्ति अनुज्ञात नहीं की जा सकती है।	**104***	**185**
Section 47 and Order 21 Rule 47 – Whether detailed inquiry by taking evidence of objector is necessary on objection being filed under Section 47 and Order 21 Rule 47 CPC?		
धारा 47 एवं आदेश 21 नियम 47 – क्या धारा 47 एवं आदेश 21 नियम 47 सीपीसी के अंतर्गत आपत्ति प्रस्तुत होने पर आपत्तिकर्ता की साक्ष्य लेकर विस्तृत जांच किया जाना आवश्यक है?	**201**	**385**
Section 96, Order 9 Rule 13 and Order 43 Rule 1 – Remedy against *ex-parte* decree.		
धारा 96, आदेश 9 नियम 13 एवं आदेश 43 नियम 1 – एक पक्षीय डिक्री के विरूद्ध उपचार।	**264**	**507**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 96 and Order 20 Rule 4 (2) read with Order 41 Rule 31 – Powers and duties of the First Appellate Court.		
धारा 96 एवं आदेश 20 नियम 4 (2) सहपठित आदेश 41 नियम 31 – प्रथम अपीलीय न्यायालय की शक्तियां एवं कर्तव्य।	**3**	**7**
Section 96 and Order 23 Rule 3 – Maintainability of appeal against the award of Lok Adalat.		
धारा 96 एवं आदेश 23 नियम 3 – लोक अदालत के पंचाट के विरूद्ध अपील की पोषणीयता।	**2***	**6**
Section 144 – Application for restitution under Section 144 lies where a decree or an order is varied or reversed in appeal, revision or any other proceeding or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose.		
धारा 144 – धारा 144 के तहत प्रत्यास्थापन के लिये आवेदन तब प्रस्तुत हो सकता है जब किसी डिक्री या आदेश को अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में बदला या अपास्त किया जाए अथवा इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपान्तरित किया जाए।	**105**	**186**
Section 151 – See Section 24 of the Hindu Marriage Act, 1955.		
धारा 151 – देखें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24।	**28***	**62**
Section 151 – When inherent jurisdiction can be exercised?		
धारा 151 – कब अंतर्निहित क्षेत्राधिकार प्रयुक्त किया जा सकता है?	**4***	**11**
Sections 151 and 152 – Amendment of partition decree – In order to make such partition decree executable, sketch map of disputed property should be made part of a decree.		
धाराएं 151 एवं 152 – विभाजन डिक्री का संशोधन – ऐसी विभाजन डिक्री को निष्पादन योग्य बनाए जाने हेतु, विवादित संपत्ति के रेखा मानचित्र को डिक्री का भाग बनाया जाना चाहिए।	**54***	**120**
Section 151 and Order 18 Rule 17 – Power of recalling witness with respect to Order 18 Rule 17 and Section 151.		
धारा 151 एवं आदेश 18 नियम 17 – आदेश 18 नियम 17 एवं धारा 151 के संदर्भ में साक्षी को पुनः बुलाने की शक्ति।	**5**	**12**
Order 1 Rule 10 – Impleadment of daughters as necessary parties in a suit for partition of ancestral property.		
आदेश 1 नियम 10 – पैतृक संपत्ति के विभाजन हेतु वाद में पुत्रियों का आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजन।	**265**	**511**
Order 1 Rule 10 – (i) Plaintiffs cannot be compelled to add a stranger to the suit where he is not a necessary party.		
(ii) Test to determine a necessary party; explained.		
(iii) A stranger making his claim independently and adversely to the title of landlord is neither a necessary nor a proper party in eviction suit.		

आदेश 1 नियम 10 – (i) वादीगण को एक अजनबी को उसके वाद में संयोजित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जहां वह आवश्यक पक्षकार नहीं है।

(ii) आवश्यक पक्षकार निर्धारित करने के लिए परीक्षण समझाया गया।

(iii) एक अजनबी, जो भवन स्वामी के स्वत्व के विरूद्ध स्वतंत्र रूप से अपना दावा करता है, निष्कासन के वाद में न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही उचित पक्षकार। **152** **270**

Order 1 Rule 10 and Order 9 Rule 13 – Whether it is mandatory to hear all affected parties in the appeal?

आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 9 नियम 13 – क्या अपील से प्रभावित होने वाले सभी पक्षकारों को सुना जाना आज्ञापक है। **266** **512**

Order 2 Rule 2 – See Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955.

आदेश 2 नियम 2 – देखें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13ख। **26*** **57**

Order 2 Rule 2 – Whether different period of limitation for challenging two different sale deeds would constitute two different causes of action?

आदेश 2 नियम 2 – क्या दो भिन्न विक्रय विलेखों को चुनौती देने के लिए दो भिन्न परिसीमा काल दो भिन्न वाद–हेतुक गठित करते हैं ? **267** **514**

Order 6 Rule 17 – Amendment of plaint cannot be allowed after commencement of trial unless Court is satisfied that inspite of due diligence, party could not have raised the matter before the commencement of trial and amendment may be refused if it introduces a totally different, new and inconsistent case, or challenges the fundamental character of the suit or is *malafide* or causes prejudice to other side which cannot be compensated adequately in terms of money.

आदेश 6 नियम 17 – वादपत्र में संशोधन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि सम्यक् सतर्कता के उपरांत भी पक्षकार विचारण प्रारंभ होने के पूर्व विषय को नहीं उठा सका था तथा ऐसा संशोधन तब अस्वीकार किया जा सकता है यदि वह सर्वथा नवीन और असंगत मामला प्रस्तुत करता हो या वाद के मूलभूत स्वरूप को ही चुनौती देता हो या विद्वेषपूर्ण हो या दूसरे पक्ष को ऐसी हानि कारित करता हो जिसकी धन के रूप में युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती हो।

106 **187**

Order 6 Rule 17 – (i) Amendment of written statement stands on a different footing than amendment of plaint and Courts should be more liberal while allowing amendments of a written statement.

(ii) Application for amendment should not have been rejected for want of affidavit and trial Court should have given an opportunity to file such an affidavit.

आदेश 6 नियम 17 – (i) लिखित कथन का संशोधन, वादपत्र के संशोधन की तुलना में एक पृथक पायदान पर होता है तथा लिखित कथन के संशोधन की अनुमति देते समय न्यायालयों को अधिक उदार होना चाहिए।

(ii) संशोधन हेतु आवेदन शपथपत्र के अभाव में खारिज नहीं किया जाना चाहिए था तथा विचारण न्यायालय को ऐसा शपथपत्र प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए था। **108*** **189**

Order 6 Rule 17 – Belated amendment, which is not necessary for determining the issue, cannot be allowed when trial is over and the case is fixed for final arguments.

आदेश 6 नियम 17 – विलंबित संशोधन, जो कि विवाद्यक निर्धारण हेतु आवश्यक नहीं है, तब अनुमत नहीं किया जा सकता है जब विचारण समाप्त हो चुका है एवं प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत है। **154*** **272**

Order 6 Rule 17 – Faulty description of plaintiff in plaint due to incorrect drafting by the counsel cannot be refused to be corrected when such mistake is apparent from reading the plaint.

आदेश 6 नियम 17 – अधिवक्ता द्वारा किए गए गलत प्रारूपण के कारण वादपत्र में वादी के त्रुटिपूर्ण वर्णन को सुधारने से इंकार नहीं किया जा सकता, जब ऐसी त्रुटि वादपत्र को पढ़ने से दर्शित हो। **153*** **271**

Order 6 Rule 17 – In eviction suit, amendment for change of beneficiary from unmarried daughter to unemployed son, for whose *bonafide* requirement, the eviction is sought, would not change the nature of suit.

आदेश 6 नियम 17 – निष्कासन के वाद में, लाभार्थी जिसकी सदभाविक आवश्यकता के लिए निष्कासन मांगा गया था, का अविवाहित पुत्री से बेरोजगार पुत्र में परिवर्तन, वाद की प्रकृति को नहीं बदलता। **109*** **190**

Order 6 Rule 17 – When amendment application was already pending, evidence was also led on proposed pleadings and plaintiff also giving undertaking that no new evidence shall be led by him, amendment application can be allowed even after trial had concluded and suit was fixed for final arguments.

आदेश 6 नियम 17 – जब संशोधन आवेदन पहले से ही लंबित था, प्रस्तावित अभिवचनों पर भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी तथा वादी ने यह वचन भी दिया कि वह अपने पक्ष में कोई भी नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगा, तब संशोधन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है यद्यपि विचारण समाप्त हो चुका हो तथा दावा अंतिम तर्क के लिए नियत कर दिया गया हो। **107*** **189**

Order 7 Rule 11 – If suit is clearly barred by limitation but cleverly drafted to overcome limitation, suit can be rejected under Order 7 Rule 11(d).

आदेश 7 नियम 11 – यदि वाद स्पष्टतः परिसीमा द्वारा बाधित है किन्तु परिसीमा के भीतर लाये जाने के उद्देश्य से चातुर्यपूर्ण तरीके से प्रारूपित किया गया हो, तो वाद आदेश 7 नियम 11(घ) के अंतर्गत नामंजूर किया जा सकता है। **155*** **272**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Order 7 Rule 11 – See Section 69 of the Partnership Act, 1932.		
आदेश 7 नियम 11 – देखें भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69।	**323***	**622**
Order 7 Rule 11 – Factors to be considered at the stage of application under Order 7 Rule 11.		
आदेश 7 नियम 11 – वादपत्र का नामंजूर किए जाने के स्तर पर विचारणीय तत्व।	**268**	**515**
Order 7 Rule 11 – Whether plaint can be rejected in part or only against one of the defendants?		
आदेश 7 नियम 11 – क्या वादपत्र प्रतिवादियों में से एक के विरूद्ध या अंशतः नामंजूर किया जा सकता है?	**269**	**516**
Order 8 Rule 6A – Whether counter-claim can be filed after closing of plaintiff evidence?		
आदेश 8 नियम 6क – क्या वादी साक्ष्य की समाप्ति पश्चात् प्रतिदावा संस्थित किया जा सकता है?	**270**	**517**
Order 9 Rule 9 – Requisite approach for deciding application for restoration of suit.		
आदेश 9 नियम 9 – वाद के पुनर्स्थापन के लिए आवेदन के निराकरण हेतु अपेक्षित दृष्टिकोण।	**202***	**388**
Order 9 Rule 9 – While considering application for restoration of suit dismissed in default, it has to be determined whether party to the suit honestly and sincerely intended to remain present before the Court when it was called on and did its best to do so.		
आदेश 9 नियम 9 – व्यतिक्रम में खारिज वाद के पुनर्स्थापन के आवेदन पर विचार करते समय यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या वाद का पक्षकार निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना चाहता था जब उसे पुकारा गया था और ऐसा करने के लिए उसने यह सर्वोत्तम किया था जो वह कर सकता था।	**110**	**190**
Order 9 Rule 9 and Order 17 Rules 2 and 3 – Appeal against dismissal of suit under Order 17 Rule 2 or Rule 3 is not maintainable – Proper remedy is to file application under Order 9 Rule 9.		
आदेश 9 नियम 9 एवं आदेश 17 नियम 2 व 3 – आदेश 17 नियम 2 या नियम 3 के अंतर्गत वाद की खारिजी के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है – उचित उपचार आदेश 9 नियम 9 के तहत आवेदन प्रस्तुत करना है।	**55**	**120**
Order 9 Rule 13 – Whether an *ex-parte* decree can be set aside on application of a defendant against whom no relief is granted?		
आदेश 9 नियम 13 – क्या एकपक्षीय आज्ञप्ति एक ऐसे प्रतिवादी के आवेदन पर अपास्त की जा सकती है, जिसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं दिया गया हो?	**271**	**518**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Order 16 Rule 14 – See Section 169 of the Motor Vehicles Act, 1988.

आदेश 16 नियम 14 – देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 169। **251** **482**

Order 21 Rule 10 and Order 41 Rule 5 – (i) Ordinarily, execution proceedings of money decree shall not be stayed unless there are special circumstances.

(ii) Appellate Court can stay execution proceedings after complying with provisions of Order 41 Rule 5 sub-Rule (3) CPC – Order of appellate Court staying execution without directing judgment debtor to furnish security or deposit amount, held to be not good.

आदेश 21 नियम 10 एवं आदेश 41 नियम 5 – (i) सामान्यतया, धन की आज्ञप्ति की निष्पादन कार्यवाहियां स्थगित नहीं करना चाहिए जब तक कि विशेष परिस्थितियां न हों।

(ii) अपीलीय न्यायालय आदेश 41 नियम 5 उप–नियम (3) सि.प्र.सं. के प्रावधानों का पालन करने के बाद आज्ञप्ति का निष्पादन स्थगित कर सकता है – अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णीत ऋणी को प्रतिभूति प्रस्तुत करने अथवा राशि अदा करने का आदेश दिए बिना ही आज्ञप्ति का निष्पादन स्थगित करने का आदेश सही न होना अवधारित किया गया। **111** **192**

Order 21 Rule 15 and Order 1 Rule 9 – Execution of decree for partition without impleading necessary parties i.e. judgment debtor or even Collector, amounts to non-joinder of parties.

आदेश 21 नियम 15 एवं आदेश 1 नियम 9 – आवश्यक पक्षकार अर्थात् निर्णीत ऋणी या यहां तक कि कलेक्टर को संयोजित किये बिना विभाजन आज्ञप्ति का निष्पादन, पक्षकारों के असंयोजन की कोटि में आता है। **156*** **272**

Order 21 Rules 37 and 40 – Procedure to be adopted in Execution of money decree through detention in civil prison.

आदेश 21 नियम 37 एवं 40 – सिविल कारागार में निरोध के माध्यम से धन डिक्री के निष्पादन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया। **56** **122**

Order 21 Rule 90 – Dismissal of an application filed under Order 21 Rule 90 CPC operates as a bar for subsequent filing of fresh suit.

आदेश 21 नियम 90 – आदेश 21 नियम 90 के अधीन संस्थित आवेदन का खारिज किया जाना, पश्चात् में नया वाद संस्थित करने पर वर्जन के रूप में लागू होता है। **157*** **273**

Order 21 Rules 97, 100 and 102 – (i) Order 21 Rule 102 prohibits a transferee *pendente lite* from resisting the execution of a decree.

(ii) When decree-holder complains of resistance of execution, executing Court should decide whether the question raised by objector or resistor legally arises between the parties and can also decide whether the objector or resistor is bound by the decree and refuses to obey it – This determination need not always require recording of evidence and Court can decide it on the basis of admissions.

आदेश 21 नियम 97, 101 एवं 102 – (i) आदेश 21 नियम 102 वादकालीन अंतरिती को आज्ञप्ति के निष्पादन का विरोध करने से प्रतिबंधित करता है।

(ii) जब आज्ञप्तिधारक निष्पादन के प्रतिरोध की शिकायत करता है, तो निष्पादन न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि क्या आपत्तिकर्ता या प्रतिरोधक द्वारा उठाये गये प्रश्न पक्षकारों के मध्य विधिक रूप से उत्पन्न होते हैं तथा निष्पादन न्यायालय यह भी तय कर सकता है कि क्या आपत्ति करने वाला या प्रतिरोध करने वाला व्यक्ति आज्ञप्ति से बाध्य है और इसे मानने से इंकार कर रहा है – इस निर्धारण के लिए सदैव साक्ष्य अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं होती है और न्यायालय इसे स्वीकारोक्तियों के आधार पर निर्धारित कर सकता है। **112 194**

Order 22 Rule 4 and Order 20 Rule 12A – See Section 19 (b) of the Specific Relief Act, 1963.

आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 20 नियम 12क – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 19 (ख)। **260 497**

Order 22 Rules 5 and 12 – See Sections 28A and 53 of the Land Acquisition Act, 1894.

आदेश 22 नियम 5 एवं 12 – देखें भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धाराएं 28क एवं 53। **236 458**

Order 26 Rules 9 and 10 and Order 39 Rule 7 – Allowing cross-examination of commissioner appointed under Order 39 Rule 7 would frustrate the very purpose of the provision.

आदेश 26 नियम 9 तथा 10 एवं आदेश 39 नियम 7 – आदेश 39 नियम 7 के अंतर्गत नियुक्त कमिश्नर के प्रतिपरीक्षण की अनुमति प्रावधान के वास्तविक उद्देश्य को विफल करेगी। **57 123**

Order 38 Rule 5 – Jurisdiction and requirements for attachment of property before judgment.

आदेश 38 नियम 5 – निर्णय के पूर्व संपत्ति की कुर्की हेतु क्षेत्राधिकार एवं आवश्यकताएं। **6* 13**

Order 39 Rule 1 and 2 – At the stage when electricity sub-station had already been constructed and was being energized for supply of electricity, granting an injunction against construction of electricity sub-station would seriously affect public interest and welfare scheme for providing electricity to people in locality – No irreparable loss or injury shall be caused by denial of injunction as compensation shall be granted under Section 67 of Electricity Act, 2003, if found entitled.

आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – उस प्रक्रम पर जब बिजली उपकेन्द्र का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका था और बिजली आपूर्ति हेतु परिदत्त की जा रही थी, बिजली उपकेन्द्र के निर्माण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करना लोकहित तथा आसपास के लोगों को बिजली उपलब्ध कराने की जन कल्याणकारी योजना को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा – निषेधाज्ञा जारी करने से इंकार करने पर कोई अपूर्णीय क्षति या हानि कारित नहीं होगी क्योंकि यदि हकदार पाया जाता है, तो धारा 67 विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रतिकर प्रदान किया जायेगा। **158* 274**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Order 39 Rules 1 and 2 – *Prima facie* case; meaning of – Relevancy of the stage of the suit.		
आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ – वाद के प्रक्रम की सुसंगतता।	**203**	**388**
Order 39 Rule 2A – Requisite standard of evidence for punishment.		
आदेश 39 नियम 2क – दण्ड हेतु अपेक्षित साक्ष्य का मानक।	**204***	**390**
Order 39 Rule 2A – When power of attorney holder executed sale deed in good faith without having knowledge of order of the Court, principal is not criminally liable for the acts of his agent.		
आदेश 39 नियम 2क – जब मुख्तारनामा धारक द्वारा विक्रय विलेख का निष्पादन न्यायालय के आदेश के ज्ञान के बिना सद्भाव में किया गया, तब मालिक उसके अभिकर्ता के कृत्यों के लिये आपराधिक रूप से दायी नहीं है।	**159***	**274**
Order 39 Rule 7 – Purpose of Inspection.		
आदेश 39 नियम 7 – निरीक्षण का उद्देश्य।	**272***	**520**
Order 41 Rule 5 – Effect of ***Asian Resurfacing of Road Agency Pvt. Ltd. v. Central Bureau of Investigation*** case on stay regarding execution proceedings.		
आदेश 41 नियम 5 – निष्पादन कार्यवाहियों के स्थगन के संबंध में ***ऐशियन रिसरफेसिंग ऑफ रोड ऐजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वि. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन*** मामले का प्रभाव।	**7***	**14**
Order 41 Rule 19 – Application dismissed in default of the First Appeal.		
आदेश 41 नियम 19 – प्रथम अपील के अनुपस्थिति में खारिजी पर लागू होना।	**273***	**520**
Order 41 Rule 22 – Jurisdiction of First Appellate Court to examine the matter not challenged before it.		
आदेश 41 नियम 22 – प्रथम अपीलीय न्यायालय का उसके समक्ष आक्षेपित न किये गये मामले के परीक्षण का क्षेत्राधिकार।	**8**	**14**
Order 41 Rule 27 – Appellate Court can allow filing of documents, when documents are relevant and necessary for deciding the rights of parties involved in the appeal and satisfactory explanation for not filing such documents in suit is given.		
आदेश 41 नियम 27 – अपीलीय न्यायालय दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, जब दस्तावेज अपील में पक्षकारों के अधिकारों के विनिश्चय के लिए सुसंगत व आवश्यक है और उन्हें दावे में प्रस्तुत न करने का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाता है।	**87 (ii)***	**161**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS ACT, 2005		
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005		
Section 25 – (i) Category of offences triable under the Act. (ii) Jurisdiction to take cognizance under Section 193 of Cr.P.C.		
धारा 25 – (i) अधिनियम के अधीन विचारणीय अपराधों का प्रवर्ग। (ii) दं.प्र.सं. की धारा 193 के अधीन संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार।	**9**	**16**
COMPANIES ACT, 2013		
कम्पनी अधिनियम, 2013		
Sections 421 (3) and 433 – Scope of special provision of Section 421 (3) of the Act.		
धाराएं 421 (3) एवं 433 – अधिनियम की धारा 421 (3) के विशेष प्रावधान का विस्तार।	**10**	**18**
CONSTITUTION OF INDIA		
भारत का संविधान		
Article 20 – See Section 300 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
अनुच्छेद 20 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300।	**96***	**170**
Article 20(3) – See Sections 302 and 394 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 27 of the Evidence Act, 1872.		
अनुच्छेद 20(3) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 394 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27।	**225**	**429**
Article 21 – See Sections 2, 15, 19, 49 and 107 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.		
अनुच्छेद 21 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराएं 2, 15, 19, 49 एवं 107।	**310**	**593**
CONTRACT ACT, 1872		
संविदा अधिनियम, 1872		
Section 16 – A registered document carries with it a presumption that it was validly executed – Burden of proving that such document is vitiated due to undue influence lies upon the party who is challenging the document. Presumption as to undue influence cannot arise merely because parties are related to each other or executant was old or of weak character.		
धारा 16 – पंजीकृत दस्तावेज अपने साथ यह उपधारणा वहन करता है कि वह वैध रूप से निष्पादित किया गया है – ऐसा दस्तावेज असम्यक् असर से दूषित है, यह प्रमाणित करने का भार उस पक्ष पर होता है जो दस्तावेज को चुनौती देता है।		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
असम्यक् असर के बारे में उपधारणा मात्र इस आधार पर उत्पन्न नहीं होती कि पक्षकार एक दूसरे से संबंधित हैं या निष्पादक वृद्ध था या दुर्बल स्वभाव का था।	97 (i) & (ii)	171
COURT FEES ACT, 1870		
न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870		
Section 7 and Article 17 (iii) – In suit for declaring sale deed void where plaintiff is neither the executant nor a party to the sale deed, plaintiff is not required to pay *ad valorem* court fee and fixed court fee is payable in such cases.		
धारा 7 एवं अनुच्छेद 17 (iii) – विक्रय विलेख को शून्य घोषित किए जाने हेतु दावे में जिसमें वादी विक्रय विलेख का न तो निष्पादक है और न ही पक्षकार, वादी को मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क संदाय करना अपेक्षित नहीं है तथा ऐसे मामलों में नियत न्यायालय शुल्क संदेय है।	58*	124
CRIMINAL PRACTICE:		
दाण्डिक प्रथा :		
– Effect of the law laid down in ***Mohan Lal v. State of Punjab, AIR 2018 SC 3853,*** on pending cases.		
– ***मोहन लाल विरूद्ध स्टेट ऑफ पंजाब, एआईआर 2018 एससी 3853,*** में प्रतिपादित विधि का लंबित मामलों पर प्रभाव।	253 (ii)	485
– See Sections 13 and 17 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and Sections 173 and 362 of the Criminal Procedure code, 1973.		
– देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 13 एवं 17 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 173 एवं 362।	325	623
– See Sections 195, 391 and 340 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
– देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 195, 391 एवं 340।	17	29
– See Section 427 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
– देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 427।	171	293
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973		
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		
Sections 30, 428 and 429 – See Sections 63 and 64 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 30, 428 एवं 429 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 63 एवं 64।	29	62

Section 31 – When Magistrate convicts and sentences an accused for two offences in a trial and imposes two sentences for each offence, it is necessary for him to specify that the sentences would run concurrently or consequently.

धारा 31 – जब मजिस्ट्रेट किसी विचारण में एक अभियुक्त को दो अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट करता है और प्रत्येक अपराध के लिए दो दण्ड अधिरोपित करता है, वहां यह आवश्यक है कि वह यह विनिर्दिष्ट करे कि दण्ड एक साथ भोगे जाएंगे अथवा एक के बाद एक प्रारंभ होंगे। **113 196**

Section 125 – (i) Adultery – Eligibility of maintenance – Refusal of wife to undergo DNA examination to examine paternity of daughter – Adverse inference u/s 114, Illustration (h) of Evidence Act can be drawn to the extent that wife had been unfaithful to her husband on one or more occasions – On such inference, a decree u/s 13 (1) (i) of the Hindu Marriage Act may be granted – But it cannot deprive her to receive maintenance u/s 125 CrPC unless husband proves that she is continuously living in adultery.

(ii) Meaning of "living in adultery".

धारा 125 – (i) जारता – भरण पोषण हेतु पात्रता – पत्नी द्वारा पुत्री के पितृत्व के परीक्षण हेतु पति के आवेदन पर डीएनए परीक्षण कराए जाने से इंकार – साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (ज) के अधीन इस सीमा तक प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्नी, पति के प्रति एक या अधिक अवसरों पर विश्वासघाती थी – ऐसी उपधारणा के आधार पर, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i) के अधीन डिक्री प्रदान की जा सकती है – परंतु यह पत्नी को धारा 125 दंप्रसं के तहत भरणपोषण प्राप्त करने से वंचित नहीं कर सकता जब तक कि पति यह साबित न कर दे कि वह निरंतर जारता में रह रही है।

(ii) ''जारता में रहना'' का अर्थ। **59* 125**

Section 125 – (i) Delay in reporting cruelty is due to the fact that generally the wife does not lodge a report so that the situation does not get aggravated, but when things go out of control and become intolerable, the wife takes the drastic step of lodging the report against her husband.

(ii) Maintenance – Fundamental principles behind Section 125 CrPC – Explained.

(iii) Wife suffering from disease of fits but husband not providing her any maintenance, amounts to desertion and cruelty by husband which is a ground for wife to live separately.

धारा 125 – (i) क्रूरता की रिपोर्ट में विलंब इस तथ्य के कारण होता है कि सामान्यतया पत्नी क्रूरता की रिपोर्ट नहीं करती है ताकि स्थितियां और गंभीर न हों, परंतु जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर और असहनीय हो जाती हैं, तब पत्नी अपने पति के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराने का कठोर कदम उठाती है।

(ii) भरण–पोषण – धारा 125 दं.प्र.सं के पीछे के मौलिक सिद्धांत – समझाए गए।

(iii) पत्नी का मिर्गी के रोग से पीड़ित होना परंतु पति द्वारा उसे कोई भी भरण–पोषण न देना पति द्वारा परित्याग एवं क्रूरता की श्रेणी में आता है जो पत्नी का उससे पृथक रहने का आधार है। **160 275**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 125 – Factors to be considered in deciding quantum of maintenance.		
धारा 125 – भरणपोषण की राशि निर्धारित करने हेतु विचार योग्य बिन्दु।	**60***	**126**
Section 125 – Factors for assessment of quantum of monthly maintenance.		
धारा 125 – मासिक भरणपोषण की राशि के निर्धारण हेतु कारक।	**11**	**19**
Section 125 – (i) If the husband is an able-bodied person, he cannot refuse to maintain his wife on ground that he is not having sufficient income. (ii) Husband not ready and willing to keep his wife with him without any reasonable cause, in absence of any complaint made by husband regarding misbehavior of wife or an application u/s 9 of Hindu Marriage Act, wife is entitled for maintenance.		
धारा 125 – (i) यदि पति शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति है, तो वह अपनी पत्नी का भरणपोषण करने से इस आधार पर इंकार नहीं कर सकता कि उसकी पर्याप्त आय नहीं है। (ii) पति बिना किसी पर्याप्त कारण के उसकी पत्नि को अपने साथ रखने के लिये तत्पर एवं रजामंद नहीं है, तब पत्नि के दुर्व्यवहार के संबंध में पति द्वारा किसी परिवाद के या हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आवेदन के अभाव में, पत्नि भरण–पोषण की हकदार है।	**114***	**197**
Section 125 – Maintenance – Sufficient cause for wife to live separately.		
धारा 125 – भरण–पोषण – पत्नी का पृथक रहने का पर्याप्त कारण।	**205***	**390**
Section 125 – (i) Once the fact of execution of document is admitted by both the parties, there is no legal necessity for the applicant to establish such document by leading evidence. (ii) Where applicant and respondent entered into marriage and started living as husband and wife for considerable period of time, respondent had complete knowledge of previous marriage of the applicant, then the respondent husband cannot be permitted to challenge the validity of marriage – A party to a marriage cannot take advantage of one's own wrong – It is his legal obligation to maintain his wife.		
धारा 125 – (i) जब एक बार दस्तावेज के निष्पादन के तथ्य को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, वहां आवेदक को ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। (ii) जहां आवेदिका और प्रत्यर्थी ने विवाह किया और काफी समय तक पति–पत्नी के रूप में रहने लगे थे, प्रत्यर्थी को आवेदिका के पूर्व विवाह का पूर्ण ज्ञान था, वहां प्रत्यर्थी–पति को विवाह की वैधता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती – विवाह का एक पक्ष स्वयं के दोष का लाभ नहीं उठा सकता है – अपनी पत्नी का भरण–पोषण करना उसका विधिक दायित्व है।	**161**	**277**
Section 125 – Proof of marriage in proceedings under Section 125.		
धारा 125 – धारा 125 के अधीन कार्यवाहियों में विवाह का सबूत।	**12**	**20**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 125 – See Section 24 of the Hindu Marriage Act, 1955.		
धारा 125 – देखें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24।	**28***	**62**
Section 125 (3) – (i) Mode of recovery of arrears of maintenance.		
(ii) Whether defaulting respondent can be sentenced to imprisonment for maintenance remaining unpaid for more than one year?		
(iii) Whether sentence of imprisonment is a mode of discharge of liability?		
धारा 125 (3) – (i) भरण–पोषण के बकाया की वसूली की रीति।		
(ii) क्या एक वर्ष से अधिक पुरानी भरण–पोषण की अवशेष राशि के लिए व्यतिक्रम करने वाले अनावेदक को कारावासीय दण्ड दिया जा सकता है?		
(iii) क्या कारावासीय दण्ड दायित्व के निर्वहन का एक तरीका है?	**275**	**523**
Sections 125 and 127 – (i) Whether maintenance allowance granted u/s 125 Cr.P.C. can be altered without recording any evidence?		
(ii) Income Tax Return, evidentiary value in cases u/s 125		
धाराएं 125 एवं 127 – (i) क्या धारा 125 के अंतर्गत प्रदत्त भरण–पोषण भत्ता बिना किसी साक्ष्य के अभिलिखित किये परिवर्तित किया जा सकता है?		
(ii) धारा 125 के प्रकरणों में आयकर विवरणी का साक्ष्यिक मूल्य।	**274**	**522**
Sections 154 and 156 – High Court should not be approached u/s 482 Cr.P.C. directly without exhausting remedy available under Section 156(3).		
धाराएं 154 एवं 156 – धारा 156(3) के अधीन उपलब्ध उपचार का उपयोग किए बिना दं.प्र.सं. की धारा 482 के अधीन सीधे उच्च न्यायालय में याचिका नहीं लगाई जानी चाहिए।	**115***	**198**
Sections 154, 227 and 239 – (i) Whether it is necessary to produce certificate under Section 65B(4) of the Evidence Act at the time of taking cognizance?		
(ii) Whether steps taken by investigating officer before registering FIR amounts to investigation?		
(iii) Parameters governing application for discharge.		
धाराएं 154, 227, एवं 239 – (i) क्या संज्ञान लेने के प्रक्रम पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है?		
(ii) क्या अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किए जाने के पूर्व उठाए गए कदम अन्वेषण की कोटि में आते हैं?		
(iii) उन्मोचन हेतु आवेदन को शासित करने वाले मापदण्ड।	**276**	**525**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 154 and 378 – (i) Effect of non-reporting of essential facts in the FIR. (ii) Scope of the jurisdiction of Appellate Court in appeal against acquittal. **धाराएं 154 एवं 378** – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवश्यक तथ्यों के न लिखाये जाने का प्रभाव। (ii) दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार।	**13***	**24**
Sections 161 and 162 – Conversion of police statements into dying declaration. **धाराएं 161 एवं 162** – पुलिस कथनों का मृत्युकालिक कथन में संपरिवर्तन।	**14***	**24**
Sections 167 (1) and 167 (2) – (i) Permissibility of extension of statutory period of 60 or 90 days. (ii) Scheme, purpose and objective of Section 167. **धाराएं 167 (1) एवं 167 (2)** – (i) 60 या 90 दिवस की सांविधिक अवधि के बढ़ाये जाने की अनुज्ञेयता। (ii) धारा 167 की योजना, प्रयोजन एवं उद्देश्य।	**15**	**25**
Section 167(2) – When remand beyond statutory period of 90 days is permissible? **धारा 167(2)** – कब 90 दिवस की सांविधिक अवधि के परे निरोध अनुज्ञेय है?	**206**	**391**
Sections 173 and 362 – See Sections 13 and 17 of the Prevention of Corruption Act, 1988. **धाराएं 173 एवं 362** – देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 13 एंव 17।	**325**	**623**
Section 177 – See Section 498A of the Indian Penal Code, 1860. **धारा 177** – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498क।	**193**	**320**
Sections 177 and 179 – (i) Whether a woman forced to leave her matrimonial home on account of acts and conduct that constitute cruelty can institute proceedings within the jurisdiction of the Court where she is forced to take shelter? (ii) Jurisdiction in case of matrimonial offences **धाराएं 177 एवं 179** – (i) क्या कोई महिला जो क्रूरता का गठन करने वाले कृत्यों एवं आचरण के आधार पर अपने वैवाहिक घर को छोड़ने के लिए मजबूर होती है, उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही कर सकती है, जहां वह आश्रय लेने के लिए मजबूर है? (ii) वैवाहिक अपराध के मामले में क्षेत्राधिकार।	**306**	**584**
Sections 190 and 319 – Discharging an accused earlier, ignoring the supplementary charge-sheet which was in existence then, is not a bar to proceed against him u/s 319 Cr.P.C. on the basis of same supplementary charge-sheet again.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 190 एवं 319 – तत्समय विद्यमान अनुपूरक अभियोग–पत्र को दरकिनार कर अभियुक्त का पूर्व में उन्मोचन, पुनः उसी अनुपूरक अभियोग–पत्र के आधार पर उसके विरूद्ध धारा 319 दंप्रसं के तहत कार्यवाही करने का वर्जन नहीं है।	**61***	**127**
Sections 190 and 319 – (i) Whether an opportunity of hearing is required to be extended to the persons against whom the Court proposes to take cognizance u/s 190 of the Code?		
(ii) Whether meticulous appreciation of evidence is permissible at the time of taking cognizance u/s 190 of the Code?		
(iii) Scope of cognizance u/s 190 and 319 of the Code.		
धाराएं 190 एवं 319 – (i) क्या उन व्यक्तियों को, जिनके विरूद्ध न्यायालय संहिता की धारा 190 के अधीन संज्ञान लिया जाना प्रस्तावित करता है, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है?		
(ii) संहिता की धारा 190 के अंतर्गत संज्ञान लिये जाते समय क्या साक्ष्य का बारीकी से मूल्यांकन अनुज्ञेय है?		
(iii) संहिता की धारा 190 एवं 319 के अधीन संज्ञान का विस्तार।	**16***	**28**
Sections 190 (1) (b) and 397 – (i) Whether the Court is required to record reasons for its satisfaction of sufficient grounds for issuance of summons?		
(ii) Remedy against an order of issuance of process.		
(iii) Scope of Revisional Court.		
धाराएं 190 (1) (ख) एवं 397 – (i) क्या न्यायालय को प्रत्येक मामले में समन जारी करने के पर्याप्त कारणों की स्वयं की संतुष्टि के कारण लिखना आवश्यक है?		
(ii) आदेशिका जारी करने के आदेश के विरूद्ध उपचार।		
(iii) पुनरीक्षण न्यायालय का विस्तार।	**207**	**393**
Sections 195 and 340 – (i) Whether mere incorrect statement in *vakalatnama* can be a ground for prosecution u/s 340 of the Code?		
(ii) Pre-condition for lodging complaint on perjury by Court.		
धाराएं 195 एवं 340 – (i) क्या मात्र वकालतनामा में किये गये असत्य कथन संहिता की धारा 340 के अधीन अभियोजन का आधार हो सकता है?		
(ii) मिथ्या साक्ष्य के लिये न्यायालय द्वारा परिवाद की पूर्व शर्त।	**277**	**528**
Sections 195 and 340 – See Section 193 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 195 एवं 340 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193।	**222**	**422**
Sections 195, 391 and 340 – (i) Exercise of power to take further or additional evidence under Section 391 of Cr.P.C.		
(ii) Permissibility of questioning the character of prosecutrix.		
(iii) Whether conviction can be based on sole testimony of the prosecutrix.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(iv) Requirement of passing disparaging remarks against police officer.		
(v) Requirements for prosecution for perjury.		
धाराएं 195, 391 एवं 340 – (i) दं.प्र.सं. की धारा 391 के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य लिये जाने की शक्ति का प्रयोग।		
(ii) अभियोक्त्री के चरित्र को प्रश्नित करने की अनुज्ञेयता।		
(iii) क्या अभियोक्त्री की साक्ष्य मात्र पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है?		
(iv) पुलिस अधिकारी के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणियां करने के लिए आवश्यकताएं।		
(v) मिथ्या साक्ष्य के लिए अभियोजन हेतु आवश्यकताएं।	**17**	**29**
Sections 195 (1)(b) and 340 – (i) To invoke Section 340 r/w/s 195 (1)(b) Cr.P.C., questionable statement should have been made deliberately and consciously and should have been found to be false comparing it with unimpeachable evidence, documentary or otherwise.		
(ii) Statements made in anticipatory bail application are yet to be tested as evidence has not yet been led and preliminary investigation report submitted by investigating officer cannot be an unimpeachable evidence to prove the statements to be false.		
धाराएं 195 (1)(ख) एवं 340 – (i) दं.प्र.सं. की धारा 195 (1)(ख) सहपठित धारा 340 को लागू करने के लिए प्रश्नगत प्रकथन जानबूझकर और सचेत रूप से किया गया हो तथा इसे अचूक साक्ष्य, दस्तावेजी अथवा अन्यथा से, तुलना करने पर गलत पाया जाना चाहिए।		
(ii) अग्रिम जमानत आवेदन में किए गए कथनों का परीक्षण किया जाना शेष रहता है क्योंकि तब तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई होती है तथा कथनों को असत्य साबित करने के लिए विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट स्पष्ट साक्ष्य नहीं मानी जा सकती है।	**162***	**279**
Section 197 – See Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.		
धारा 197 – देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19।	**41**	**98**
Section 197 – When sanction to prosecute Government officer is required?		
धारा 197 – सरकारी अधिकारी के अभियोजन हेतु मंजूरी कब आवश्यक है?	**278***	**530**
Section 197 – Whether Manager of the nationalized bank can claim protection u/s 197 Cr.P.C.?		
धारा 197 – क्या एक राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रबंधक धारा 197 दं.प्र.सं. के अंतर्गत संरक्षण की माँग कर सकता है?	**279 (i)**	**530**
Section 198 – See Section 497 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 198 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 497।	**32**	**72**

Sections 200 and 203 – (i) Second complaint on same facts when first complaint dismissed on withdrawal is maintainable where the first complaint did not lead to conviction, acquittal or discharge and was not dismissed on merits.

(ii) Mentioning the fact of filing earlier complaint or reasons of its withdrawal in subsequent complaint is not necessary and they are not condition precedent for maintaining second complaint.

धाराएं 200 एवं 203 – (i) समान तथ्यों पर द्वितीय परिवाद, जब प्रथम परिवाद वापसी में खारिज हुआ, पोषणीय है जब प्रथम परिवाद में दोषसिद्धी, दोषमुक्ति या उन्मोचन नहीं हुआ और गुणागुण पर खारिज नहीं किया गया।

(ii) पश्चातवर्ती परिवाद में पूर्व में प्रस्तुत परिवाद या उसे वापस लेने के आधार के तथ्य वर्णित करना आवश्यक नहीं है और वे द्वितीय परिवाद की पोषणीयता हेतु आवश्यक शर्त नहीं हैं।

62 **127**

Sections 203, 227, 239 and 245 – Ambit and scope of powers of Court in an application for discharge.

Factors governing satisfaction of Magistrate in a private complaint at the stage of registration.

धाराएं 203, 227, 239 एवं 245 – उन्मोचन हेतु आवेदन के संदर्भ में न्यायालय की शक्तियों का क्षेत्र एवं विस्तार।

प्राईवेट परिवाद पंजीबद्ध किए जाने के स्तर पर मजिस्ट्रेट के समाधान को शासित करने वाले कारक। **280 (i) & (ii)** **532**

Sections 212, 215 and 464 – Absence of charge would vitiate conviction only if it has caused prejudice to accused and failure of justice has been occasioned.

धाराएं 212, 215 एवं 464 – आरोप की अनुपस्थिति दोषसिद्धी को मात्र तब दूषित करेगी जब उससे यदि अभियुक्त प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ है और उससे न्याय की हानि हुई है।

63 **129**

Sections 216, 386 and 464 – (i) Appellate Court can alter charge.

(ii) If some of the co-accused, charged with Section 149 IPC are acquitted and the remaining accused are less than five in number, then charge under Section 149 IPC against remaining accused collapses – However, they can be convicted with the aid of Section 34 IPC if evidence of common intention is available.

धाराएं 216, 386 एवं 464 – (i) अपीलीय न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है।

(ii) यदि धारा 149 भा.दं.सं. से आरोपित कुछ सहअभियुक्त दोषमुक्त हो जाते हैं और शेष अभियुक्त संख्या में पांच से कम हैं, तो शेष अभियुक्तगण के संबंध में धारा 149 भा.दं.सं. का अरोप निष्फल हो जाएगा – हालांकि, यदि सामान्य आशय की साक्ष्य उपलब्ध हो तो वे भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से दोषसिद्ध किए जा सकते हैं। **116** **198**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 227 – Considerations for framing of charge and discharge.		
धारा 227 – आरोप की विरचना तथा उन्मोचन के विचारणीय कारक।	**281**	**536**
Section 227 – Stage to appreciate evidence, when arises?		
धारा 227 – साक्ष्य का मूल्यांकन का स्तर किस प्रक्रम पर उद्‌भूत होता है।	**282**	**537**
Sections 227 and 239 – Considerations for discharge of accused.		
धाराएं 227 एवं 239 – अभियुक्त की उन्मुक्ति हेतु विचारणीय बिंदु।	**18**	**34**
Sections 228 and 464 – Effect of omission to frame charge.		
धाराएं 228 एवं 464 – आरोप विरचना में लोप का प्रभाव।	**283**	**538**
Section 231 – (i) Deferral of cross-examination. (ii) Guiding principles regarding conduction of criminal trial.		
धारा 231 – (i) प्रतिपरीक्षा का स्थगन। (ii) दाण्डिक विचारण के संचालन से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत।	**19**	**37**
Sections 235 (2) and 354 – (i) Accused must be provided real and effective opportunity to adduce material relating to mitigating circumstances during pre-sentence hearing which may be provided on the same day after passing of judgment of conviction, if accused is ready to submit his arguments or Court may fix a separate date for hearing on sentence. (ii) Where minimum sentence is proposed to be imposed, question of pre-sentence hearing does not arise. (iii) Appellate Court can remedy the effect of non-compliance of Section 235(2) Cr.P.C. either by remanding the matter or by itself giving an effective opportunity to the accused. (iv) Mental illness after conviction is a mitigating circumstance and 'Test of severity' for assessing mental illness propounded.		
धाराएं 235 (2) एवं 354 – (i) दण्ड पूर्व सुनवाई के समय अभियुक्त को गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों से संबंधित सामग्री प्रस्तुत करने के लिए वास्तविक और प्रभावी अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो दोषसिद्धि के पश्चात उसी दिन भी प्रदान की जा सकती है, यदि अभियुक्त अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए तैयार है अथवा न्यायालय दण्ड पर सुनवाई के लिए एक पृथक तिथि भी नियत कर सकती है। (ii) जहां न्यूनतम दण्ड प्रस्तावित किया जाता है, वहां दण्ड–पूर्व सुनवाई का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। (iii) अपीलीय न्यायालय धारा 235 (2) दं.प्र.सं. के उल्लंघन के प्रभाव के मामले को प्रतिप्रेषित कर अथवा अभियुक्त को स्वयं एक प्रभावी अवसर देकर उल्लंघन के प्रभाव का निवारण कर सकती है। (iv) दोषसिद्धि के पश्चात मानसिक बीमारी, गंभीरता कम करने वाली परिस्थिति है तथा मानसिक बीमारी का आंकलन करने के लिए 'गंभीरता का परीक्षण' के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए।	**163**	**279**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 235 (2) and 354 – See Section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 235 (2) एवं 354 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	**184**	**304**
Sections 273, 299 and 317 – Recording of evidence in absence of accused.		
धाराएं 273, 299 एवं 317 – अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेखन।	**284***	**539**
Section 300 – Accused discharged of offences u/s 13 (1)(c)(d)(e) r/w/s 13 (2) of Prevention of Corruption Act and Section 409 IPC on the ground of invalid sanction of prosecution – Special Court should have directed the prosecution to obtain valid sanction – Further, filing of new charge-sheet after obtaining valid sanction of prosecution is not barred by Section 300 Cr.P.C. and principle of double jeopardy will not apply.		
धारा 300 – अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1)(ब)(क)(म) सहपठित धारा 13 (2) तथा धारा 409 भा.दं.सं. के आरोप से, अभियोजन की अविधिमान्य मंजूरी के आधार पर उन्मोचित किया गया – विशेष न्यायालय को अभियोजन को विधिमान्य मंजूरी प्राप्त करने के निर्देश देने चाहिए थे – आगे यह भी कि, विधिमान्य मंजूरी प्राप्त करने के बाद नवीन अभियोग–पत्र प्रस्तुत करना धारा 300 दं.प्र.सं. के तहत वर्जित नहीं है और दोहरे दण्ड का सिद्धांत लागू नहीं होगा।	**96***	**170**
Section 311 – (i) Factors of duration of a case or delay in trial are irrelevant when a prayer is made for examination of a material witness. (ii) The determinative factor of whether a witness is a material witness is that whether summoning of said witness is in fact essential to the just decision of case.		
धारा 311 – (i) जब एक महत्वपूर्ण साक्षी की परीक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है तब किसी मामले की लंबित रहने की अवधि अथवा विचारण में विलंब के कारक अप्रासंगिक होते हैं। (ii) एक साक्षी तात्विक साक्षी है, यह निर्धारित करने का कारक यह है कि क्या उक्त साक्षी को बुलाना वास्तव में मामले के सही निर्णय के लिए आवश्यक है।	**164**	**284**
Section 311 – (i) Section 311 has two parts, first is discretionary while second is mandatory and imposes obligation on the Court and this power should be invoked by the Court only to meet the ends of justice. (ii) Courts should not encourage filing of successive applications for recall of a witness where reasons for non-examination in earlier stages of the case are not satisfactory.		
धारा 311 – (i) धारा 311 के दो भाग हैं, पहला विवेकाधीन है जबकि दूसरा अनिवार्य है और न्यायालय पर दायित्व अधिरोपित करता है तथा यह शक्ति न्यायालय द्वारा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही उपयोग की जानी चाहिए। (ii) न्यायालयों को साक्षी को पुनः आहूत करने के उत्तरोत्तर आवेदन प्रोत्साहित नहीं करने चाहिए जब प्रकरण के पूर्ववर्ती प्रक्रमों पर परीक्षण न कराने के कारण संतोषजनक नहीं हैं।	**165**	**286**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 311 – Recalling of prosecutrix.		
धारा 311 – अभियोक्त्री का पुनः बुलाया जाना।	**285***	**540**
Section 311 – (i) Whether a witness can be recalled to confront him with deposition of another witness? (ii) Stage for recalling a witness.		
धारा 311 – (i) क्या किसी साक्षी को अन्य साक्षी के बयान से खंडन करने हेतु पुनः आहूत किया जा सकता है? (ii) किसी साक्षी को आहूत करने का प्रक्रम।	**208***	**397**
Section 313 – Omission to frame question regarding contents of ballistic expert report during examination of accused cannot be a ground to brush aside the report if it did not cause any prejudice to accused.		
धारा 313 – अभियुक्त परीक्षण के दौरान प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ प्रतिवेदन की विषयवस्तु के संबंध में प्रश्न विरचित न करना प्रतिवेदन को दरकिनार करने का आधार नहीं है यदि उससे अभियुक्त को कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।	**64***	**134**
Section 313 – See Sections 3 and 106 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 313 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 106।	**23**	**50**
Section 313 – See Sections 34, 302 and 364 of the Indian Penal Code, 1860		
धारा 313 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34, 302, एवं 364।	**128**	**216**
Section 315 – In ordinary course, since Section 315 of the Code does not prescribe any time limit for filing an application for examination of accused as defence witness, Court shall not reject permission to examine the accused as a defence witness unless convincing reasons are not available on record.		
धारा 315 – सामान्य अनुक्रम में, चूंकि संहिता की धारा 315, अभियुक्त के बचाव साक्षी के रूप में परीक्षण हेतु आवेदन किये जाने हेतु कोई परिसीमा विहित नहीं करती, न्यायालय अभियुक्त को बचाव साक्षी के रूप में परीक्षण की अनुज्ञा को तब तक नामंजूर नहीं करेगा जब तक कि अभिलेख पर विश्वासप्रद कारण उपलब्ध न हों।	**166***	**288**
Section 319 – (i) A person can be added as accused invoking Section 319 of the Code not only for the same offence for which accused is tried but for any offence and any such offence shall be such that in respect of which all accused could be tried together. (ii) To summon an accused u/s 319 of the Code, there has to be *prima facie* evidence against such accused and complaint or testimony of the witnesses must indicate the role played by proposed accused in commission of an offence.		

धारा 319 – (i) संहिता की धारा 319 का अवलंब लेते हुये किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में न केवल उस अपराध के लिये जोड़ा जा सकता है जिसके लिये अभियुक्त विचारित किया जा रहा है बल्कि किसी भी अपराध के लिये जोड़ा जा सकता है तथा कोई भी अन्य अपराध ऐसा अपराध होना चाहिए जिसके लिये सभी अभियुक्तगण विचारित किये जा सकते थे।

(ii) संहिता की धारा 319 के अंतर्गत किसी अभियुक्त को समन करने के लिए, ऐसे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य होनी चाहिए तथा परिवाद अथवा साक्षियों की परिसाक्ष्य से प्रस्तावित अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने में अदा की गई भूमिका इंगित होनी चाहिए। **168*** **289**

Section 319 – Mere disclosure of names by some witnesses during trial is not strong and cogent evidence to add such persons as additional accused, especially when complaint is filed against family members and where names or their identities are not disclosed at first opportunity, neither in FIR nor in the statement recorded u/s 161 of the Code.

धारा 319 – विचारण के दौरान कुछ साक्षियों द्वारा मात्र नामों का प्रकटन ऐसे व्यक्तियों को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में जोड़ने के लिये यह एक दृढ़ एवं अकाट्य साक्ष्य नहीं है, विशिष्टतः तब, जब परिवाद कुटुम्ब के सदस्यों के विरूद्ध संस्थित किया गया हो और जिसमें उनके नामों या पहचान को प्रथम अवसर पर, न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में, उजागर किया गया हो। **167** **288**

Section 319 – When summoning an additional accused, test to be applied is of a degree of satisfaction that the evidence, if goes unrebutted, may lead to conviction of the proposed accused, which is more than that of a *prime facie* case as exercised at the time of framing of charge.

धारा 319 – अतिरिक्त अभियुक्त को समन करते समय, लागू होने वाला परीक्षण समाधान की ऐसी कोटि का होना चाहिए कि यदि साक्ष्य अखंडित रहती है तो प्रस्तावित अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है, जो आरोप विरचना के समय प्रयुक्त प्रथम दृष्टया मामले से अधिक हो। **117** **200**

Section 319 – (i) Court can summon as additional accused a person, whose name was not included in FIR but who could be tried together with accused.

(ii) Exercise of jurisdiction under Section 319 Cr.P.C. requires satisfaction of the Court about more than *prima facie* case as exercised at the time of framing of charge.

धारा 319 – (i) न्यायालय अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में किसी व्यक्ति को, जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल नहीं है किन्तु जिसे अभियुक्त के साथ विचारित किया जा सकता है, समन कर सकती है।

(ii) धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अधिकारिता का प्रयोग, अपराध की विरचना के समय प्रयुक्त प्रथम दृष्टया मामले से अधिक समाधान की अपेक्षा करता है। **118** **201**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 319 – (i) Whether Court can exercise power u/s 319 of the Code to summon an accused merely on the basis of statement made in examination-in-chief of witness? (ii) Summoning of additional accused.		
धारा 319 – (i) क्या साक्षी के मात्र मुख्य परीक्षण के कथनों के आधार पर न्यायालय किसी अभियुक्त को समन करने हेतु संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग कर सकता है? (ii) अतिरिक्त अभियुक्त को आहूत करना।	**286**	**540**
Section 320 – Discretion of Court while deciding application for compounding.		
धारा 320 – शमन हेतु आवेदन का निराकरण करते समय न्यायालय का विवेकाधिकार।	**209***	**397**
Section 330 – Whether an application to release lunatic u/s. 330 of the Code can be rejected on the ground that accused is released on bail?		
धारा 330 – क्या संहिता की धारा 330 के अंतर्गत किसी विकृतचित्त को छोड़ने के लिये आवेदन, इस आधार पर नामंजूर किया जा सकता है कि अभियुक्त जमानत पर छोड़ा जा चुका है?	**210***	**398**
Section 354 – See Sections 302 and 326A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 354 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 326क।	**224**	**427**
Section 354 – See Section 376 (2) of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 354 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376 (2)।	**191**	**317**
Section 357A – Additional compensation of ₹ 1,50,000/- ordered to be paid by each accused person to acid attack victim aged 19 years in addition to the compensation payable by State under Scheme for acid attack victims.		
धारा 357क – 19 वर्षीय अम्ल हमले की पीड़िता को राज्य द्वारा अम्ल हमले के पीड़ितों के लिए स्कीम के अधीन देय प्रतिकर सहित प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में ₹ 1,50,000/– अदा करने का आदेश पारित।	**169***	**290**
Section 362 – Purpose of Section 362 is only to correct clerical or arithmetical error and correction or rehearing on merits does not come under its scope.		
धारा 362 – धारा 362 का उद्देश्य मात्र लिपिकीय या अंक संबंधी त्रुटि सुधारना है तथा गुणागुण पर सुधार अथवा पुनः सुनवाई इसके विस्तार में नहीं आता।	**65***	**134**
Section 366 – Considerations for finding out the 'rarest of rare case'.		
धारा 366 – 'विरलतम से विरल मामला' पता लगाने के लिये विचार योग्य कारक।	**211**	**398**
Section 386 – Scope for Appellate Court in appeal against acquittal for offence u/s 138 of N.I. Act.		
धारा 386 – धारा 138 एन. आई. एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय की शक्ति।	**212**	**402**

Section 389 – Accused persons found in possession of "manufactured drugs" without any authorization have committed an offence both under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and NDPS Act,1985.

धारा 389 – बिना किसी प्राधिकार के 'विनिर्मित औषधि' अभियुक्तगण के आधिपत्य में पाये जाने से उन्होंने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 दोनों के तहत अपराध कारित किया है। **170 291**

Sections 389 and 357 – See Sections 138 and 148 of the Negotiable Instruments Act, 1881.

धाराएं 389 एवं 357 – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धाराएं 138 एवं 148। **321 615**

Section 394 – Application for leave to continue appeal by near relative on death of accused pending appeal can be made within 30 days of death of appellant by virtue of proviso to Section 394 Cr.P.C. and delay in filing such application can be considered during pendency of appeal also and if delay is found *bonafide*, it can be condoned.

धारा 394 – अपील के लंबित रहते दौरान अभियुक्त की मृत्यु पर निकट नातेदार द्वारा अपील जारी रखने हेतु अनुमति का आवेदन धारा 394 दं.प्र.सं. के परंतुक के आलोक में अपीलार्थी की मृत्यु से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है तथा ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब अपील के लंबित रहते दौरान भी विचार किया जा सकता है और यदि विलंब सद्भाविक पाया जाता है, तो उसे क्षमा किया जा सकता है। **66 134**

Section 397 – (i) In every criminal revision, the party/complainant on whose application the impugned order was passed, is a necessary party along with State and such party/ complainant should also be impleaded as respondent in the revision petition.

(ii) Direction by the High Court to Sessions Judge to "consider and allow" the bail application of accused persons amounts to usurping the powers and interfering in the discretionary power of the subordinate Courts and is not legal.

धारा 397 – (i) प्रत्येक आपराधिक पुनरीक्षण में, आवेदक/परिवादी, जिसके आवेदन पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, राज्य के साथ एक आवश्यक पक्षकार होता है तथा ऐसे आवेदक/परिवादी को भी संशोधन याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए।

(ii) उच्च न्यायालय का सत्र न्यायाधीश को अभियुक्तगण की जमानत अर्जी पर ''विचार कर उसे स्वीकार करने'' का निर्देश अधीनस्थ न्यायालयों की शक्ति का अतिक्रमण है एवं उनकी वैवेकीय शक्ति में हस्तक्षेप करने के समान है तथा विधिसम्मत नहीं है। **119 203**

Section 427 – Different sentences of imprisonment passed against accused in different cases registered under Section 138 Negotiable Instruments Act cannot be directed to run concurrently under Section 427 Cr.P.C. where there are different transactions, different criminal cases registered and cases decided by different judgments – However, when the cheques dishonoured arise out of the same loan transaction, it may justify the direction of concurrent running of sentences.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 427 – अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पंजीबद्ध विभिन्न मामलों में पारित विभिन्न कारावास के दण्डादेशों को समवर्ती चलाने के निर्देश धारा 427 दं.प्र.सं. के तहत नहीं दिए जा सकते हैं, जहां लेनदेन पृथक–पृथक हैं, पृथक–पृथक आपराधिक मामले पंजीबद्ध किए गए हैं और पृथक–पृथक निर्णयों द्वारा मामले निराकृत किए गए हैं – हालांकि, जब अनादरित चेक एक ही ऋण संव्यवहार से उत्पन्न हुए हों, यह दण्डादेशों के समवर्ती चलने के आदेश को सही ठहरा सकता है।	**171**	**293**
Section 437 – Whether release of accused on bail u/s 437(6) of the Code after expiration of statutory period of sixty days is mandatory?		
धारा 437 – क्या संहिता की धारा 437 (6) के अधीन 60 दिवस की सांविधिक अवधि की समाप्ति उपरांत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना आबद्धकर है?	**287**	**541**
Section 437 (6) – There need to be something more serious reasons for denying bail u/s 437(6) than mere grounds on which the bail may be refused under Section 437(1).		
धारा 437 (6) – धारा 437(6) के अधीन जमानत आवेदन अस्वीकार करने के लिए धारा 437(1) के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने के आधारों से कुछ अधिक गंभीर कारण होने आवश्यक हैं।	**120**	**205**
Sections 437 and 397 – Whether an order passed under Section 437(6) of the Code is revisable?		
धाराएं 437 एवं 397 – क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (6) के अधीन पारित आदेश पुनरीक्षण योग्य है?	**288**	**545**
Section 438 – See Sections 4 and 12 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015		
धारा 438 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराएं 4 एवं 12।	**233**	**453**
Section 439 – Conditions for bail should be proportionate to the nature and gravity of the offence and some more stringent conditions should be imposed in addition to general conditions when financial fraud of huge money is involved in the case.		
धारा 439 – जब मामले में अत्यधिक धन का आर्थिक कपट अंतर्वलित हो तब जमानत की शर्तें अपराध की गंभीरता और प्रकृति के अनुपात में होना चाहिए तथा सामान्य शर्तों के अतिरिक्त कुछ अधिक कठोर शर्तें अधिरोपित की जानी चाहिए।	**172**	**295**
Section 439 – Considerations for grant/denial of bail.		
धारा 439 – जमानत मंजूर/इंकार करने हेतु विचारणीय बिन्दु।	**20***	**42**
Section 439 – Granting of bail in cases of rape on pretext of marriage.		
धारा 439 – विवाह के आश्वासन में बलात्संग के मामलों में जमानत प्रदान किया जाना।	**289***	**548**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 451 – See Sections 52 and 52A of the Forest Act, 1927		
धारा 451 – देखें वन अधिनियम, 1927 की धाराएं 52 एवं 52क।	**215**	**409**
Sections 451 and 457 – See Section 47-D of the Excise Act, 1915 (M.P.).		
धाराएं 451 एवं 457 – देखें आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र.) की धारा 47–घ।	**291**	**551**
Section 456 – (i) Trial Court can pass an order for restoration of the possession of the property to the person who was forcibly dispossessed while convicting the accused of the trespass and if the trial Court had not passed such order while convicting the accused, the order may be passed within one month from the date of conviction. (ii) No limitation has been provided for appellate or revisional Court to make such order to restore possession of immovable property.		
धारा 456 – (i) अतिचार के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध करते समय विचारण न्यायालय सम्पत्ति के आधिपत्य के पुनर्स्थापन के लिए ऐसे व्यक्ति के पक्ष में आदेश कर सकता है जो बलपूर्वक आधिपत्यच्युत किया गया है तथा यदि विचारण न्यायालय अभियुक्त की दोषसिद्धि के समय ऐसा आदेश नहीं करता है तो ऐसा आदेश दोषसिद्धि की तिथि से एक माह के भीतर किया जा सकता है। (ii) स्थावर सम्पत्ति के आधिपत्य के पुनर्स्थापन हेतु अपीलीय अथवा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश करने के लिए कोई परिसीमा विहित नहीं की गई है।	**136**	**230**
Sections 468 and 473 – When chargesheet or complaint is filed beyond limitation as mandated u/s 468 Cr.P.C., before taking cognizance, Court must issue notice to the accused to hear him on question of condonation of delay.		
धाराएं 468 एवं 473 – जहां अभियोग पत्र या परिवाद, दं.प्र.सं. की धारा 468 में यथा समाविष्ट परिसीमा के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, तब संज्ञान लेने के पूर्व, न्यायालय को अभियुक्त को विलंब क्षमा किए जाने के प्रश्न पर उसे सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी करना चाहिए।	**67**	**136**
CRIMINAL TRIAL :		
आपराधिक विचारण :		
– Accused and deceased living in same building – Access was highly probable – Presence of accused at the scene of the offence (house of deceased) proved by cogent evidence – Accused and his father were missing since the time of offence – Injuries on body of deceased indicate signs of struggle – Accused was unable to explain injuries on his face – Post-mortem report suggested that death was not suicidal, but deceased was hanged after she lost consciousness – Absence of enmity between accused and witnesses negate chance of false implication – Voluntary extra-judicial confession was also proved – Held, the chain of circumstances are sufficient to connect the accused with the death of the deceased.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– अभियुक्त और मृतक एक ही इमारत में रहते थे – पहुँच अत्यधिक संभावित थी – घटना स्थल (मृतक का घर) पर अभियुक्त की उपस्थिति ठोस साक्ष्य से साबित हुई – अभियुक्त और उसके पिता अपराध के समय से गायब थे – मृतक के शरीर पर लगी चोटें संघर्ष के संकेत देती हैं – अभियुक्त अपने चेहरे पर आई चोटों को स्पष्ट करने में असमर्थ था – पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रकट हुआ कि मृत्यु आत्महत्या नहीं थी, अपितु मृतका को अचेत होने के बाद फांसी पर चढ़ाया गया था – अभियुक्त और साक्षियों के मध्य वैमनस्यता का अभाव, मिथ्या संलिप्तिकरण की संभावना को नकारता है – स्वैच्छिक गैर–न्यायिक संस्वीकृति भी साबित हुई – अभिनिर्धारित, परिस्थितियों की श्रृंखला अभियुक्त को मृतक की मृत्यु से संयोजित करने के लिए पर्याप्त है।	**174***	**296**
– Duty of Magistrate during trial.		
– विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट के कर्तव्य।	**279 (ii)**	**530**
– Judge should not make unmerited and undeserving remarks affecting character and reputation, specially in case of witnesses or the parties who are not before him, unless it is absolutely necessary for just and proper decision of the case and that too after affording an opportunity of explaining or defending to that witness or the party.		
– न्यायाधीश को चरित्र तथा प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली अनुपयुक्त व अयोग्य टिप्पणियां न करने का एक तत्स्थानी वक्तव्य भी होता है, विशेषकर ऐसे साक्षियों और पक्षकारों के मामले में जो उसके समक्ष नहीं हैं, जब तक कि यह मामले के ऋजु व उचित निर्णय के लिए आवश्यक न हो और वह भी ऐसे साक्षी या पक्षकार को समझाने अथवा बचाव करने का अवसर प्रदान करने के बाद ही।	**121**	**206**
– See Sections 3, 9 and 27 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 9 एवं 27।	**135**	**226**
– See Sections 101, 106 and 118 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 101, 106 एवं 118।	**21***	**43**
– See Section 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376।	**305**	**580**
– (i) Subsequent conviction and sentence of an eye witness in another case does not affect his credibility in present case.		
(ii) In light of evidence of eye witnesses and other material adduced by prosecution, non-recovery or non-production of weapon need not materially affect the case of prosecution.		
– (i) किसी अन्य मामले में एक चक्षुदर्शी साक्षी की पश्चातवर्ती दोषसिद्धि वर्तमान मामले में उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है।		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(ii) चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य सामग्री के प्रकाश में, हथियार की जप्ती या प्रस्तुति न होना, अभियोजन मामले को तात्विक रूप से प्रभावित नहीं करती।	173*	296
DISSOLUTION OF MUSLIM MARRIAGE ACT, 1939		
मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939		
Section 2 – See Sections 12, 26 and 36 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.		
भाग 2 – देखें घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धाराएं 12, 26 एवं 36।	145*	249
DOWRY PROHIBITION ACT, 1961		
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961		
Sections 3 and 4 – See Section 498A of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3 एवं 4 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498क।	193	320
Section 4 – See Sections 302 and 498A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 4 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 498क।	302	575
DRUGS AND COSMETICS ACT, 1940		
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940		
Sections 18, 27 and 28 – Before a person is convicted under Section 18(c) r/w/s 27(b)(ii) of the Act, prosecution must establish that drugs are stocked or stored for sale without license.		
धाराएं 18, 27 एवं 28 – अधिनियम की धारा 27(ख)(ii) सहपठित धारा 18(ग) के अधीन दोषसिद्ध किए जाने के पूर्व अभियोजन द्वारा यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उन औषधियों को बिना अनुज्ञप्ति विक्रय हेतु संग्रहीत या स्टॉक किया गया था।	122 (i)	209
– See Section 389 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
– देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389।	170	291
ELECTRICITY ACT, 2003		
विद्युत अधिनियम, 2003		
Section 67 – See Order 39 Rules 1 and 2 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 67 – देखे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 39 नियम 1 एवं 2।	158*	274

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 126 and 135 – Distinction between 'unauthorised use of electricity u/s 126' and 'theft of electricity u/s 135' explained.		
धाराएं 126 एवं 135 – 'धारा 126 के अधीन विद्युत के अनाधिकृत उपयोग' एवं 'धारा 135 के अधीन विद्युत की चोरी' में विभेद समझाया गया।	**123***	**210**
EVIDENCE ACT, 1872		
साक्ष्य अधिनियम, 1872		
Section 3 – Appreciation of circumstantial evidence. Appreciation of evidence regarding charge of penetrative sexual assault.		
धारा 3 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन। प्रवेशन लैंगिक हमले के आरोप के संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन।	**68 (i) & (ii)***	**136**
Section 3 – Appreciation of evidence. (i) Significance of motive for commission of offence where there is ample ocular evidence. (ii) Related and interested witness.		
धारा 3 – साक्ष्य का मूल्यांकनः (i) अपराध को कारित करने के हेतुक का महत्व जहाँ कि पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य हो। (ii) संबंधी एवं हितबद्ध साक्षी।	**213**	**405**
Section 3 – Appreciation of evidence of injured eye-witness.		
धारा 3 – आहत चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य का मूल्यांकन।	**69***	**137**
Section 3 – (i) Appreciation of evidence of injured witnesses. (ii) Appreciation of evidence of defence witnesses.		
धारा 3 – (i) आहत साक्षियों की साक्ष्य का मूल्यांकन। (ii) बचाव साक्षियों की साक्ष्य का मूल्यांकन।	**175***	**297**
Section 3 – (i) Appreciation of eye witnesses. (ii) When delay in lodging FIR is fatal?		
धारा 3 – (i) चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य का मूल्यांकन। (ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब, कब घातक है?	**176**	**298**
Section 3 – (i) Appreciation of testimony of injured witness. (ii) Credibility of testimony of witness closely related to accused. (iii) Appreciation of inconsistencies in testimonies of witnesses.		
धारा 3 – (i) आहत साक्षी की साक्ष्य का मूल्यांकन। (ii) अभियुक्त के निकट संबंधी साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता। (iii) साक्षियों की साक्ष्य में असंगतता का मूल्यांकन।	**71**	**138**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 3 – Omission of name of accused in FIR despite being known previously to witness who subsequently deposes in Court about presence of accused at the time of occurrence, is an improvement over earlier statement and a material omission.		
धारा 3 – प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के नाम का लोप जबकि साक्षी उसे पूर्व से जानता था, जो बाद में न्यायालय में घटना के समय अभियुक्त की उपस्थिति के बारे में साक्ष्य देता है, पूर्व कथन में सुधार तथा एक तात्विक लोप है।	**70***	**138**
Section 3 – See Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 3 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125।	**12**	**20**
Section 3 – See Sections 279 and 304A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 279 एवं 304क।	**182***	**303**
Section 3 – See Section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	**30**	**65**
Sections 3, 8, 25 and 27 – (i) Whether mental awareness of particular place is a fact as contemplated in Section 27 of the Evidence Act? (ii) Whether confession of the co-accused by itself can be the basis to proceed against the other accused? (iii) Effect of acquittal of accused under Section 302 of IPC on charge under Section 201 of IPC.		
धाराएं 3, 8, 25 एवं 27 – (i) क्या विनिर्दिष्ट स्थान की मानसिक जानकारी धारा 27 में अनुध्यात तथ्य है? (ii) क्या सह–अभियुक्त की संस्वीकृति स्वतः अन्य अभियुक्त के विरूद्ध अग्रसर होने का आधार हो सकती है? (iii) भा.दं.सं. की धारा 302 के अधीन अभियुक्त की दोषमुक्ति का भा.दं.सं. की धारा 201 के आरोप पर प्रभाव।	**22**	**44**
Sections 3, 8 and 27 – (i) When accused was seen following the victim and running after the incident, witnesses whose presence was natural identifying accused by reference to colour of his t-shirt, accused was stranger in small village to be identified easily, such identification in Court even in absence of test identification parade held reliable. (ii) Recovery cannot be suspected on ground of delay and investigators cannot be faulted if accused himself gives information after delay. (iii) Presence of scratch marks on the face and neck of accused after the incident, held to be another circumstance against the accused.		
धाराएं 3, 8 एवं 27 – (i) जब अभियुक्त को घटना के बाद पीड़ित का पीछा करते और भागते हुए देखा गया साक्षीगण, जिनकी उपस्थिति स्वाभाविक थी, ने अभियुक्त को उसके टी–शर्ट के		

कलर से पहचाना, अभियुक्त एक छोटे गांव में अजनबी था जिसे आसानी से पहचाना जा सकता था, न्यायालय में ऐसी पहचान, पहचान परीक्षा परेड के अभाव में भी विश्वसनीय है।

(ii) बरामदगी को विलंब के आधार पर संदेहास्पद नहीं माना जा सकता तथा यदि अभियुक्त स्वयं विलंब के पश्चात जानकारी देता है तो अन्वेषण अधिकारियों की त्रुटि नहीं मानी जा सकती।

(iii) घटना के पश्चात् अभियुक्त के चेहरे तथा गले पर खरोंच के निशानों की उपस्थिति, अभियुक्त के विरूद्ध एक अन्य परिस्थिति होना पाई गई। **72*** **140**

Sections 3, 8, 32, 45 and 157 – Appreciation of Evidence:

Relevancy of statements of prosecutrix under Section 157.

Inference of consent of prosecutrix.

Appreciation of corroborative medical evidence.

Scope of interference in appeal against acquittal.

धाराएं 3, 8, 32, 45 एवं 157 – साक्ष्य का मूल्यांकनः

धारा 157 के अंतर्गत अभियोक्त्री के कथनों की सुसंगतता।

अभियोक्त्री की सम्मति का निष्कर्ष।

सम्पुष्टिकारक चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्यांकन।

दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में हस्तक्षेप की सीमा। **230 (ii) to (v)** **443**

Sections 3, 9 and 27 – (i) Proof of dacoity with murder.

(ii) Evidentiary value of statements u/s 27.

(iii) Effect of failure to hold Test Identification Parade during investigation and non-identification of accused by prosecution witnesses.

(iv) Effect of failure to establish motive of the accused.

धाराएं 3, 9 एवं 27 – (i) हत्या के साथ डकैती का सबूत।

(ii) धारा 27 के अंतर्गत कथनों का मूल्य।

(iii) विवेचना के दौरान पहचान परेड कराने में असफल रहने तथा अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियुक्त की पहचान न करने, का प्रभाव।

(iv) अभियुक्त के हेतुक को स्थापित करने में चूक का प्रभाव। **135** **226**

Sections 3 and 32 – (i) A related witness cannot be said to be an 'interested' witness merely by virtue of being a relative of the victim.

(ii) Distinction between 'interested witness' and 'related witness'.

(iii) Appreciation of evidence of related witness.

(iv) Reliability of dying declaration.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 3 एवं 32 – (i) संबंधी साक्षी को मात्र इस कारण हितबद्ध साक्षी नहीं कहा जा सकता है कि वह पीड़ित का संबंधी है।		
(ii) संबंधी साक्षी तथा हितबद्ध साक्षी में भेद।		
(iii) संबंधी साक्षी की साक्ष्य का मूल्यांकन।		
(iv) मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता।	**124**	**211**
Sections 3 and 65B – See Sections 364A and 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3 एवं 65बी – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 364क एवं 302।	**189**	**311**
Sections 3 and 106 – (i) Principle of last seen together in circumstantial evidence.		
(ii) Principles and duty underlined under Section 313 of Cr.P.C.		
(iii) Standard of proof for defence evidence.		
धाराएं 3 एवं 106 – (i) परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत।		
(ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत रेखांकित सिद्धांत एवं कर्तव्य।		
(iii) प्रतिरक्षा साक्ष्य के लिये सबूत का स्तर।	**23**	**50**
Sections 3 and 106 – See Sections 134, 166 and 187 of Motor Vehicles Act, 1988.		
धाराएं 3 तथा 106 – देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धाराएं 134, 166 तथा 187।	**138**	**233**
Sections 3 and 118 – Appreciation of evidence:		
(i) Effect of omission of name of one of the accused in statement of one eye-witness?		
(ii) Contradiction between inquest report and post mortem report?		
(iii) Appreciation of evidence of defence of false implication?		
धाराएं 3 एवं 118 – साक्ष्य का मूल्यांकनः		
(i) किसी एक चक्षुदर्शी साक्षी के कथनों में एक अभियुक्त के नाम के लोप का प्रभाव?		
(ii) मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास का प्रभाव?		
(iii) मिथ्या संलिप्त किये जाने के बचाव की साक्ष्य का मूल्यांकन।	**290**	**549**
Sections 3 and 118 – Appreciation of testimony of injured child witness.		
धाराएं 3 एवं 118 – आहत बाल साक्षी की साक्ष्य का मूल्यांकन।	**73 (i)***	**141**
Sections 3, 138 and 139 – An accused who did not avail his right of cross-examination cannot be permitted to find fault in evidence of witnesses.		
धाराएं 3, 138 एवं 139 – एक अभियुक्त जिसने उसके प्रतिपरीक्षण के अधिकार का उपयोग नहीं किया, को साक्षी की साक्ष्य में दोष निकालने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती।	**81 (ii)***	**148**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 6 and 25 – Statement of accused to Station In-charge informing that he committed murder of his wife is admissible u/s 6 Evidence Act and can be treated as extra-judicial confession.		
धाराएं 6 एवं 25 – अभियुक्त का थाना प्रभारी को यह सूचित करते हुए कथन कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत ग्राह्य है और न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के रूप में माना जा सकता है।	**74***	**142**
Section 8 – Effect of absence of motive in cases of circumstantial evidence.		
धारा 8 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में हेतुक के अभाव का प्रभाव।	**218***	**417**
Section 9 – Appreciation of evidence relating to dock identification by minor in absence of identification at the stage of Test Identification Parade.		
धारा 9 – पहचान परेड के प्रक्रम पर पहचान के अभाव में अवयस्क द्वारा कठघरे की पहचान से संबंधित साक्ष्य का मूल्यांकन।	**229 (i)**	**440**
Section 11 – Plea of *alibi* – Deceased died due to sustaining 100% burn injuries at her matrimonial home – Deceased implicated name of accused in her dying declaration – Accused not residing with deceased in matrimonial home – Medical certificate issued by Medical Superintendent which shows that the accused was admitted in hospital and underwent surgery few days before incident and unable to move out of house, is sufficient to accept the plea of *alibi* of the accused.		
धारा 11 – अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् – मृतक की मृत्यु उसके ससुराल में 100% जलने की चोटों के कारण हुई – मृतक ने उसके मृत्युकालिक कथनों में अभियुक्त का नाम आलिप्त किया – अभियुक्त मृतक के साथ ससुराल में नहीं रह रहा था – चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण पत्र जो यह दर्शित करता है कि अभियुक्त अस्पताल में भर्ती था और घटना के कुछ दिन पूर्व उसका ऑपरेशन हुआ था तथा वह घर से बाहर निकलने में असमर्थ था, अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक् को स्वीकार करने के लिये पर्याप्त है।	**177***	**298**
Section 27 – Appreciation of Evidence: Effect of omission of important fact in FIR in case based on circumstantial evidence. Whether order of a Magistrate is mandatory for taking fingerprints of an accused?		
धारा 27 – साक्ष्य का मूल्यांकनः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में महत्वपूर्ण तथ्य के लोप का प्रभाव। क्या किसी अभियुक्त का अंगुलछाप लिए जाने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश आज्ञापक है?	**225 (i) & (iv)**	**429**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 30 – See Sections 21(c), 29 and 67 of the N.D.P.S. ACT, 1985.		
धारा 30 – देखें स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 21(ग), 29 एवं 67।	**141**	**239**
Section 32 – Appreciation of evidence: (i) Evidentiary value of dying declaration. (ii) Reliability of related witnesses.		
धारा 32 – साक्ष्य का मूल्यांकनः (i) मृत्युकालीन कथन का साक्ष्यिक मूल्य। (i) संबंधी साक्षी की विश्वसनीयता।	**299**	**569**
Section 32 – Reliabilty of dying declaration.		
धारा 32 – मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता।	**75***	**143**
Section 32 – See Sections 161 and 162 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 32 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 161 एवं 162।	**14**	**24**
Section 32 – (i) Evidentiary value of dying declaration. (ii) Identification of accused in dying declaration. (iii) Effect of interpolation of date in FIR/*Dehati Nalishi.*		
धारा 32 – (i) मृत्युकालिक कथन का साक्ष्यिक मूल्य। (ii) मृत्युकालिक कथन में अभियुक्त की पहचान। (iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट/देहाती नालिशी में तिथि के अंतरवेषण का प्रभाव।	**132**	**219**
Section 32 – (i) Relevancy of dying declaration. (ii) Reliability of two dying declarations.		
धारा 32 – (i) मृत्युकालिक कथन की सुसंगतता। (ii) दो मृत्युकालिक कथनों की विश्वसनीयता।	**125***	**214**
Section 32 – See Sections 302 and 498A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 32 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 498क।	**302**	**575**
Sections 32 and 106 – Reliability of third dying declaration.		
धाराएं 32 एवं 106 – तीसरे मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता।	**80 (ii)**	**147**
Section 62 – Under section 62 of the Indian Evidence Act, carbon copies can be taken into consideration as primary evidence.		
धारा 62 – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, की धारा 62 के अधीन कार्बन प्रति को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में विचार में लिया जा सकता है।	**122 (ii)**	**209**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 65B – See Sections 154, 227 and 239 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 65ख – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154, 227 एवं 239।	**276**	**525**
Sections 67 and 68 – See Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 67 एवं 68 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125।	**161**	**277**
Sections 68, 69 and 90 – (i) To attract the presumption regarding 30 years old document under Section 90 of Evidence Act, it should be proved that (a) the document is more than 30 years old; (b) it is produced from proper custody; (c) it is on its face free from suspicion. (ii) Proof of attestation of a document as per Section 68 of the Evidence Act is required only when the disputed document is required by law to be attested – Also since sale deed is not required by law to be attested, hence, proof of attestation as per Section 68 and 69 is not mandatory.		
धाराएं 68, 69 एवं 90 – (i) 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के संबंध में साक्ष्य अधिनियम, की धारा 90 के अधीन उपधारणा करने के लिए यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि –(ए) दस्तावेज 30 वर्ष से अधिक पुराना है; (बी) वह उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत हुआ है; (सी) वह प्रथम दृष्टि में संदेह से मुक्त है। (ii) साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार दस्तावेज के अनुप्रमाणन का प्रमाण तब आवश्यक है, जब विवादित दस्तावेज विधि द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना अपेक्षित हो – यह भी कि, चूंकि विक्रय विलेख के विधि द्वारा अनुप्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं है, अतः धारा 68 और 69 के अनुसार अनुप्रमाणन का प्रमाण अनिवार्य नहीं है।	**178**	**299**
Sections 90 and 114A – See Section 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 90 एवं 114 क – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376।	**190**	**315**
Section 101 – See Section 64 of the Limitation Act, 1963.		
धारा 101 – देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 64।	**137**	**231**
Section 101 – See Section 38 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 101 – देखें विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 38।	**149**	**253**
Sections 101, 106 and 118 – (i) Appreciation of evidence of child witness. (ii) Burden of proof in criminal cases.		
धाराएं 101, 106 एवं 118 – (i) बाल साक्षी की साक्ष्य का मूल्यांकन। (ii) दाण्डिक मामलों में सबूत का भार।	**21***	**43**
Section 106 – Appreciation of Evidence: (i) Proof of plea of *alibi*. (ii) Burden of proof in case of circumstantial evidence.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 106 – साक्ष्य का मूल्यांकनः (i) अन्यत्रता के बचाव का साबित किया जाना। (ii) परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में सबूत का भार।	**300**	**571**
Section 113-B – Presumption and essentials of dowry death – Meaning of "soon before". **धारा 113–ख** – दहेज मृत्यु की उपधारणा एवं आवश्यक तत्व – ''कुछ पूर्व'' का अर्थ।	**24**	**53**
Section 113-B – Where all three ingredients of offence of dowry death are proved, presumption u/s 113-B has to be drawn in absence of rebuttal defence evidence. **धारा 113–ख** – जहां दहेज मृत्यु के तीनों तत्व साबित हो जाते हैं, वहां खंडनीय बचाव साक्ष्य के अभाव में धारा 113–ख के तहत उपधारणा की जाएगी।	**82***	**150**
Section 114 – See Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973. **धारा 114** – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125।	**59***	**125**
Section 114 – See Sections 147 and 149 of the Motor Vehicles Act, 1988. **धारा 114** – देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धाराएं 147 एवं 149।	**241**	**468**
Section 116 – See Sections 12(1)(c) and 12(1)(f) of the Accommodation Control Act, 1961 (M.P.) **धारा 116** – देखें स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.) की धाराएं 12(1)(ग) एवं 12(1)(च)।	**102**	**181**
Section 118 – Appreciation of evidence: (i) Related witness versus Interested witness. (ii) Extra judicial confession. **धारा 118** – साक्ष्य का मूल्यांकन : (i) संबंधी साक्षी विरूद्ध हितबद्ध साक्षी। (ii) न्यायिकेत्तर संस्वीकृति।	**301**	**573**
Section 134 – (i) Appreciation of evidence in sexual offences. (ii) Effect of delay in FIR in sexual offences. **धारा 134** – (i) लैंगिक अपराधों में साक्ष्य का मूल्यांकन। (ii) लैंकिंग अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब का प्रभाव।	**134**	**224**
Section 134 – Appreciation of sole testimony of Food Inspector. **धारा 134** – खाद्य निरीक्षक की एकल साक्ष्य का मूल्यांकन।	**259**	**496**
Sections 135 and 138 – See Section 231 of the Criminal Procedure Code, 1973. **धाराएं 135 एवं 138** – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 231।	**19**	**37**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 145 – See Section 311 of the Criminal Procedure Code, 1973		
धारा 145 – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311।	**208***	**397**
Section 165 – See Section 169 of the Motor Vehicles Act, 1988.		
धारा 165 – देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 169।	**251**	**482**
EXCISE ACT, 1915 (M.P.)		
आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र.)		
Sections 34 (2), 44 and 61 – According to provision of Section 61 of the Act of 1915, Magistrate shall take cognizance of such an offence only upon complaint filed by Collector or Excise Officer not below the rank of District Excise Officer.		
धाराएं 34 (2), 44 एवं 61 – 1915 के अधिनियम की धारा 61 के प्रावधान के अनुसार, मजिस्ट्रेट ऐसे अपराधों का संज्ञान केवल कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के आबकारी द्वारा किये गये परिवाद पर ही लेगा।	**126***	**215**
Section 47-D – (i) Whether Magistrate is justified to grant opportunity of hearing to prosecution, where application is filed to release the seized vehicle under the Act?		
(ii) Relevant date of consideration for bar created under Section 47-D.		
धारा 47–घ – (i) क्या वाहन को निर्मुक्त किये जाने हेतु संस्थित आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है?		
(ii) अभिगृहीत वाहन की निर्मुक्ति हेतु 1915 के अधिनियम की धारा 47–घ के अधीन अधिरोपित वर्जना के विचार हेतु सुसंगत तिथि।	**291**	**551**
FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006		
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006		
Section 55 – There can be prosecution for offence both u/s 55 of FSS Act and u/s 188 of IPC for non-compliance of orders passed under the Act.		
धारा 55 – एफएसएस अधिनियम के तहत पारित आदेशों के अपालन के लिए इस अधिनियम की धारा 55 तथा धारा 188 भा.दं.सं., दोनों के तहत अभियोजन हो सकता है।	**76 (i)***	**144**
FAMILY COURTS ACT, 1984		
कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984		
Section 19 – (i) Whether an order of maintenance pendente lite under Section 24 of HMA is appealable?		
(ii) Quantum of Maintenance pendente lite.		
धारा 19 – (i) क्या हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन पारित वादकालीन भरण–पोषण आदेश अपील योग्य है?		
(ii) वादकालीन भरण–पोषण की दर।	**292**	**552**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
FOREST ACT, 1927		
वन अधिनियम, 1927		
Section 52 – (i) Whether confiscation proceeding and criminal proceeding in forest or wildlife offences can be undertaken simultaneously?		
(ii) Approach while deciding application for release of vehicle when confiscation proceedings are pending.		
धारा 52 – (i) क्या वन अथवा वन्य जीव अपराधों के संबंध में अधिहरण कार्यवाही तथा आपराधिक कार्यवाही एक साथ प्रारंभ की जा सकती है?		
(ii) वाहन की निर्मुक्ति हेतु आवेदन के निराकरण के दौरान दृष्टिकोण जबकि अधिहरण कार्यवाहियाँ लंबित हों।	**214**	**407**
Sections 52 and 52A – Jurisdiction of Magistrate to release vehicle once confiscation proceedings have been initiated.		
धाराएं 52 एवं 52क – मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन को निर्मुक्त किये जाने की अधिकारिता जब एक बार अधिहरण कार्यवाहियाँ प्रारंभ की जा चुकी है।	**215**	**409**
– Release of seized vehicle in forest offences.		
– वन अपराधों में अभिगृहीत वाहन की निर्मुक्ति।	**293***	**553**
GENERAL CLAUSES ACT, 1897		
सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897		
Section 27 – See Sections 147 and 149 of the Motor Vehicles Act, 1988.		
धारा 27 – देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धाराएं 147 एवं 149।	**241**	**468**
HINDU LAW:		
हिंदू विधिः		
– Nature of Hindu widow's property rights before enactment of Hindu Succession Act, 1956. Right of reversioners.		
– हिन्दू विधवा के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पूर्व संपत्ति में अधिकार की प्रकृति। उत्तरभोगियों के अधिकार।	**294 (i) & (ii)**	**554**
(i) Rights of a person after division of HUF property.		
(ii) When the birth right in HUF property is available?		
(i) हिंदू अविभक्त कुटुंब के विभाजन पश्चात् व्यक्ति के अधिकार।		
(ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में जन्म से अधिकार कब होता है?	**25**	**55**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
HINDU MARRIAGE ACT, 1955		
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955		
Section 13 – See Order 1 Rule 10 and Order 9 Rule 13 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 13 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 9 नियम 13।	**266**	**512**
Section 13B – Considerations for custody of minor children.		
धारा 13ख – अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा हेतु विचारणीय बिंदु।	**26***	**57**
Section 13B – (i) In case of divorce by mutual consent, compliance of statutory period of six months is not mandatory, on satisfaction of Court about parties living separately for more than statutory period and failure of all efforts at mediation and conciliation.		
(ii) Video conferencing can be used where parties are unable to appear in person for any just and valid reasons.		
धारा 13ख – (i) पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद के मामले में न्यायालय के पक्षकारों के वैधानिक अवधि से अधिक अवधि के लिए पृथक रहने और मध्यस्थता और पुनर्मिलन के सभी प्रयासों के विफल होने के बारे में संतुष्ट होने पर, न्यूनतम छह माह की वैधानिक अवधि का पालन किया जाना आज्ञापक नहीं है।		
(ii) जहां पक्षकार न्यायासंगत और वैध कारणों से स्वीय उपस्थिति में अक्षम हों वहां वीडियो कान्फ्रेसिंग का उपयोग किया जा सकता है।	**77**	**144**
Section 13B – Legal rights of minor daughter to claim maintenance and claim share in property of father cannot be terminated by an agreement between the parents and daughter shall have a discretion to exercise such rights or not on her attaining majority.		
धारा 13ख – अवयस्क पुत्री का भरण–पोषण तथा पिता की संपत्ति में अंश के दावे का अधिकार माता–पिता के मध्य करार से समाप्त नहीं किया जा सकता तथा पुत्री के पास विवेकाधिकार होगा कि वयस्कता प्राप्त करने पर वह इन अधिकारों का प्रयोग करेगी या नहीं।	**78***	**146**
Section 13 (1) (i) – See Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 13 (1) (i) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125।	**59***	**125**
Section 24 – (i) Factors for consideration for grant of maintenance – Effect of the qualification of the wife and income of the wife's father.		
(ii) Relevant date for the entitlement of maintenance.		
धारा 24 – (i) भरणपोषण प्रदान करने हेतु विचारणीय बिंदु – पत्नी की योग्यता तथा उसके पिता की आय का प्रभाव।		
(ii) भरण–पोषण का हकदार होने के लिए सुसंगत तिथि।	**27**	**58**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 24 – Grant of maintenance to the Muslim wife.		
धारा 24 – मुस्लिम पत्नी को भरणपोषण प्रदान किया जाना।	**28***	**62**
Section 24 – See Section 19 of the Family Courts Act, 1984.		
धारा 24 – देखें कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19।	**292**	**552**
HINDU MINORITY AND GUARDIANSHIP ACT, 1956		
हिन्दू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956		
Section 6 – (i) Custody of minor child.		
(ii) Preferential right of father and relatives of deceased mother.		
धारा 6 – (i) अप्राप्तवय बालक की अभिरक्षा।		
(ii) पिता तथा मृत माता के नातेदारों के अधिमानी अधिकार।	**295**	**560**
Section 6 – See Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955.		
धारा 6 – देखें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13ख।	**26***	**57**
HINDU SUCCESSION ACT, 1956		
हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956		
Section 14 – Property in possession of Hindu woman at the commencement of Act of 1956, when becomes her absolute property?		
धारा 14 – 1956 के अधिनियम के लागू होने के समय हिन्दू महिला के आधिपत्य की संपत्ति – कब उसके पूर्ण स्वामित्व की हो जाती है?	**296**	**562**
Section 30 – A coparcener can dispose of his undivided share in Mitakshara joint family property by Will or any testamentary disposition.		
धारा 30 – कोई सहदायिक, मिताक्षरा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अपने अविभाजित अंश को इच्छापत्र अथवा किसी वसीयती व्ययन द्वारा व्ययनित कर सकता है।	**127**	**215**
IDENTIFICATION OF PRISONERS ACT, 1920		
बन्दी शिनाख्त अधिनियम, 1920		
Sections 4 and 5 – See Sections 302 and 394 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 27 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 4 एवं 5 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 394 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27।	**225**	**429**
INDIAN PENAL CODE, 1860		
भारतीय दण्ड संहिता, 1860		
Sections 34 and 149 – See Sections 216, 386 and 464 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 34 एवं 149 – देखें धाराएं 216, 386 एवं 464 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973।	**116**	**198**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 34, 149 and 302 – (i) Non-applicability of Section 149 is no bar in convicting the accused persons with the aid of Section 34. (ii) Common intention may be developed at the spur of moment on the spot. **धाराएं 34, 149 एवं 302** – (i) धारा 149 की गैर–प्रयोज्यता धारा 34 की सहायता से अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने में कोई रोक नहीं लगाती है। (ii) सामान्य आशय मौके पर क्षणिक उकसावे पर विकसित हो सकता है।	**179**	**301**
Sections 34, 302 and 323 – See Sections 212, 215 and 464 of the Criminal Procedure Code, 1973. **धाराएं 34, 302 एवं 323** – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 212, 215 एवं 464।	**63**	**129**
Sections 34, 302 and 364 – (i) When 'last seen' theory along with other circumstances are established by prosecution, mere denial of his involvement in crime by accused would not suffice but it is duty of the accused to explain these circumstance in his examination. (ii) Death of one of the main co-accused sharing common intention while committing crime would not exonerate the other co-accused from prosecution. **धाराएं 34, 302 एवं 364** – (i) अन्य परिस्थितियों के साथ–साथ अभियोजन पक्ष द्वारा जब 'अंतिम बार साथ देखा जाना' भी स्थापित कर दिया जाए, अभियुक्त द्वारा मात्र अपराध में अपनी भागीदारी से इंकार करना पर्याप्त न होगा बल्कि अभियुक्त का यह कर्तव्य है कि वह परीक्षण में इन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण दे। (ii) अपराध करते समय सामान्य आशय रखने वाले मुख्य सह–अभियुक्त की मृत्यु अन्य सह–अभियुक्त को अभियोजन से मुक्त नहीं करेगी।	**128**	**216**
Sections 53 and 302 – Socio-economic factors particularly ground realities relating to access to justice and remedies to justice which are not easily available to poor and probability of reform or rehabilitation and social reintegration of accused into society must be considered while awarding death sentence. **धाराएं 53 एवं 302** – मृत्यु दण्डादेश पारित करते समय सामाजिक–आर्थिक कारक विशिष्टतः न्याय तक पहुँच से संबंधित वास्तविक आधार व न्यायिक उपचार, जो कि गरीबों को सहज उपलब्ध नहीं हैं एवं अभियुक्त के सुधार या पुनर्वास व समाज से पुनः जुड़ने की संभावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए।	**180***	**302**
Sections 63 and 64 – (i) Set-off of default sentence for non-payment of fine. (ii) Whether default sentences in multiple offences can run concurrently *inter se.* **धाराएं 63 एवं 64** – (i) जुर्माने के असंदाय के लिये व्यतिक्रम के कारावास का मुजरा किया जाना। (ii) क्या कई अपराधों में व्यतिक्रम के कारावास आपस में एक साथ चल सकते हैं?	**29**	**62**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Section 84 – Sentencing – Death sentence awarded to driver of State Transport for causing death of nine people due to denial of permission to change his duty – Plea of insanity not established by accused – Held, accused was under mental strain and stress which resulted into the incident – No criminal antecedents of accused – Accused not menace and threat to harmonious and peaceful co-existence of society – Conduct of accused satisfactory in jail – Possibility of reform cannot be denied – Death sentence modified to life imprisonment.

धारा 84 – दण्डादेश – राज्य परिवहन के चालक को उसके कर्तव्य को परिवर्तित करने से इंकार करने के कारण नौ लोगों की मृत्यु कारित करने के लिये मृत्यु दण्ड दिया गया – अभियुक्त द्वारा पागलपन के बचाव को स्थापित नहीं किया गया – अभिनिर्धारित, अभियुक्त मानसिक तनाव और अवसाद में था जिसके कारण घटना घटी – अभियुक्त का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है – अभियुक्त समाज के सामंजस्यपूर्ण तथा शांतिमय सह–अस्तित्व के लिये खतरा या धमकी नहीं है – जेल में अभियुक्त का आचरण संतोषजनक रहा – सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता – मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। **181*** **302**

Sections 90 and 375 – Distinction between 'rape' and 'consensual sex' with reference to promise of marriage.

धाराएं 90 एवं 375 – विवाह करने के वचन के संदर्भ में 'बलात्संग' तथा 'सहमति से स्थापित संबंध' में भेद। **216** **411**

Sections 107 and 306 – Whether refusal to return ornaments would amount to abetment of suicide?

धाराएं 107 एवं 306 – क्या जेवरात वापस करने से इंकार करना आत्महत्या का दुष्प्रेषण की कोटि में आयेगा? **217*** **416**

Sections 120B, 302 r/w/s 34, 302 r/w/s 114 and 379 r/w/s 34 – See Section 8 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 120ख, 302 सहपठित धारा 34, 302 सहपठित धारा 114 तथा 379 सहपठित धारा 34 – देखें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8। **218*** **417**

Sections 148, 149 and 302 – Appreciation of Evidence:

(i) Appreciation of evidence in case of difference in opinion of two doctors.

(ii) Ocular evidence versus medical evidence.

धाराएं 148, 149 एवं 302 – साक्ष्य का मूल्यांकनः

(i) दो डॉक्टरों के मतों में भिन्नता की दशा में साक्ष्य का मूल्यांकन।

(ii) चक्षुदर्शी साक्ष्य विरूद्ध चिकित्सीय साक्ष्य। **219*** **417**

Section 149 – Constructive liability; determination of.

धारा 149 – आन्वयिक दायित्व का निर्धारण। **297** **564**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 149 – Factors for ascertaining the "common object" of an assembly.		
धारा 149 – किसी जमाव के ''सामान्य उद्देश्य'' को अवधारित करने हेतु कारक।	**220***	**418**
Sections 149, 302 and 304 Part-I – Appreciation of Evidence: (i) Effect of non-explanation of injuries on self by the accused. (ii) Whether proof of an overt act of every member of unlawful assembly is required?		
धाराएं 149, 302 एवं 304 भाग–I – साक्ष्य का मूल्यांकनः (i) अभियुक्त द्वारा स्वतः चोटों का स्पष्टीकरण न देने का प्रभाव। (ii) क्या विधिविरूद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य के प्रत्यक्ष कृत्य का प्रमाण आवश्यक है?	**221**	**418**
Section 188 – Order u/s 188 IPC may relate to act which causes or tends to cause danger to human life and hence section 188 IPC will apply for alleged violation of prohibitory order of the Commissioner, Food and Safety also.		
धारा 188 – धारा 188 भा.दं.सं. के तहत आदेश, मानव जीवन को संकट कारित करने वाले या कारित करने की प्रवृत्ति रखने वाले कार्य से संबंधित हो सकता है तथा अतः धारा 188 भा.दं.सं. आयुक्त, खाद्य एवं सुरक्षा के प्रतिबंधात्मक आदेश के कथित उल्लंघन पर भी लागू होगी।	**76 (ii)***	**144**
Section 193 – Whether Magistrate can take cognizance of an offence u/s 193 IPC on the basis of a private complaint?		
धारा 193 – क्या प्राइवेट परिवाद के आधार पर मजिस्ट्रेट धारा 193 भा.दं.सं. के अपराध का संज्ञान ले सकता है?	**222**	**422**
Sections 193, 195, 211 and 376 – See Sections 195, 391 and 340 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 193, 195, 211 एवं 376 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 195, 391 एवं 340।	**17**	**29**
Sections 279 and 304A – (i) In case of rash and negligent driving even when the driver of the vehicle fled from the scene with his vehicle, circumstance that accused was surrendered by his commandant is sufficient to prove the identity of accused as driver. (ii) Appreciation of evidence in case of rash and negligent driving. (iii) Benefit of probation cannot be granted to the accused, where death is caused due to rash and negligent driving.		
धाराएं 279 एवं 304क – (i) उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के मामले में यद्यपि वाहन का चालक अपने वाहन के साथ घटना स्थल से भाग गया था परंतु परिस्थिति कि अभियुक्त को उसके कमांडेंट द्वारा अभ्यर्पण करा दिया गया, चालक के रूप में अभियुक्त की पहचान साबित करने के लिये पर्याप्त है।		

(ii) उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन।

(iii) अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए जहां कि मृत्यु उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के कारण हुई हो। **182*** **303**

Section 295A – Picturization of folk song through winking does not amount to insult or attempt to insult religion or religious beliefs of class of citizens.

धारा 295क – आँखों के इशारों के जरिये लोकगीत का चित्रण करना नागरिकों के वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान या अपमान करने के प्रयत्न की श्रेणी में नहीं आता है। **183*** **304**

Section 300 – When is culpable homicide amounts to murder under Exception I to Section 300 IPC?

धारा 300 – भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आपराधिक मानव वध कब हत्या है? **223** **427**

Section 300, Exception 4 and Section 304, Part II – Conditions to bring the case within Exception 4 to Section 300.

धारा 300, अपवाद 4 और धारा 304, भाग दो – धारा 300 के अपवाद 4 के तहत प्रकरण लाने हेतु शर्तें। **298** **566**

Sections 301 and 302 – If accused person had intention to kill one person but killed another, they would be punishable for offence of murder under doctrine of transfer of malice.

धाराएं 301 एवं 302 – यदि अभियुक्तगण का किसी एक व्यक्ति की हत्या कारित करने का आशय था किंतु वे किसी अन्य की हत्या कर देते हैं, तो वे द्वेष के अंतरण के सिद्धांत के अंतर्गत हत्या का अपराध करने के लिए दण्डित किए जाने योग्य होंगे। **79*** **146**

Section 302 – An accused cannot be acquitted on the sole ground that the other co-accused have been acquitted.

धारा 302 – कोई अभियुक्त इस एकमेव आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है कि अन्य सह अभियुक्तगण दोषमुक्त कर दिए गए हैं। **130*** **218**

Section 302 – Capital punishment commuted to life imprisonment, when motive of the crime was not on record, accused was young at the time of committing offence, there was absence of extreme brutality and State failed to show that there is no possibility of reform or rehabilitation.

धारा 302 – मृत्यु दण्ड आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, जब अपराध का हेतुक अभिलेख पर नहीं था, अपराध कारित करते समय अभियुक्त युवा था, नितांत पाश्विकता का अभाव था और राज्य यह दर्शित करने में असफल रहा कि सुधार या पुर्नवास की कोई संभावना नहीं है। **68 (iii)* 136**

Section 302 – (i) Death sentence; imposition of – Assessment of aggravating and mitigating circumstances – Law summed up.

(ii) Possibility of reformation is a guiding factor for assessing mitigating circumstances.

(iii) A bifurcated hearing for conviction and sentence is necessary and convict should be provided necessary time to furnish evidence relevant to sentencing and mitigation.

धारा 302 – (i) मृत्यु दण्ड अधिरोपित किया जाना – गंभीरता बढ़ाने वाली एवं कम करने वाली परिस्थितियों का आंकलन – विधि समेकित की गई।

(ii) गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों का आंकलन करने में 'सुधार की संभावना' एक मार्गदर्शक कारक है।

(iii) दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के लिए एक द्विभाजित सुनवाई आवश्यक है तथा दोषी को दण्डादेश एवं गंभीरता कम करने वाली प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समय प्रदान किया जाना चाहिए। **184 304**

Section 302 – Deceased died a homicidal death inside matrimonial home of which accused gave no explanation – No grave and sudden provocation by deceased and accused absconded after incident – Conviction upheld.

धारा 302 – मृतक की मृत्यु वैवाहिक गृह के अंदर हुई जिसका अभियुक्त ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया – मृतक द्वारा कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं और घटना के बाद अभियुक्त फरार हो गया – दोषसिद्धी की पुष्टि की गई। **80 (i) 147**

Section 302 – (i) Effect of Improvements by witness in deposition before Court.

(ii) Effect of omissions in FIR.

(iii) Effect of delay in sending recovered weapon to FSL.

धारा 302 – (i) साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य में सुधार का प्रभाव।

(ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट में लोपों का प्रभाव।

(iii) बरामद हथियार को एफएसएल को भेजने में हुए विलंब का प्रभाव। **30 65**

Section 302 – (i) Evidence cannot be rejected just because it is partisan.

(ii) Facts of recovery cannot be disregarded merely because it was not made before independent witness.

(iii) As regards value of evidence of police officials, there is no such legal proposition that the evidence of police officials unless supported by independent witness is unworthy of acceptance or the evidence of police officials can be outrightly disregarded.

धारा 302 – (i) साक्ष्य केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं की जा सकती है कि वह पक्षपोशी है।

(ii) अभिग्रहण का तथ्य मात्र इस कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष नहीं किया गया था।

(iii) पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य के मूल्य के संबंध में, ऐसी कोई विधिक प्रतिपादना नहीं है कि पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य जब तक कि स्वतंत्र साक्षियों से अनुसमर्थित न हो, स्वीकृति के अयोग्य है अथवा पुलिस अधिकारियों की ऐसी साक्ष्य पूर्णतः अस्वीकार कर देनी चाहिए। **131*** **218**

Section 302 – Medical evidence versus direct evidence in case of murder.

धारा 302 – हत्या के मामले में चिकित्सीय साक्ष्य बनाम प्रत्यक्ष साक्ष्य। **129*** **217**

Section 302 – See Sections 3 and 106 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 106। **23** **50**

Section 302 – See Section 32 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32। **132** **219**

Section 302 – See Section 32 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32। **299** **569**

Section 302 – See Section 106 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106। **300** **571**

Section 302 – See Section 118 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118। **301** **573**

Sections 302 and 120B – Essentials of criminal conspiracy to commit murder.

धाराएं 302 एवं 120ख – हत्या कारित करने हेतु आपराधिक षड़यंत्र के आवश्यक तत्व। **81 (i)*** **148**

Sections 302 and 201 – See Sections 3, 8, 25 and 27 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 302 एवं 201 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8, 25 एवं 27। **22** **44**

Sections 302 and 304 Part II – (i) Murder – Third clause of Section 300 explained.
(ii) Distinction between 'murder' and 'culpable homicide' explained.

धाराएं 302 एवं 304 भाग दो – (i) हत्या – धारा 300 के तृतीय खण्ड की व्याख्या की गई। (ii) 'हत्या' एवं 'आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है', में विभेद समझाया गया। **185** **307**

Sections 302 and 304 Part II – Section 302 IPC is not ruled out because of infliction of single blow when intention to cause death is clearly portrayed by circumstances.

धाराएं 302 एवं 304 भाग 2 – धारा 302 भा.दं.सं. को एकल प्रहार के आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता है जब परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से मृत्यु कारित करने का आशय दर्शित हो। **186** **309**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 302, 307, 364, 380 and 201 – Death sentence – Appreciation of aggravating circumstances for deciding "rarest of rare case".		
धाराएं 302, 307, 364, 380 एवं 201 – मृत्यु दण्ड – ''विरल से विरलतम मामला'' विनिश्चित करने हेतु अनुबद्धकारी परिस्थितियों का मूल्यांकन।	**226***	**437**
Sections 302, 376 (2)(f) and 201 – See Section 366 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 302, 376 (2)(च) एवं 201 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366।	**211**	**398**
Sections 302 and 326A – Death sentence – Previous conviction is not a special reason to bring the case in the category of the rarest of rare cases.		
धाराएं 302 एवं 326क – मृत्यु दण्ड – पूर्व दोषसिद्धि मामले को विरल से विरलतम की श्रेणी में लाने का कोई विशेष कारण नहीं है।	**224**	**427**
Sections 302 and 394 – Effect of delay in arrest of accused over the case of prosecution. Effect of recovery based on involuntary statements of the accused.		
धाराएं 302 एवं 394 – अभियुक्त की गिरफ्तारी में विलंब का अभियोजन के मामले पर प्रभाव। अभियुक्त के अस्वैच्छिक कथनों पर आधारित बरामदगी का प्रभाव।	**225 (ii) & (iii)**	**429**
Sections 302 and 498A – Reliability of dying declaration in case of dowry death.		
धाराएं 302 एवं 498क – दहेज मृत्य के मामले में मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता।	**302**	**575**
Section 304 – See Sections 2(33) and 15 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.		
धारा 304 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराएं 2 (33) एवं 15।	**311**	**600**
Section 304-A – Sentencing policy in relation to offences u/s 304-A.		
धारा 304–क – धारा 304क से संबंधित अपराधों में दण्ड नीति।	**227***	**437**
Section 304-B – See Section 113-B of the Evidence Act, 1872.		
धारा 304–ख – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113–ख।	**24**	**53**
Section 304-B – See Section 113-B of the Evidence Act, 1872.		
धारा 304–ख – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113–ख।	**82***	**150**
Section 306 – Accused was demanding his own lent money back from the deceased – No evidence that the accused was demanding an additional amount even after repayment of the entire loan amount by deceased – It cannot be said that accused abetted the deceased to commit suicide.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 306 – अभियुक्त स्वयं द्वारा दी गई उधार राशि मृतक से वापस मांग रहा था – ऐसी कोई साक्ष्य नहीं कि अभियुक्त मृतक द्वारा संपूर्ण ऋण राशि अदा कर देने के बाद भी अतिरिक्त राशि की मांग कर रहा था – यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया।	**83**	**150**
Section 306 – Alleged act of insulting deceased by using abusive language by accused will, by itself, not constitute abetment of suicide – There should be evidence capable of suggesting that accused intended by such act to instigate deceased to commit suicide.		
धारा 306 – अभियुक्त द्वारा अपमानजनक भाषा का उपयोग कर मृतक को अपमानित करने का कथित कृत्य, स्वमेव, आत्महत्या का दुष्प्रेरण गठित नहीं करेगा – ऐसा संकेत करने में समर्थ साक्ष्य होनी चाहिए कि अभियुक्त ऐसे कार्य द्वारा मृतक को आत्महत्या कारित करने को उकसाने को आशयित था।	**84***	**158**
Section 306 – In abetment to commit suicide, abettor must have a positive role in facilitating commission of suicide, there must be proximity between act of abettor and suicide committed by deceased and mere single incident is not sufficient to hold an abettor responsible for instigating deceased to commit suicide.		
धारा 306 – आत्महत्या के दुष्प्रेरण में, आत्महत्या को सुकर बनाने में दुष्प्रेरक की सकारात्मक भूमिका अवश्य होनी चाहिये, मृतक द्वारा आत्महत्या कारित करने एवं दुष्प्रेरक के कृत्य के मध्य सामीप्य होना चाहिये तथा एक मात्र घटना दुष्प्रेरक को मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने हेतु दायी ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं है।	**187***	**310**
Section 307 – Causing fracture of nasal bone and injuries upon nose of complainant does not come within the purview of intention of accused to cause death u/s 307.		
धारा 307 – परिवादी की नाक की अस्थि भंग एवं नाक पर चोट कारित करना अभियुक्त द्वारा धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मृत्यु कारित करने के आशय की परिधि में नहीं आता है।	**188***	**311**
Section 307 – Essentials of attempt to murder.		
धारा 307 – हत्या के प्रयास के आवश्यक तत्व।	**228**	**438**
Section 307 – Proof of grievous or life-threatening hurt is not a *sine qua non* for the offence punishable u/s. 307 but intention of the accused is important which can be ascertained from the actual injury and surrounding circumstances including nature of weapon used and severity of blows inflicted.		
धारा 307 – घोर या जीवन संकटापित करने वाली उपहति का सबूत धारा 307 के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु अनिवार्य नहीं है किंतु अभियुक्त का आशय महत्वपूर्ण है जिसे वास्तविक क्षति और प्रयुक्त आयुध व कारित प्रहारों की गंभीरता सहित प्रतिवेशी परिस्थितियों से अभिनिर्धारित किया जा सकता है।	**133**	**222**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 320 and 326 – (i) Whether acid is a corrosive substance for the purpose of Section 326 IPC? (ii) Hurt caused by pouring acid on the body of victim; when becomes grievous? **धाराएं 320 एवं 326** – (i) क्या धारा 326 भा.द.सं. के प्रयोजन के लिये अम्ल एक संक्षारक पदार्थ है? (i) पीड़ित के शरीर पर अम्ल फेंककर कारित उपहति कब घोर उपहति होती है?	**303**	**579**
Section 324 – Appreciation of evidence: Effect of absence of motive in offence punishable u/s 24 of the Indian Penal Code, 1860 **धारा 324** – साक्ष्य का मूल्यांकन : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 324 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संदर्भ में अपराध के उद्देश्य/हेतुक के अभाव का प्रभाव।	**304**	**580**
Sections 325 and 326 – Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapon – Wooden stick used to cause grievous injury – In absence of material to show that stick is a dangerous weapon, offence would fall u/s 325 IPC and not u/s 326 IPC. **धाराएं 325 एवं 326** – घातक आयुध द्वारा स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करना – गंभीर उपहति कारित करने में डंडे का उपयोग – डंडे को घातक आयुध दर्शित करने की सामग्री के अभाव में, अपराध धारा 325 भा.दं.सं. के अंतर्गत आएगा न कि धारा 326 भा.दं.सं. के अधीन।	**73 (ii)***	**141**
Sections 326A and 326B – (i) Section 326A of IPC is attracted in a case of acid attack in which simple injury is caused. (ii) Difference between Section 326A and Section 326B is only the presence of injury – Presence of actual injury attracts Section 326A whereas the mere act of throwing acid or attempting to throw or administer or attempting to use any other means with intention of causing injury attracts Section 326B. **धाराएं 326क एवं 326ख** – (i) अम्ल हमले के मामले में, जिसमें साधारण उपहति कारित होती है, उसमें भा.दं.सं. की धारा 326क आकर्षित होती है। (ii) धारा 326क और 326ख में भेद, मात्र उपहति की उपस्थिति है – वास्तविक उपहति की उपस्थिति धारा 326क को आकर्षित करती है जबकि उपहति कारित करने के आशय से अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयास करना या देना या अन्य किसी माध्यम से उपयोग करने के प्रयत्न का कार्य धारा 326ख को आकर्षित करता है।	**85***	**159**
Section 354 – See Section 134 of the Evidence Act, 1872. **धारा 354** – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 131।	**134**	**224**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 364A and 302 – (i) Evidentiary value of related witness. (ii) Establishment of identity through call detail record (CDR). (iii) Effect of delay in FIR. (iv) Evidentiary value of electronic records. **धाराएं 364क एवं 302** – (i) संबंधी साक्षी की साक्ष्य का मूल्य। (ii) कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से पहचान स्थापित करना। (iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब का प्रभाव। (iv) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का साक्ष्यिक मूल्य।	**189**	**311**
Section 376 – (i) Appreciation of sole testimony of prosecutrix. (ii) Absence of injury or non-rupture of hymen. (iii) Approach of Courts as to offences against women. **धारा 376** – (i) अभियोक्त्री की एकल साक्ष्य का मूल्यांकन। (ii) उपहति की अनुपस्थिति अथवा योनिच्छद का विदीर्ण न होना। (iii) महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के संबंध में न्यायालयों का दृष्टिकोण।	**305**	**580**
Section 376 – Factors for consideration while imposing punishment for offence of rape. **धारा 376** – बलात्संग के अपराधों में दण्ड अधिरोपित करते समय विचार योग्य कारक।	**229 (ii)**	**440**
Section 376 – (i) In rape cases, distinction between 'false promise of marriage' and 'mere breach of promise to marry' explained. (ii) Rape or consensual sex – Accused, prosecutrix and their families were known to each other – Accused was set to marry another girl but continued to promise to marry the prosecutrix – Accused called the prosecutrix on the fateful day, received her on railway station and took to his residence – Prosecutrix initially refused but accused allured her with promise to marry and had physical relation with her – Later, both the families negotiated – Accused again expressed his willingness to marry prosecutrix and social function was also scheduled twice – On scheduled date, accused married the other girl in Arya Samaj – That other girl deposed that negotiations of her marriage with accused were going on since one year – Held, accused had no intention to marry prosecutrix since inception and it is a clear case of cheating and deception. **धारा 376** – (i) बलात्कार के मामलों में 'विवाह का मिथ्या वचन' एवं 'मात्र विवाह करने के वचन का भंग' में भेद समझाया गया। (ii) बलात्कार या सहमतिपूर्ण यौन संबंध – अभियुक्त, अभियोक्त्री और उनके परिवार एक–दूसरे से परिचित थे – अभियुक्त का विवाह किसी अन्य लड़की से तय था फिर भी वह अभियोक्त्री से विवाह करने का वादा करता रहा – अभियुक्त ने प्रश्नगत दिन अभियोक्त्री को बुलाया, उसे रेल्वे स्टेशन से लिया और अपने आवास पर ले गया – अभियोक्त्री ने शुरू में इन्कार किया परन्तु		

अभियुक्त ने विवाह करने का वचन कर उसे फुसलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए – बाद में दोनों परिवारों ने बातचीत की – अभियुक्त ने पुनः अभियोक्त्री से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की और दो बार सामाजिक समारोह भी निर्धारित किए गए – निर्धारित तिथि पर, अभियुक्त ने आर्य समाज में दूसरी लड़की से विवाह कर लिया – उस दूसरी लड़की ने बताया कि अभियुक्त के साथ उसके विवाह की बातचीत एक वर्ष से चल रही थी – अभिनिर्धारित, अभियुक्त का प्रारंभ से ही अभियोक्त्री से विवाह करने का कोई आशय नहीं था और यह छल एवं प्रवंचना का एक स्पष्ट मामला है। **190 315**

Section 376 – See Section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973

धारा 376 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439। **289* 548**

Sections 376 (A), 302 and 201 – When death sentence can be imposed as an exception?

धाराएं 376(क), 302 एवं 201 – मृत्यु दण्ड कब अपवाद के रूप में अधिरोपित किया जा सकता है? **231 449**

Section 376 (2) – (i) No previous criminal antecedent, tender age (19 years) during commission of crime, good jail conduct are mitigating circumstances which should be considered while awarding death sentence.

(ii) Death sentence – Accused convicted u/s 376 (2) IPC r/w/s 5 r/w/s 6 POCSO Act and Section 302 IPC for committing rape and murder of 7½ year old girl – He was awarded death sentence by trial Court which was affirmed by the High Court – Considering the above mitigating circumstances, his death sentence was commuted to life imprisonment.

धारा 376 (2) – (i) किसी पूर्व आपराधिक इतिहास का अभाव, अपराध के समय अल्प आयु (19 वर्ष), कारावास में अच्छा आचरण गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियां हैं जिन्हें मृत्यु दण्ड देते समय विचार में लेना चाहिए।

(ii) मृत्यु दण्ड – अभियुक्त भा.दं.सं. की धारा 376 (2) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 सहपठित धारा 6 और भा.दं.सं. की धारा 302 के अधीन एक 7½ वर्षीय बालिका के बलात्कार और हत्या के आरोप में दोषी पाया गया – विचारण न्यायालय द्वारा उसे मृत्यु दण्ड से दंडित किया गया जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई – गंभीरता कम करने वाली उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में, उसके मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। **191 317**

Section 376 (2) (g) (prior to amendment of 2013) – See Sections 228 and 464 of the Criminal Procedure Code, 1973

धारा 376 (2) (छ) (2013 के संशोधन के पूर्व) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 228 एवं 464। **283 538**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 376 (2) (g) – When a suicide note can be treated as dying declaration?		
धारा 376 (2)(छ) – कब किसी आत्महत्या लेख को मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है?	**230 (i)**	**443**
Section 396 – See Sections 3, 9 and 27 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 396 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 9 एवं 27।	**135**	**226**
Sections 405, 406, 415 and 420 – (i) Criminal breach of trust – Loan transaction – Held, law recognizes difference between 'simple payment' and 'entrustment of money' – Advancement of loan is not entrustment of money – There cannot be a criminal breach of trust without clear case of entrustment.		
(ii) Distinction between 'cheating' and 'mere breach of contract' explained.		
धाराएं 405, 406, 415 एवं 420 – (i) आपराधिक न्यासभंग – ऋण संव्यवहार – अभिनिर्धारित, विधि 'सामान्य भुगतान' और 'धन के न्यस्तिकरण' के मध्य विभेद करती है – ऋण दिया जाना धन का न्यस्तिकरण नहीं है – न्यस्तिकरण के स्पष्ट मामले के बिना आपराधिक न्यासभंग नहीं हो सकता है।		
(ii) 'छल' एवं 'संविदा का उल्लंघन' में भेद समझाया गया।	**192**	**318**
Section 409 – See Section 300 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 409 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300।	**96***	**170**
Sections 420, 465, 467, 468, 471, 477A and 120B – See Sections 190 (1) (b) and 397 of Criminal Procedure Code 1973.		
धाराएं 420, 465, 467, 468, 471, 477क एवं 120ख – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 190 (1) (ख) एवं 397।	**207**	**393**
Sections 420 and 468 – (i) Territorial jurisdiction for the offence of cheating.		
(ii) Effect of not impleading company as accused.		
धाराएं 420 एवं 468 – (i) छल के अपराध हेतु क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार।		
(ii) कंपनी को अभियुक्त न बनाये जाने का प्रभाव।	**31**	**68**
Section 448 – See Section 456 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 448 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 456।	**136**	**230**
Section 497 – Constitutionality of Section 497 of IPC.		
धारा 497 – भा.दं.सं. की धारा 497 की संवैधानिकता।	**32**	**72**
Section 498-A – In cases of matrimonial offence with respect to demand of dowry, when part of crime is committed within the territorial jurisdiction of the Court where wife's paternal home is situated, then such Court has territorial jurisdiction.		
धारा 498–क – दहेज की मांग के संबंध में वैवाहिक अपराध के मामलों में, यदि अपराध का कोई भाग उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर घटित होता है, जहां पत्नी का पैतृक निवास है, तो ऐसे न्यायालय को विचारण की क्षेत्रीय अधिकारिता हाती है।	**193**	**320**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 498-A – See Section 177 and 179 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 498–क – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 177 एवं 179।	**306**	**584**
Section 498-A – (i) Whether decree of divorce between parties, wipe out any criminal offence committed under IPC and PWDV Act? (ii) Whether complaint u/s 498A should be filed only by woman who is subjected to cruelty?		
धारा 498–क – (i) क्या पक्षकारों के मध्य विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति भारतीय दण्ड संहिता तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कारित किसी दाण्डिक अपराध को समाप्त कर देती है? (ii) क्या धारा 498क के अंतर्गत परिवाद मात्र क्रूरता के अधीन महिला द्वारा ही संस्थित किया जाना चाहिए?	**307**	**587**
Section 499 – Essential elements of offence of defamation.		
धारा 499 – मानहानि के अपराध के आवश्यक तत्व।	**308**	**588**
Section 499 – Inaccurate and selective reporting of Court proceedings with version of only one side with false caption is not protected under Exception 4 of Section 499 of the Code.		
धारा 499 – न्यायालय की कार्यवाहियों की त्रुटिपूर्ण एवं चुनिंदा रिपोर्टिंग, झूठे अनुशीर्षक सहित केवल एक पक्ष के विवरण के साथ, संहिता की धारा 499 के अपवाद 4 के तहत संरक्षित नहीं है।	**86***	**160**
Sections 504 and 506 – Essential ingredients of offence of intentional insult to provebe breach of peace enunciated. Essential ingredients of offence of criminal intimidation enunciated.		
धाराएं 504 एवं 506 – लोकशांति भंग कराने के आशय से साशय अपमान के अपराध के आवश्यक तत्व प्रतिपादित।		
आपराधिक अभित्रास के अपराध के आवश्यक तत्व प्रतिपादित किए गए।	**280 (iii) & (iv)**	**532**
INDIAN POST OFFICE RULES, 1933		
भारतीय डाक घर नियम, 1933		
Rule 195 – See Sections 147 and 149 of the Motor Vehicles Act, 1988.		
नियम 195 – देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धाराएं 147 एवं 149।	**241**	**468**
INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000		
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000		
Section 66-D – See Sections 420 and 468 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 66–घ – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 420 एवं 468।	**31**	**68**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
INSURANCE ACT, 1938		
बीमा अधिनियम, 1938		
Section 64VB – See Section 147 of the Motor Vehicles Act, 1988.		
धारा 64VB – देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 147।	**89**	**162**
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS:		
बौद्धिक सम्पदा अधिकार:		
– See Section 29 of the Trade Marks Act, 1999.		
– देखें व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 29।	**33***	**74**
INTERPRETATION OF STATUTES:		
संविधियों का निवार्चन:		
– The word 'may' used in Section 148, Negotiable Instruments Act, 1881 should be construed as 'shall' – However, in exceptional cases, the appellate Court is empowered not to direct to deposit the same but special reasons shall be recorded for it.		
– परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 148 में प्रयुक्त शब्द 'may (सकता है)' का अर्थान्वयन 'shall (करेगा)' के रूप में किया जाना चाहिए – हालांकि, आपवादिक मामलों में अपील न्यायालय निक्षेप (जमा) करने का निर्देश न देने के लिए सशक्त है परंतु इसके लिए विशेष कारण अभिलिखित करने होंगे।	**321 (ii)**	**615**
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2000		
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000		
Sections 2, 3 and 4 – (i) Whether Principal Magistrate, while sitting alone, can finally decide a case pending before the Juvenile Justice Board?		
(ii) Effect of disposal of case in contravention of the provisions of the Act.		
(iii) Effect of decision by a Court having no jurisdiction.		
धाराएं 2, 3 एवं 4 – (i) क्या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित मामले को, प्रधान मजिस्ट्रेट, जब वह अकेले बैठा है, अंतिम रूप से निराकृत कर सकता है?		
(ii) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में मामले के निराकरण का प्रभाव।		
(iii) अधिकारिता न रखने वाले न्यायालय द्वारा विनिश्चय का प्रभाव।	**309**	**589**
Section 7A – Plea of juvenility can be raised at any stage before any Court by an accused, including Supreme Court, even after final disposal of the case.		
धारा 7क – अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रक्रम पर एवं किसी भी न्यायालय के समक्ष, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी शामिल है, यहां तक कि प्रकरण के अंतिम निपटारे के बाद भी, किशोर होने का अभिवाक् लिया जा सकता है।	**194***	**322**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2001

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2001

Rule 22 – Determination of plea of juvenility.

नियम 22 – किशोर होने के अभिवाक् का निर्धारण। **232 451**

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) AMENDMENT ACT, 2006

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006

Section 7-A – See Rule 22 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2001.

धारा 7–क – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2001 का नियम 22। **232 451**

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2007

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007

Rule 12 – See Section 7A of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

नियम 12 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7क। **194* 322**

Rule 12 – See Rule 22 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2001.

नियम 12 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2001 के नियम 22। **232 451**

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2015

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

Sections 2, 4 and 7 – See Sections 2, 3 and 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

धाराएं 2, 4 एवं 7 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धाराएं 2, 3 एवं 4। **309 589**

Sections 2, 15, 19, 49 and 107 – (i) Precautions at the stage of preliminary assessment into heinous offences by Board.

(ii) Criminal investigation as to child alleged to be in conflict with law.

(iii) Effect of sending a juvenile to prison.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 2, 15, 19, 49 एवं 107 – (i) बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण के स्तर पर पूर्वावधानियां। (ii) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक के संबंध में आपराधिक अन्वेषण। (iii) किशोर को कारागार प्रेषित करने का प्रभाव।	**310**	**593**
Sections 2(33) and 15 – (i) Definition of heinous offence. (ii) Whether offence punishable u/s 304 IPC comes within the ambit of heinous offence? **धाराएं 2 (33) एवं 15** – (i) जघन्य अपराध की परिभाषा। (ii) क्या धारा 304 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(33) में यथा परिभाषित जघन्य अपराध की परिधि में आता है?	**311**	**600**
Sections 4 and 12 – Whether child in conflict with law is entitled to move application for anticipatory bail? **धाराएं 4 एवं 12** – क्या विधि का उल्लंघन करने वाला बालक अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का पात्र है?	**233**	**453**
Sections 15 and 25 – Requirement of preliminary assessment for an offence committed prior to commencement of the Act. **धाराएं 15 एवं 25** – अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व कारित अपराध हेतु प्रारंभिक निर्धारण की आवश्यकता।	**234**	**456**
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2016 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016**		
Rules 10A and 86 – See Sections 2, 15, 19, 49 and 107 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 **नियम 10 क एवं 86** – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराएं 2, 15, 19, 49 एवं 107।	**310**	**593**
LAND ACQUISITION ACT, 1894 **भू–अर्जन अधिनियम, 1894**		
Sections 4, 6, 11 and 16 – Suit for declaration of title and permanent injunction is not maintainable against the acquisition proceedings under the Act and only remedy available is to either challenge the acquisition proceedings as being against the provisions of the Act or to claim compensation payable under the Act. **धाराएं 4, 6, 11 एवं 16** – अधिनियम के अधीन अर्जन कार्यवाहियों के विरूद्ध स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रचलनीय नहीं है तथा एकमात्र उपचार या तो अर्जन कार्यवाहियों को अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध होने से चुनौती देना या अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर का दावा करना है।	**87 (i)***	**161**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 12(2) and 18 – Period of limitation for reference against the award for enhancement of compensation u/s 18.		
धाराएं 12(2) एवं 18 – धारा 18 के तहत क्षतिपूर्ति में वृद्धि हेतु पंचाट के विरूद्ध रेफरेंस हेतु परिसीमा की अवधि।	**235**	**456**
Sections 16 and 48 – (i) Manner in which possession of acquired land is required to be taken under the Act. (ii) Power of State to withdraw from acquisition of land.		
धाराएं 16 एवं 48 – (i) अधिनियम के अधीन किस रीति से अर्जित भूमि का आधिपत्य लिया जाना अपेक्षित है। (ii) भूमि का अर्जन प्रत्याहरित करने की राज्य की शक्ति।	**34**	**75**
Sections 18 and 23 – (i) Determination of compensation by 'Comparison method'. (ii) Amended provisions of Section 23 (1A) and 23 (2) would apply to determine the amount of interest and solatium, where land was acquired before amendment.		
धाराएं 18 एवं 23 – (i) 'तुलना विधि' द्वारा प्रतिकर का निर्धारण। (ii) धारा 23 (1ए) और 23 (2) के संशोधित प्रावधान ब्याज और तोषण की राशि निर्धारित करने के लिए लागू होंगे, जहां संशोधन से पूर्व ही भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका हो।	**195**	**322**
Sections 28A and 53 – Impleadment of legal heirs in execution proceedings for recovery of compensation.		
धाराएं 28क एवं 53 – प्रतिकर की वसूली हेतु निष्पादन कार्यवाहियों में विधिक उत्तराधिकारियों का संयोजन।	**236**	**458**
LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT, 1987 **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987**		
Section 21 – See Section 96 and Order 23 Rule 3 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 21 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 एवं आदेश 23 नियम 3।	**2***	**6**
LIMITATION ACT, 1963 **परिसीमा अधिनियम, 1963**		
Section 5 – Condonation of delay.		
धारा 5 – विलंब का उपमर्षण।	**264**	**507**
Section 5 – Delay of 1942 days (i.e. 4 years 6 months) in filing appeal for the reason that the lawyer did not take timely steps to file an appeal is not sufficient cause to condone the delay because if a lawyer is not taking interest in attending Court on time, then party must take steps to engage another lawyer to ensure that appeal is filed on time.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 5 – अधिवक्ता द्वारा अपील संस्थित करने के लिये समय पर आवश्यक उपाय न किये जाने के कारण अपील संस्थित करने में 1942 दिवस (अर्थात् 4 वर्ष एवं 6 माह) का विलंब, विलंब क्षमा हेतु पर्याप्त कारण नहीं है क्योंकि यदि कोई अधिवक्ता समय पर न्यायालय में उपस्थित होने में रूचि नहीं ले रहा है तो पक्षकार को किसी अन्य अधिवक्ता को नियुक्त करने का उपाय करना चाहिए जिससे अपील समय पर संस्थित किया जाना सुनिश्चित हो सके।	**196**	**324**
Section 5 – Relevancy of previous conduct of applicant while condoning the delay.		
धारा 5 – विलंब क्षमा करने के दौरान आवेदक के पूर्वाचरण की सुसंगतता।	**35***	**81**
Section 5 – See Sections 421 (23) and 433 of the Companies Act, 2013.		
धारा 5 – देखें कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 421 (23) एवं 433।	**10**	**18**
Sections 5 and 14 – (i) Courts should adopt liberal view and justice oriented approach while deciding sufficient cause for condonation of delay.		
(ii) Factors constituting sufficient cause explained.		
(iii) An application u/s 5 of the Limitation Act cannot be rejected on the ground that applicant was not diligent while making application for certified copy of the order impugned and was not receiving the same when asked to receive.		
धाराएं 5 एवं 14 – (i) विलंब क्षमा किये जाने हेतु न्यायालयों को पर्याप्त कारण तय करते समय उदार मत एवं न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।		
(ii) पर्याप्त कारण बनाने वाले घटक समझाये गये।		
(iii) परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि आवेदक आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करते समय तत्पर नहीं था और प्रति प्राप्त करने के लिए कहने पर भी उसे प्राप्त नहीं कर रहा था।	**197**	**325**
Sections 9, 17 and 29 – (i) Overriding effect of limitation period prescribed under Arbitration Act, 1996.		
(ii) Period for challenging award – Condonation of delay.		
(iii) Issues relating to pleading of exclusion of delay caused by fraud.		
धाराएं 9, 17 एवं 29 – (i) माध्यस्थम अधिनियम, 1996 के अधीन विहित परिसीमा अवधि का अध्यारोही प्रभाव।		
(ii) पंचाट को आक्षेपित करने हेतु परिसीमा – विलंब क्षमा किया जाना।		
(iii) कपट के द्वारा कारित विलंब के अपवर्जन के अभिवचन से संबंधित बिंदु।	**36**	**81**
Section 27 – See Section 54 of the Transfer of Property Act, 1882.		
धारा 27 – देखें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54।	**48***	**109**

Section 27 and Articles 64 and 65 – Limitation for suit for possession by Reversioner. Effect of adverse possession.

धारा 27 एवं अनुच्छेद 64 एवं 65 – आधिपत्य हेतु उत्तरभोगी द्वारा प्रस्तुत वाद की परिसीमा। विरोधी अधिपत्य का प्रभाव। **294 (iii) & (iv) 554**

Articles 58 and 65 – Limitation for suit for possession based on title.

अनुच्छेद 58 एवं 65 – स्वत्व पर आधारित आधिपत्य हेतु वाद के लिए परिसीमा। **312 601**

Section 64 – (i) Distinction between 'suit based on possessory title, and 'suit based on proprietary title' explained.

(ii) Settled possession or effective possession of person without title, entitles such person to protect his possession as if he were true owner.

(iii) For proof of possessory title, person who asserts possessory title over particular property will have to show that he is under settled or established possession of said property and merely stray or intermittent acts of trespass do not give such right against true owner.

(iv) Burden of proof is on the plaintiff to prove his case to the satisfaction of the Court and he cannot rely on weaknesses of the defendant.

धारा 64 – (i) आधिपत्य विषयक स्वत्व पर आधारित वाद तथा स्वामित्व आधारित स्वत्व पर आधारित वाद में भेद समझाया गया।

(ii) बिना स्वत्व के व्यक्ति का सुस्थापित या प्रभावी आधिपत्य ऐसे व्यक्ति को अपने आधिपत्य की संरक्षा हेतु इस प्रकार अधिकृत करता है जैसे कि वह वास्तविक स्वामी हो।

(iii) आधिपत्य विषयक स्वत्व के सबूत हेतु कोई व्यक्ति जो किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर आधिपत्य विषयक स्वत्व का दावा करता है, उसे यह दर्शित करना होगा कि वह उस सम्पत्ति के सुस्थापित आधिपत्य में है तथा मात्र अतिचार के एकल या अंतरायिक (बीच–बीच के) कार्य वास्तविक स्वामी के विरूद्ध ऐसा अधिकार नहीं देते हैं।

(iv) सबूत का भार वादी पर होता है कि वह अपना मामला न्यायालय के समाधान पर साबित करे और वह प्रतिवादी की दुर्बलताओं पर भरोसा नहीं कर सकता है। **137 231**

Articles 64 and 65 – (i) Pleading of 'acquisition of title through predecessor' as well as 'acquisition of title by adverse possession' being inconsistent, are impermissible.

(ii) Plaintiff cannot claim relief on the basis of adverse possession – It is merely a defence to be used by defendant as shield.

अनुच्छेद 64 एवं 65 – (i) 'पूर्वजों के माध्यम से स्वामित्व के अर्जन' के साथ 'प्रतिकूल आधिपत्य द्वारा स्वामित्व के अर्जन' का अभिवाक् असंगत होने से अनुज्ञेय नहीं है।

(ii) वादी विरोधी आधिपत्य के आधार पर अनुतोष की मांग नहीं कर सकता – यह प्रतिवादी द्वारा ढाल के रूप में लिया जाने वाला मात्र एक बचाव है। **198* 326**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Article 65 – Approach of Court on question of limitation.		
अनुच्छेद 65 – परिसीमा के बिन्दु पर न्यायालय का दृष्टिकोण।	**37**	**86**
Article 109 – See Order 2 Rule 2 of the Civil Procedure Code, 1908.		
अनुच्छेद 109 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 2 नियम 2।	**267**	**514**
MENTAL HEALTH ACT, 1987		
मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987		
Sections 50, 51, 52, 53 and 54 – (i) Whether separate applications are required for declaration of a person to be mentally ill and for appointment of guardian or manager for him?		
(ii) Whether an application u/s 50 of the Mental Health Act can be rejected on the ground that details of property have not been disclosed?		
धाराएं 50, 51, 52, 53 एवं 54 – (i) क्या किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने एवं उसके लिए अभिभावक या प्रबंधक की नियुक्ति के लिए पृथक–पृथक आवेदन आवश्यक हैं?		
(ii) क्या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 50 के अधीन प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि संपत्ति का विवरण नहीं दिया गया है?	**313***	**604**
MOHAMMEDAN LAW:		
मुस्लिम विधिः		
– Conditions for making valid and complete oral gift under Muslim Law.		
– मुस्लिम विधि में वैध और पूर्ण मौखिक दान करने की शर्तें।	**97 (iii)**	**171**
– (i) Validity of marriage between Muslim man and Hindu woman.		
(ii) Whether child born out of *fasid* (irregular) marriage is entitled to claim a share in his father's property?		
– (i) मुस्लिम पुरूष तथा हिंदू महिला के मध्य विवाह की वैधता।		
(ii) क्या ***फासीद*** (अनियमित) विवाह से पैदा होने वाली संतान को अपने पिता की संपत्ति में अंश का दावा करने का हकदार है?	**237**	**462**
MONEY LENDERS ACT, 1934 (M.P.)		
साहूकार अधिनियम, 1934 (म.प्र.)		
Sections 11-B and 11-H – Whether a non-registered money lending firm can sue for recovery of loan?		
धाराएं 11–ख एवं 11–ज – क्या एक गैर पंजीकृत साहूकार फर्म ऋण की वसूली हेतु दावा प्रस्तुत कर सकती है?	**238**	**462**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
MOTOR VEHICLES ACT, 1988		
मोटर यान अधिनियम, 1988		
Section 50 r/w/s 2 (30) – Upon transfer of vehicle, the person in whose name the vehicle stands registered in RTO records, is treated to be the registered owner, even if possession handed over to transferee after receiving consideration and he is liable to pay compensation as long his name continues in RTO records.		
धारा 50 सहपठित धारा 2 (30) – वाहन के अंतरण में जिस व्यक्ति के नाम पर मोटर यान, आरटीओ अभिलेखों में पंजीकृत होता है, उसे स्वामी माना जाता है, चाहे प्रतिफल प्राप्त करने के बाद अंतरिति को आधिपत्य दे दिया गया हो और वह क्षतिपूर्ति अदा करने हेतु दायी होगा जब तक उसका नाम आरटीओ अभिलेखों में बना रहता है।	**88***	**162**
Sections 134, 166 and 187 – (i) Standard of proof for Motor Accident Claim Cases must be of preponderance of probability and not strict standard of proof beyond all reasonable doubt as followed in criminal cases.		
(ii) If presence of a witness at the time and place of the accident proved, the entire version of his evidence cannot be discarded only on the ground of his inability to identify the age of the pillion rider.		
(iii) Non-examination of best witness as pillion rider would not be fatal in accident claim cases.		
(iv) Evaluation of evidence in claim cases explained.		
(v) In determination of compensation, objection about deduction of income tax from calculated income is not sustainable in view of the law laid down in ***National Insurance Company Limited v. Pranay Sethi and others, (2017) 16 SCC 680***.		
धाराएं 134, 166 एवं 187 – (i) वाहन दुर्घटना मामलों के लिए सबूत का स्तर अधिसंभाव्यता की प्रबलता का होना चाहिए और न कि सभी संदेह से परे होने का ऐसा कठोर स्तर जिसे आपराधिक मामलों में अनुसरित किया जाता है।		
(ii) यदि दुर्घटना के समय और स्थान पर साक्षी की उपस्थिति साबित हो जाती है, तो पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति की आयु बताने में अक्षमता मात्र के आधार पर उसकी सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।		
(iii) सर्वोत्तम साक्षी यथा पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति की परीक्षा न कराया जाना दुर्घटना दावा प्रकरण के लिए घातक नहीं होगा।		
(iv) दावा प्रकरणों में साक्ष्य का मूल्यांकन समझाया गया।		
(v) प्रतिकर का निर्धारण करते समय संगणित आय से आयकर विकलित करने के संबंध में आपत्ति ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी तथा अन्य (2017) 16 एससीसी 680,*** में मामले में प्रतिपादित विधि के आलोक में पोषणीय नहीं है।	**138**	**233**

Sections 140 and 168 – (i) In collision of car behind a running truck, distance of 10-15 feet between the two vehicles held not to be a safe distance and driver of car held to be rash and negligent in driving.

(ii) Question of contributory negligence arises only when both the parties were rash and negligent while driving.

(iii) Liability of owner u/s 140 is regardless of the fact that vehicle was not driven rashly and negligently.

धाराएं 140 एवं 168 – (i) एक चलते हुए ट्रक के पीछे कार के टकराने में, दोनों वाहनों के बीच की दूरी मात्र 10–15 फीट तक सुरक्षित दूरी न होना अभिनिर्धारित की गई और कार चालक द्वारा उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण चालन करना अवधारित किया गया।

(ii) योगदायी उपेक्षा का प्रश्न तभी उठता है जब दोनों पक्ष वाहन चलाते समय उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण रहे हों।

(iii) धारा 140 के अधीन वाहन स्वामी का दायित्व इस तथ्य पर निर्भर नहीं करता है कि वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक नहीं चलाया गया था। **139 236**

Section 147 – Due to effect of Section 64VB of the Insurance Act and Section 147 of Motor Vehicles Act, Insurance Company cannot postpone the liability after receipt of premium and is liable to pay compensation.

धारा 147 – बीमा अधिनियम की धारा 64VB एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 147 के प्रभाव के कारण, बीमा कंपनी प्रीमियम की राशि प्राप्त करने के बाद दायित्व को स्थगित नहीं कर सकती और प्रतिकर अदा करने के दायित्वाधीन है। **89 162**

Section 147 – On accident by vehicle taken on hire by State Corporation whose conductor was provided by Corporation and driver, by owner, registered owner, Corporation and insurance company liable to pay compensation jointly and severally and corporation would be entitled to recover the amount from the owner as per the agreement between them.

धारा 147 – राज्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए वाहन से दुर्घटना होने पर, जिसका परिचालक निगम द्वारा प्रदान किया गया था और चालक, स्वामी द्वारा, पंजीकृत स्वामी, निगम व बीमा कंपनी संयुक्ततः व पृथकतः क्षतिपूर्ति अदा करने के दायित्वाधीन हैं तथा उनके मध्य हुए करार के अनुसार निगम, स्वामी से राशि वसूल करने का हकदार होगा। **91* 166**

Section 147 – When claimant travelling in the tractor as a passenger in breach of policy, insurance company is not liable but directed to pay the compensation with liberty to recover it from the owner.

धारा 147 – पॉलिसी के उल्लंघन में जब दावेदार ट्रैक्टर में यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था, तब बीमा कंपनी दायित्वाधीन नहीं है परंतु स्वामी से वसूल करने की स्वतंत्रता के साथ प्रतिकर अदा करने हेतु निर्देशित किया गया। **90 165**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 147 – When doctrine of pay and recovery is not permissible?		
धारा 147 – कब भरो एवं वसूल करो का सिद्धांत लागू नहीं होता है?	**239***	**465**
Section 147(1) – (i) Liability of insurance company when the deceased comes under the purview of Workmen's Compensation Act, 1923. (ii) Whether call to abstain from work is a sufficient cause for non-appearance of counsel?		
धारा 147(1) – (i) बीमा कम्पनी का दायित्व जब मृतक कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की परिधि में आता है। (ii) क्या कार्य से विरत रहने का आह्वान अधिवक्ता की अनुपसंजाति हेतु पर्याप्त कारण है?	**240**	**466**
Sections 147 and 149 – Law relating to cancellation of Insurance policy and intimation thereto.		
धाराएं 147 एवं 149 – बीमा पॉलिसी के रद्दकरण तथा इसकी सूचना से संबंधित विधि।	**241**	**468**
Section 163 – When deduction of amount received under insurance policy or other contract is permissible for assessment of compensation?		
धारा 163 – प्रतिकर के निर्धारण हेतु बीमा पॉलिसी अथवा अन्य संविदा के अधीन प्राप्त राशि की कटौती कब अनुज्ञेय है?	**242**	**472**
Section 163 – (i) Whether age of deceased or the age of claimant should be taken into account for assessment of compensation? (ii) Whether future prospects can be awarded, where deceased was self employed person? (iii) Appropriate scale for damages for loss to estate, loss to love and affection and funeral expenses.		
धारा 163 – (i) प्रतिकर के निर्धारण हेतु दावाकर्ता की आयु अथवा मृतक की आयु में से किसे ध्यान में रखा जाना चाहिए? (ii) क्या भविष्यवर्ती संभावनाएं अधिनिर्णीत की जा सकती हैं, जहां मृतक स्वनियोजित था? (iii) संपत्ति की क्षति, प्रेम एवं स्नेह की क्षति एवं अंतिम संस्कार के खर्चों के लिये क्षतिपूर्ति हेतु समुचित मापदण्ड।	**243**	**474**
Section 163 – Deduction of quantum with regard to personal expenses of deceased.		
धारा 163 – मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के संबंध में राशि की कटौती किया जाना।	**244***	**476**
Section 163A – Meaning of 'accident' arising out of the use of a motor vehicle.		
धारा 163क – मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न 'दुर्घटना' का तात्पर्य।	**246***	**477**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 163 and 166 – Assessment of compensation when victim is a student.		
धाराएं 163 एवं 166 – प्रतिकर का निर्धारण जबकि पीड़ित एक विद्यार्थी हो।	**245**	**476**
Sections 165 and 166 – Whether death due to electrocution by wire while standing on top of roof of bus, comes under accident arising out of the use of a motor vehicle?		
धाराएं 165 एवं 166 – क्या बस की छत के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से हुई मृत्यु मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न हुई दुर्घटना के अंतर्गत आती है?	**247***	**478**
Section 166 – Assessment of compensation and future prospects.		
धारा 166 – प्रतिकार का निर्धारण और भविष्य की संभावनाएं।	**314***	**605**
Section 166 – (i) Assessment of compensation in death cases. (ii) Whether *ex-gratia* payment received by the claimants from the employer of the deceased is to be deducted while assessing pecuniary loss?		
धारा 166 – (i) मृत्यु के मामले प्रतिकर का निर्धारण। (ii) क्या आर्थिक नुकसानी के निर्धारण में दावाकर्ता द्वारा मृतक के नियोक्ता से अनुग्रहपूर्वक प्राप्त भुगतान की कटौती की जानी चाहिए?	**315**	**605**
Section 166 – Determination of multiplier.		
धारा 166 – गुणांक का निर्धारण।	**316***	**610**
Section 166 – Driving the vehicle by the deceased driver without a driving license, does not amount to contributory negligence on his part.		
धारा 166 – मृतक चालक द्वारा बिना चालन अनुज्ञप्ति के वाहन चलाना उसकी स्वयं की ओर से योगदायी उपेक्षा नहीं है।	**92***	**166**
Section 166 – When claimant suffered permanent disability by amputation of his left leg, his disability assessed to 90% as with the amputated leg, claimant, cannot pursue his livelihood as driver or daily wage labourer.		
धारा 166 – जब दावाकर्ता के बाएं पैर के विच्छेदन के कारण स्थाई विकलांगता कारित हुई, उसकी विकलांगता 90 प्रतिशत आंकलित की गई क्योंकि, विच्छेदित पैर के साथ, दावाकर्ता, वाहन चालक या दिहाड़ी मजदूर के रूप में अपनी आजीविका अर्जित नहीं कर सकता है।	**140***	**238**
Sections 166 and 168 – Whether claim petition against insurance company alone is maintainable in cases of composite negligence of both the vehicles?		
धाराएं 166 एवं 168 – क्या दोनों वाहनों की सम्मिश्रित उपेक्षा की दशा में मात्र बीमा कंपनी के विरूद्ध दावा याचिका पोषणीय है?	**248**	**478**
Sections 166, 168 and 173 – Concept of actionable negligence in motor accident claim cases.		
धाराएं 166, 168 एवं 173 – मोटर यान दावों के मामलों में अनुयोज्य असावधानी की अवधारणा।	**317**	**610**

Sections 166, 168 and 173 – (i) Factors for consideration while estimating functional disability.

(ii) When multiplier method to be applied in injury cases?

धाराएं 166, 168 एवं 173 – (i) कार्यात्मक निर्योग्यता के प्राक्कलन हेतु विचारणीय कारक।

(ii) क्षति के मामलों में कब गुणक पद्धति लागू होती है? **38** **88**

Sections 166, 168 and 169 – Scheme and nature of provisions of the Act relating to compensation.

धाराएं 166, 168 एवं 169 – अधिनियम के अधीन प्रतिकर संबंधी उपबंधों की योजना एवं प्रकृति। **249** **479**

Section 168 – Can a Tribunal award compensation in excess of the claimed amount?

धारा 168 – क्या अधिकरण दावाकृत राशि से अधिक राशि का अधिनिर्णय पारित कर सकते हैं? **250** **481**

Section 168 – Claimants of deceased agriculturist who was also doing other work, are entitled to future prospects in view of decision in ***National Insurance Company Limited v. Pranay Sethi, (2017) 16 SCC 680***.

धारा 168 – मृतक कृषक जो अन्य कार्य भी करता था, के दावेदार ***नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटिड वि. प्रणय सेठी, (2017) 16 एससीसी 680,*** में दिए गए निर्णय अनुसार भविष्यवर्ती लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। **93*** **167**

Section 168 – (i) In relation to future prospects, law laid down in ***National Insurance Company Limited v. Pranay Sethi, (2017) 16 SCC 680,*** should be followed.

(ii) Deduction for personal and living expenses from the income of the deceased bachelor where widowed mother and large number of younger non-earning sisters or brothers were dependent on his income may be restricted to one-third.

(iii) Aged father and non-earning brother/sister dependent on deceased would be entitled to compensation as his dependents.

(iv) The term 'Consortium' includes 'spousal consortium', 'parental consortium', and 'filial consortium'.

धारा 168 – (i) भविष्यवर्ती लाभ के संबंध में ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वि. प्रणय सेठी, (2017) 16 SCC 680,*** में प्रतिपादित विधि का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(ii) अविवाहित मृतक की आय से व्यक्तिगत व जीवन निर्वाह व्यय कि की जाने वाली कटौती को जहां विधवा मां और आय न अर्जित करने वाले बड़ी संख्या में भाई या बहन उसकी आय पर आश्रित थे, एक तिहाई तक सीमित किया जा सकता है।

(iii) मृतक पर आश्रित वृद्ध पिता व गैर कमाऊ भाई–बहिन आश्रित के रूप में प्रतिकर पाने के हकदार हैं।

(iv) सहचर्य अभिव्यक्ति में 'दाम्पत्यिक सहचर्य', 'पैतृक सहचर्य' एवं 'सन्तान संबंधी सहचर्य' शामिल हैं। **94** **167**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 168 – (i) Necessity of recording of reasons for judicial order. (ii) Determination of just compensation and issues relating to deduction. **धारा 168** – (i) न्यायिक आदेश हेतु कारणों के अभिलिखित किये जाने की आवश्यकता। (ii) न्यायोचित क्षतिपूर्ति का निर्धारण तथा कटौती से संबंधित बिंदु।	**1**	**1**
Section 169 – Duties of the Presiding Officer of the Motor Accident Claims Tribunal. **धारा 169** – मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य।	**251**	**482**
NDPS ACT, 1985 **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985**		
Sections 2 (v), 2 (xii), 2 (xvi), 2 (xix), 2 (xx), 2 (xiv), 2 (xxiii) and 21 – Factors for determining the quantity of narcotic drug and psychotropic substances – Matter referred to the larger bench. **धाराएं 2 (v), 2 (xii), 2 (xvi), 2 (xix), 2 (xx), 2 (xiv), 2 (xxiii) एवं 21** – स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ की मात्रा के निर्धारण हेतु कारक – मामला वृहद पीठ को भेजा गया।	**39**	**94**
Sections 8/18 (b) and (c) r/w/s 29 – Effect of taking samples from one of the many packets. **धाराएं 8/18 (ख) एवं (ग) सहपठित धारा 29** – कई पैकटों में से किसी एक पैकेट से नमूना लेने का प्रभाव।	**252***	**484**
Sections 8, 15, 42, 50 and 57 – (i) Section 50 of the Act does not apply when recovery of contraband does not involve personal search. (ii) Testimony of police officials; evidentiary value of – Principles reiterated (iii) When contraband was recovered from verandah annexed with houses – Revenue records show that house belongs to accused – Secretary of Gram Panchayat also proved that *verandah* is annexed with house and is in possession of accused – Cross-examination of witness remain intact – Held, contraband was recovered from exclusive and conscious possession of accused. **धाराएं 8, 15, 42, 50 एवं 57** – (i) अधिनियम की धारा 50 तब लागू नहीं होती है जब निषिद्ध वस्तु की जप्ती में व्यक्तिगत तलाशी शामिल नहीं होती है। (ii) पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य – सिद्धांत दोहराए गए। (iii) जब घर के साथ लगे बरामदे से निषिद्ध वस्तु जप्त की गई थी – राजस्व अभिलेख दर्शित करते हैं कि घर अभियुक्त का है – ग्राम पंचायत के सचिव ने यह भी साबित किया कि बरामदा घर से लगा हुआ है जो अभियुक्त के आधिपत्य में है – साक्षी का प्रतिपरीक्षण अक्षुण्ण रहा – अभिनिर्धारित, निषिद्ध वस्तु अभियुक्त के अनन्य और सजग आधिपत्य से प्राप्त की गई थी।	**199**	**327**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 8, 22 and 68 – See Section 389 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 8, 22 एवं 68 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389।	**170**	**291**
Sections 21(c), 29 and 67 – Confessional statement of co-accused recorded u/s 67 of the N.D.P.S. Act cannot form the sole basis of conviction of another co-accused.		
धाराएं 21(ग), 29 एवं 67 – स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के तहत अभिलिखित सहअभियुक्त के संस्वीकृति कथन, अन्य सहअभियुक्त की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकते हैं।	**141**	**239**
Section 32B – Whether trial court can impose punishment higher than the minimum term of imprisonment prescribed in absence of any of the factors enumerated in clauses (a) to (f) of Section 32?		
धारा 32ख – क्या विचारण न्यायालय धारा 32 के खण्ड (क) से (च) में प्राविधित किन्हीं बातों के अभाव में न्यूनतम विहित दण्डादेश से अधिक दण्डादेश अधिरोपित कर सकता है?	**318**	**612**
Section 50 – Applicability of Section 50 where recovery is made from bags.		
धारा 50 – धारा 50 की प्रयोज्यता जहाँ कि बरामदगी थैले से हुई हो।	**253 (i)**	**485**
NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881		
पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881		
Sections 20, 138 and 139 – (i) Liability in case of issuance of signed blank cheque. (ii) Nature of presumption u/s 139.		
धाराएं 20, 138 एवं 139 – (i) निरंक हस्ताक्षरित चैक जारी करने की दशा में दायित्व। (ii) धारा 139 के अधीन उपधारणा की प्रकृति।	**254***	**489**
Sections 118, 138 and 139 – Complainants/appellants case found to be proved that the two cheques were issued towards the discharge of an existing liability and legally enforceable debt – Respondent also admitted his signature in cheques and pro-note – Held, presumption under Section 139 would operate – But respondent failed to produce any credible evidence to rebut the statutory presumption – Hence, conviction held proper.		
धाराएं 118, 138 एवं 139 – आवेदकगण/अपीलार्थीगण का मामला, कि दो चैक विद्यमान दायित्व तथा वैध रूप से प्रवर्तनीय ऋण के उन्मोचन के लिए जारी किए गए थे, प्रमाणित पाया गया, प्रत्यर्थी ने भी चैकों व प्रोनोट पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए – अभिनिर्धारित, धारा 139 के तहत उपधारणा प्रवर्तनीय होगी – पर वैधानिक उपधारणा के खंडन में विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में प्रत्यर्थी असफल रहा अतः, दोषसिद्धी उचित ठहराई गई।	**142**	**244**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 118 and 139 – Whether from of receipts or accounts are relevant factors while examining, whether the accused has been able to rebut the presumption?		
धाराएं 118 एवं 139 – क्या अभियुक्त द्वारा उपधारणा को खण्डित किए जाने के विवेचन हेतु रसीद या लेखा का प्रारूप सुसंगत कारक है?	**212**	**402**
Section 138 – Amendment of typographical errors can be made in a complaint filed u/s 138 of N.I. Act		
धारा 138 – परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन प्रस्तुत परिवाद में लेखन संबंधी त्रुटियों का संशोधन किया जा सकता है।	**95***	**170**
Section 138 – Law relating to complaint against company under Section 138.		
धारा 138 – धारा 138 के अंतर्गत कंपनी के विरूद्ध परिवाद से संबंधित विधि।	**256**	**491**
Section 138 – Quantum of sentence – Accused was sentenced to undergo two months simple imprisonment, ₹ 10,000/- fine and further directed to pay compensation of ₹ 6,00,000/- – She deposited the fine and amount of compensation – Considering that she was just 24 years of age and the only earning member in her family, her father was unwell and physically incapable of doing any work, she was serving as a teacher and her monthly income was around ₹ 4,000/- – If she is compelled to undergo the sentence of two months, she would lose her job and her entire family would suffer penury situation – Jail sentence was modified to additional compensation of ₹ 50,000/-.		
धारा 138 – दण्ड की मात्रा अभियुक्त को दो माह के साधारण कारावास के साथ ₹ 10,000/– का अर्थदण्ड एवं ₹ 6,00,000/– का प्रतिकर अदा करने का निर्देश दिया गया – उसने अर्थदण्ड और प्रतिकर की राशि जमा कर दी – इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि अभियुक्त मात्र 24 वर्ष की थी ओर अपने परिवार की एकमात्र आय अर्जित सदस्य थी, उसके पिता अस्वस्थ थे और शारीरिक रूप से कोई भी काम करने में असमर्थ थे, वह एक शिक्षक के रूप में सेवा कर रही थी और उसकी मासिक आय लगभग ₹ 4000/– थी – यदि उसे दो माह का कारावास भुगतने के लिए भेजा जाता है, तो वह अपनी नौकरी खो देगी और उसके पूरे परिवार को दरिद्रता की स्थिति भुगतनी होगी – अतः कारावासीय दण्ड को ₹ 50,000/– के अतिरिक्त प्रतिकर में बदल दिया गया।	**143***	**246**
Section 138 – See Section 427 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 138 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 427।	**171**	**293**
Section 138 – Whether payment of balance consideration in pursuance of agreement to sale amounts to legally enforceable debt?		
धारा 138 – क्या विक्रय करार के पालन में शेष प्रतिफल का संदाय विधितः प्रवर्तनीय ऋण की श्रेणी में आता है?	**255**	**491**

Sections 138 and 139 – (i) Presumption when signature upon cheque is admitted by accused.

(ii) Presumption – When accused raises a probable defence regarding financial capacity of complainant in his cross-examination.

धाराएं 138 एवं 139 – (i) उपधारणा जबकि अभियुक्त द्वारा चैक पर हस्ताक्षर स्वीकार कर लिया गया है।

(ii) उपधारणा जबकि अभियुक्त द्वारा परिवादी के प्रतिपरीक्षण के दौरान उसकी आर्थिक सक्षमता को लेकर अधिसंभाव्य बचाव लिया जाता है। **319*** **614**

Sections 138 and 142 – Dishonour of cheque – Multiple demand notices – Cause of action when arises?

धाराएं 138 एवं 142 – चैक का अनादरण – एक से अधिक मांग सूचना पत्र – वाद हेतुक कब उत्पन्न होगा? **320** **614**

Sections 138 and 142 – Effect of serving demand notice beyond the period of 30 days.

धाराएं 138 एवं 142 – 30 दिवस के पश्चात् मांग सूचना पत्र के भेजे जाने का प्रभाव। **40*** **98**

Sections 138 and 143-A – (i) Whether Section 143-A shall be applicable to pending trials?

(ii) Whether opportunity of hearing is required to be given to the accused before imposing interim compensation under Section 143-A of the Act?

धाराएं 138 एवं 143–क – (i) क्या धारा 143–क लंबित विचारणों पर लागू होगी?

(ii) क्या अभियुक्त पर अधिनियम की धारा 143–क के अधीन अंतरिम प्रतिकर अधिरोपित करने के पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है? **257** **494**

Sections 138 and 148 – (i) Whether amendment as to power of Appellate Court to order payment pending appeal against conviction shall be applicable to the proceedings initiated prior to the date of insertion of Section 148 i.e. 01.09.2018?

(ii) Whether provision as to direct appellant/accused by Appellate Court to deposit minimum 20% of the fine or compensation awarded by the trial Court u/s 148, is mandatory?

(iii) Whether Section 357(2) of Cr.P.C. is applicable to Section 148 of the Negotiable Instruments Act?

धाराएं 138 एवं 148 – (i) क्या दोषसिद्धि के विरूद्ध लंबित अपील में भुगतान करने की अपीलीय न्यायालय की शक्ति से संबंधित संशोधन धारा 148 के समाविष्ट किए जाने की तिथि यथा 01.09.2018 के पूर्व प्रारंभ कार्यवाहियों पर लागू होगा?

(i) क्या अभियुक्त/अपीलार्थी को अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 148 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत अर्थदण्ड या प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिशत जमा करने का निर्देश देने संबंधी प्रावधान आज्ञापक है?

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(iii) क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 के संबंध में धारा 357(2) दं.प्र.सं. प्रयोज्य है?	321	615
Section 141 – (i) Offences by partnership firm. (ii) Liability of one of the partners for cheques issued by another.		
धारा 141 – (i) भागीदारी फर्म के द्वारा अपराध। (ii) एक भागीदार द्वारा जारी किए गए चेक के लिए दूसरे भागीदार का दायित्व।	322	621
PARTNERSHIP ACT, 1932 **भागीदारी अधिनियम, 1932**		
Section 69 – Maintainability of suit based on unregistered partnership deed.		
धारा 69 – अपंजीकृत भागीदारी विलेख के आधार पर संस्थित वाद की प्रचलनशीलता।	323*	622
PRE-CONCEPTION AND PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION) ACT, 1994 **गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994**		
Sections 17 and 28 – Whether CMHO of a district is competent to file complaint u/s 28 of the Act?		
धाराएं 17 एवं 28 – क्या जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अधिनियम की धारा 28 के अधीन परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम है?	258*	496
PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988**		
Sections 8 and 12 – Liability of non-public servant.		
धाराएं 8 एवं 12 – गैर–लोक सेवक का दायित्व।	324*	623
Section 13 – See Section 300 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 13 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300।	96*	170
Sections 13 and 17 – Whether authorisation order for investigation not filed along with charge sheet can subsequently be filed?		
धाराएं 13 एंव 17 – क्या अभियोग पत्र के साथ अप्रस्तुत अन्वेषण के लिये प्राधिकार आदेश बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है?	325	623

Section 19 – (i) Sanction for prosecution when the person is not holding the relevant office.

(ii) Cheating, fabrication of records or misappropriation of public money.

धारा 19 – (i) अभियोजन के लिए मंजूरी जबकि व्यक्ति संबंधित पद को धारित नहीं करता है।

(ii) छल, अभिलेखों को गढ़ना या लोक संपत्ति का दुर्विनियोग। **41** **98**

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT, 1954
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

Sections 2 (ix) (g), 7 (ii), 16 (1) (a) (ii) and 20A – (i) Impleadment of distributor as a co-accused in case of misbranding.

(ii) Availability of right to get the sample analyzed by the Central Food Laboratories.

धाराएं 2 (ix) (g), 7 (ii), 16 (1) (क) (ii) एवं 20क – (i) मिथ्याछापावली के मामले में वितरक को सह–अभियुक्त के रूप में जोड़ा जाना।

(ii) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा लगाये गये नमूने को प्राप्त करने के अधिकार की उपलब्धतता। **42*** **100**

Section 16 – See Section 134 of the Evidence Act, 1872.

धारा 16 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134। **259** **496**

PROBATION OF OFFENDERS ACT, 1958
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958

Section 4 – See Section 304A of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 4 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304क। **227*** **437**

PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

Sections 2 (1)(d) and 27 – (i) Definition of "child" under Section 2(1)(d) of the POCSO Act means any person below the age of 18 years and does not engulf and embrace, in its connotative expanse, "mental age" of a person irrespective of his or her biological age.

(ii) Medical examination of child is mandatory whether POCSO Act is mentioned in FIR or not.

(iii) POCSO Act is a beneficial legislation and its provisions must be construed to help in carrying out the beneficial purpose of the Act and should not unduly expand the scope of a provision.

धारा 2 (1)(घ) एवं 27 – (i) पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के तहत ''बालक'' की परिभाषा का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से है तथा यह अपने सहवर्ती विस्तार में, किसी व्यक्ति की 'मानसिक आयु' को भी सम्मिलित एवं अंतर्विष्ट नहीं करती है, चाहे ऐसे व्यक्ति की जैविक आयु कुछ भी हो।

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(i) बालक का चिकित्सीय परीक्षण अनिवार्य है चाहे पॉक्सो अधिनियम का उल्लेख एफआईआर में हो अथवा नहीं।		
(iii) पॉक्सो अधिनियम हितकारी विधि है तथा उसके उपबंधों का अर्थान्वयन हितकारी उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करने के लिये किया जाना चाहिए और प्रावधान के विषय का क्षेत्र का अनुचित विस्तार नहीं करना चाहिए।	**144**	**246**
Sections 3 and 4 – See Section 3 of the Evidence Act, 1872 and Section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3 एवं 4 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	**68***	**136**
Sections 5 and 6 – See Section 376 (2) of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 5 एवं 6 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376 (2)।	**191**	**317**
Section 5 (i) and (m) r/w/s 6 – See Sections 376 (A), 302 and 201 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 5 (झ) एवं (ड) सहपठित धारा 6 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 376 (क), 302 एवं 201।	**231**	**449**
PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005		
Sections 2(f) and 12 – Live-in relationship when becomes relationship in the nature of marriage?		
धारा 2(च) एवं 12 – लिव–इन संबंध, विवाह की प्रकृति का संबंध कब बनता है?	**326**	**626**
Sections 12, 26 and 36 – (i) Muslim women can claim relief under Protection of Women from Domestic Violence Act.		
(ii) Proceeding initiated by wife for divorce under Dissolution of Muslim Marriage Act, does not disentitle wife to claim relief under DV Act.		
धाराएं 12, 26 एवं 36 – (i) एक मुस्लिम महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष की मांग कर सकती है।		
(ii) पत्नी द्वारा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद हेतु प्रारंभ की गई कार्यवाही, पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष की मांग से वंचित नहीं करती है।	**145***	**249**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORIZED OCCUPANTS) ACT, 1971		
सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम, 1971		
Section 3 (b) – Estate Officer has to exercise its jurisdiction in relation to the public premises falling in the local limits specified in the notification issued u/s 3 of the Act.		
धारा 3 (ख) – अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं में आने वाले सरकारी स्थान के संबंध में संपदा अधिकारी को क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना है।	**146**	**250**
REGISTRATION ACT, 1908		
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908		
Section 17 – See Section 58 (c) of the Transfer of Property Act, 1882.		
धारा 17 – देखें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58 (ग)।	**99***	**177**
Section 17 – When a compromise decree is required to be registered?		
धारा 17 – कब सहमति डिक्री का पंजीयन आवश्यक है?	**43**	**102**
Sections 17, 49 and 50 – See Section 16 of the Contract Act, 1872.		
धाराएं 17, 49 एवं 50 – देखें संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 16।	**97**	**171**
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989		
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989		
Section 3 (1) (x) – Effect – When complainant omits to mention in his statement that expressions used by accused refer to caste or tribe to which he belongs.		
धारा 3 (1) (x) – परिवादी अपने कथनों में अभियुक्त द्वारा उसकी जाति या वर्ग सूचक शब्दों का प्रयोग किए जाने के उल्लेख के लोप का प्रभाव।	**327***	**628**
Section 3(1)(x) – (i) Insult or intimidation must be with an intention to humiliate the victim in a public place for being a member of SC/ST community.		
(ii) Word *"Adiwasin"* is not abusive enough to constitute offence u/s 3(1)(x) of the Act – *"Adiwasin"* means a female adiwasi or a female member of ST community beyond which no other meaning deserves to be ascribed to it.		
धारा 3 (1)(x) – (i) अनादर अथवा अभित्रास पीड़ित को एससी/एसटी समुदाय का सदस्य होने से अपमानित करने के आशय से लोक स्थान पर होना चाहिए।		

(ii) शब्द ''आदिवासिन'' अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त अपमानजनक नहीं है – ''आदिवासिन'' का अर्थ है महिला आदिवासी या एसटी समुदाय की महिला सदस्य जिसके अतिरिक्त उस शब्द को अन्य कोई अर्थ देना उचित नहीं है।

98 176

SERVICE LAW:
सेवा विधिः

– (i) Right for compassionate appointment is not a vested right.

(ii) While considering an application for compassionate appointment, policy prevailing at time of consideration of the application is applicable.

(i) अनुकम्पा नियुक्ति का अधिकार निहित अधिकार नहीं है।

(ii) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पर विचार करते समय, आवेदन पर विचार के समय अभिभावी नीति लागू होती है। **147* 251**

– See Regulation 20 (3) (iii) of the UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976.

– देखें यूकों बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 का विनियम 20 (3) (iii)।

44 105

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

Section 19(b) – (i) Requirement to implead all the legal heirs.

(ii) Power of *Karta* to sell coparcenary property.

(iii) Proper form of a decree for specific performance of suit involving transferor, prior transferee and subsequent transferee.

धारा 19(ख) – (i) समस्त विधिक उत्तराधिकारियों को संयोजित किये जाने की आवश्यकता।

(ii) सहदायिक संपत्ति को विक्रय करने की कर्ता की शक्ति।

(iii) अंतरक, पूर्ववत् अंतरिती तथा पश्चात्वर्ती अंतरिती से संबंधित विनिर्दिष्ट पालन के वाद में डिक्री का उचित प्रारूप। **260 497**

Section 20 – To have a relief of specific performance of unregistered agreement to sale, proof of execution of agreement is a must and where *factum* of execution of agreement itself is doubted, plaintiff/appellant is not entitled to the relief of specific performance.

धारा 20 – अपंजीकृत विक्रय करार के विनिर्दिष्ट पालन की सहायता प्राप्त करने के लिए, करार के निष्पादन का सबूत आवश्यक है तथा जहां करार के निष्पादन का तथ्य स्वमेव में संदेहास्पद है, वादी/अपीलार्थी विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

148* 252

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 34 – Whether suit for mere declaration without claiming the relief of partition, is maintainable?		
धारा 34 – क्या विभाजन के अनुतोष का दावा किये बिना, मात्र घोषणा हेतु वाद पोषणीय है?	**45**	**106**
Section 38 – Meaning of word "occupier" for the purpose of granting mandatory injunction.		
धारा 38 – आज्ञापक व्यादेश अनुदत्त करने के प्रयोजन से शब्द ''अधिभोगी'' से तात्पर्य।	**261**	**502**
Section 38 – Perpetual injunction against co-owner.		
धारा 38 – सह–स्वामी के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश।	**328***	**628**
Section 38 – (i) Relief of perpetual injunction can only be granted to a person who is in actual and lawful possession of suit property on the date of suit. (ii) Burden of proof lies upon plaintiff to prove that he was in actual and physical possession of the property on the date of suit and the fact of possession of the plaintiff cannot be inferred from circumstances and plaintiff is bound to prove it. (iii) A person who is not paying rent for more than fifteen years cannot be said to be in lawful possession.		
धारा 38 – (i) शाश्वत व्यादेश का अनुतोष केवल ऐसे व्यक्ति को ही अनुदत्त किया जा सकता है जो वाद की तिथि पर वादग्रस्त सम्पत्ति के वास्तविक एवं विधिपूर्ण आधिपत्य में हो। (ii) सबूत का भारत वादी पर होता है वह यह साबित करे कि वह वाद की तिथि पर सम्पत्ति के वास्तविक एवं भौतिक आधिपत्य में था तथा वादी के आधिपत्य के तथ्य का परिस्थितियों से अनुमान नहीं निकाला जा सकता है और वादी इसे साबित करने के लिए आबद्ध है। (iii) ऐसा व्यक्ति जो विगत पंद्रह वर्षों से भाटक संदाय नहीं कर रहा है, विधिपूर्ण आधिपत्य में नहीं कहा जा सकता है।	**149**	**253**
SUCCESSION ACT, 1925		
उत्तराधिकार अधिनियम, 1925		
Section 214 – See Sections 28A and 53 of the Land Acquisition Act, 1894.		
धारा 214 – देखें भूमि–अर्जन अधिनियम, 1894 की धाराएं 28क एवं 53।	**236**	**458**
Section 383 – Revocation of Succession Certificate.		
धारा 383 – उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण।	**329***	**629**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
STAMP ACT, 1899		
स्टाम्प अधिनियम, 1899		
Section 33 – Payment of stamp duty for property sold by public auction.		
धारा 33 – लोक नीलामी द्वारा विक्रीत संपत्ति हेतु स्टाम्प शुल्क का संदाय।	**46***	**107**
Item 12 of Schedule I – Whether the foreign award is included in "award" under Item 12 of Schedule I of the Act?		
अनुसूची I का मद क्रमांक 12 – क्या अधिनियम की अनुसूची I के मद क्रमांक 12 के अंतर्गत ''पंचाट'' में विदेशी पंचाट शामिल है?	**47***	**108**
TRADE MARKS ACT, 1999		
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999		
Section 29 – Action for passing off – Relevancy of defendant's state of mind in formation of cause of action for passing off.		
धारा 29 – पासिंग ऑफ के लिये कार्यवाही – पासिंग ऑफ के लिए वाद हेतुक के गठन में प्रतिवादी की मानसिक अवस्था की सुसंगतता।	**33***	**74**
TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882		
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882		
Sections 8 and 54 – See Hindu Law and Section 27, Articles 64 and 65 of the Limitation Act, 1963.		
धाराएं 8 एवं 54 – देखें हिन्दू विधि एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27, अनुच्छेद 64 एवं 65।	**294**	**554**
Section 43 – Transfer by unauthorised person – The transfer was under fraudulent/ erroneous representation about being authorised to transfer – Such person subsequently acquires interest in property transferred – In the circumstances, the suit by the heirs of the transferor for cancellation of the sale deed would not be maintainable – Rights of transferee would be protected by operation of Section 43 of the Act.		
धारा 43 – अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण – अंतरण करने के लिए अधिकृत होने के संबंध में कपटपूर्ण/मिथ्या प्रदर्शन के अधीन अंतरण – तत्पश्चात अंतरित सम्पत्ति में ऐसा व्यक्ति हित अर्जित करता है – ऐसी परिस्थितियों में अंतरणकर्ता के उत्तराधिकारियों के द्वारा विक्रयपत्र को निरस्त करने का वाद संधारणीय नहीं होगा – अधिनियम की धारा 43 के प्रवर्तन द्वारा अंतरिती के अधिकार संरक्षित होंगे।	**150**	**254**
Section 52 – See Order 21 Rules 97, 100 and 102 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 52 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 21 नियम 97, 100 एवं 102।	**112**	**194**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 54 – See Sections 68, 69 and 90 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 54 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 68, 69 तथा 90।	**178**	**299**
Section 54 – (i) What interest can be transferred in tangible property? (ii) When does the right in property of a person, not in possession of such property, extinguish?		
धारा 54 – (i) मूर्त संपत्ति में कौन सा हित अंतरित किया जा सकता है? (ii) संपत्ति के आधिपत्य में रहने वाले किसी व्यक्ति का ऐसी संपत्ति में अधिकार कब निर्वापित हो जाता है?	**48***	**109**
Section 58 – When possession of mortgagee becomes adverse to the original owner?		
धारा 58 – कब बंधकदार का आधिपत्य मूल स्वामी के प्रतिकूल हो जाता है?	**49***	**110**
Section 58 (c) – (i) Distinction and assessment in "mortgage by conditional sale" and "sale with a condition to repurchase". (ii) Interpretation of "mortgage by conditional sale" and "sale with a condition to repurchase".		
धारा 58 (ग) –(i) ''सशर्त विक्रय द्वारा बंधक'' तथा ''पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय'' में विभेद एवं निर्धारण। (ii) ''सशर्त विक्रय द्वारा बंधक'' तथा ''पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय'' का अर्थान्वयन।	**330***	**629**
Section 58 (c) – In registered sale deed, no conditions of mortgage or of conditional sale mentioned and subsequent agreement of mortgage converting transaction into that of a conditional sale or mortgage, not registered – Such document is in admissible in evidence and cannot be relied upon in a suit for redemption of mortgage.		
धारा 58 (ग) – पंजीकृत विक्रय अभिलेख में बंधक अथवा सशर्त विक्रय की शर्तें वर्णित नहीं तथा संव्यवहार को सशर्त विक्रय या बंधक में परिवर्तित करने का पश्चात का बंधक का करार पंजीकृत नहीं – ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और बंधक मोचन हेतु वाद में निर्भरित नहीं किया जा सकता।	**99***	**177**
Section 122 – Mentioning of value of property for the purpose of stamp duty and registration charges on first page of gift deed does not invalidate the same by saying that consideration has been received by donor for executing gift deed.		
धारा 122 – दान विलेख के प्रथम पृष्ठ पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन प्रभारों के उद्देश्य से संपत्ति की कीमत का उल्लेख किया जाना दान विलेख को यह कहते हुए अमान्य नहीं करता है कि दान विलेख निष्पादित करने के लिये दाता द्वारा प्रतिफल प्राप्त किया जा चुका है।	**200***	**330**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 122, 123, 124, 125 and 126 – Whether a conditional and incomplete gift can be cancelled?		
धाराएं 122, 123, 124, 125 एवं 126 – क्या सशर्त और अपूर्ण दान रद्द किया जा सकता है?	**50**	**111**
UCO BANK OFFICER EMPLOYEES' (CONDUCT) REGULATIONS, 1976		
यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976		
Regulation 20 (3) (iii) – Whether an employee is entitled to subsistence allowance during pendency of an inquiry against him?		
विनियम 20 (3) (iii) – क्या एक कर्मचारी उसके विरूद्ध लंबित जाँच के दौरान निर्वाह भत्ता पाने का अधिकारी है?	**44**	**105**
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967		
विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967		
Section 43D(2) – See Sections 167(2) of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 43घ(2) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167(2)।	**206**	**391**
URBAN LAND (CEILING AND REGULATION) ACT, 1976		
शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976		
Section 10 (3) – Third party purchaser, purchasing property after issuance of notification u/s 10 (3) of the Act, has no *locus standi* to claim the right in land.		
धारा 10 (3) – अधिनियम की धारा 10(3) के अधीन अधिसूचना जारी होने के बाद संपत्ति क्रय करने वाले व्यक्ति के पास उस भूमि पर दावा करने की कोई हैसियत नहीं होती है।	**100***	**178**
WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1972		
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972		
Section 50 – See Section 52 of the Forest Act, 1927.		
धारा 50 – देखें वन अधिनियम, 1927 की धारा 52।	**214**	**407**
WAKF ACT, 1995		
वक्फ़ अधिनियम, 1995		
Sections 6 and 85 – (i) Jurisdiction of Civil Court in matters relating to Wakf.		
(ii) Whether a non-Muslim or stranger to the Wakf can file suit before the Tribunal or raise dispute as to status of property before Tribunal?		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 6 एवं 85 – (i) वक्फ से संबंधित मामलों में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार। (ii) क्या कोई गैर–मुस्लिम अथवा वक्फ़ से अपरिचित व्यक्ति अधिकरण के समक्ष वाद संस्थित कर सकता है अथवा संपत्ति की प्रास्थिति के संबंध में प्रतिवाद कर सकता है?	**262**	**504**

PART- II A
(GUIDELINES)

1.	Directives issued by the Supreme Court for the effective implementation of Witness Protection Scheme, 2018	**257**
2.	Guidelines to be followed by Motor Accidents Claims Tribunals	**331**
3.	यूनियन ऑफ इंडिया विरूद्ध मोहन लाल व अन्य (दांण्डिक अपील क्रमांक 652/2012 आदेश दिनांक 28.1.2016) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश	**113**

PART-III
(CIRCULARS/NOTIFICATIONS)

1.	Notification of State Government regarding designation of Special Courts for trail of cases under Madhya Pradesh NIkshepkon ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam, 2000.	**1**
2.	Notification dated 16.08.2019 of Ministry of Women and Child Development (CW-I Section) regarding the date of enforcement of POSCO (Amendment) Act, 2019.	**1**
3.	Notification dated 28.08.2019 of Ministry of Road Transport and Highways regarding the dated of enforcement of certain provisions of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019.	**1**
4.	Notification dated 30.08.2019 of Ministry of Road Transport and Highways regarding the date of enforcement of the Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019.	**2**

PART – IV
IMPORTANT CENTRAL/STATE ACTS & AMENDMENTS

1.	Amendments in the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008	**13**
2.	Amendments in the Madhya Pradesh Civil Court Rules, 1961	**13**
3.	Amendment in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal)	**14**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
4. Amendments in the District Courts of Madhya Pradesh Digitization of Records Rules, 2016		**14**
5. Madhya Pradesh Video Conferencing Rules, 2018		**15**
6. The High Court of Madhya Pradesh (Designation of Senior Advocates) Rules, 2018		**5**
7. The Madhya Pradesh Adhivakata Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019		**55**
8. The Madhya Pradesh Excise (Amendment) Act, 2014		**26**
9. The Madhya Pradesh District Court Technical Manpower (Appointment & Conditions of Service) Rules, 2019		**27**
10. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019		**1**
11. The Personal Laws (Amendment) Act, 2019		**11**
12. The Protection of Children from Sexual offences (Amendment) Act, 2019		**55**

NOMINAL INDEX OF CASES INCLUDED IN PART II

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
A.K. Hade v. Shailendra Singh Yadav and anr.	ILR (2018) MP 1807	308	588
Aarish Asgar Qureshi v. Fareed Ahmed Qureshi and another	2019 (2) Crimes 43 (SC)	162*	279
Accused 'X' v. State of Maharashtra	2019 (2) Crimes 175 (SC)	163	279
Achpal alias Ramswaroop and another v. State of Rajasthan	AIR 2018 SC 4647	15	25
Aftab Khan v. State of M.P.	ILR (2018) MP 1194 (DB)	229	440
Ajad Khan v. Vaheed Khan and another	AIR 2019 MP 69	198*	326
Ajay Choudhari v. State of M.P.	2019 (1) ANJ (MP) 93	129*	217
Ajit Kaur alias Surjit Kaur v. Darshan Singh (Dead) Through LRs. and others	AIR 2019 SC 2122	296	562
Alkem Laboratories Ltd. (M/s.) v. State of M.P. and anr.	ILR (2018) MP 1314	42*	100
Alok v. Shashi Somani and others	2018 (3) MPLJ 641	4*	11
Alok Khanna v. M/s Rajdarshan Hotel Pvt. Ltd.	ILR (2018) MP 709	56	122
Amar Nath Jha v. Nand Kishore Singh & etc.	2018 (3) Crimes 486 (SC)	13*	24
Ambrish and another v. State of M.P. and another	2018 (4) MPLJ 52	100*	178
Amrish Rana v. State of Himachal Pradesh	AIR 2018 SC 4604	70*	138
Anil Dhakad v. State of M.P.	ILR (2018) MP 1835	291	551
Anubhav Ajmani v. Smt. Garima Ajmani	ILR (2018) MP 2043	274	522
Anurag Mathur & ors v. State of M.P. and anr.	ILR (2017) MP 2031	193	320
Anurag Soni v. State of Chhattisgarh	2019 (2) Crimes 162 (SC)	190	315
Asar Mohammad v. State of U.P.	AIR 2018 SC 5264	22	44
Ashish Jain v. Makrand Singh and ors.	2019 (1) ANJ (SC) (Suppl.) 76	225	429
Ashok Lalwani v. State Bank of India	2019 (1) MPLJ 575	111	192
Asim Shariff v. National Investigation Agency	(2019) 7 SCC 148	281	536
Atma Ram and others v. State of Rajasthan	AIR 2019 SC 1961	284*	539
Babita and others v. Jubair and others	2019 ACJ 1403	244*	476
Badrisingh v. State of M.P.	ILR (2017) MP 1952	199	327
Bal Mukund Sharma alias Balkund Chaudhary and others v. State of Bihar	(2019) 5 SCC 469 (3 Judge Bench)	297	564
Balakrishnan and others v. State of Tamil Nadu	2019 CriLJ 930	175*	297
Balkrishna Dattatraya Galande v. Balkrishna Rambharose Gupta	AIR 2019 SC 933	149	253

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Basalingappa v. Mudibasappa	AIR 2019 SC 1983	319*	614
Bengal Chemists and Druggists Association v. Kalyan Chowdhury	2018 (4) MPLJ 7 (SC)	10	18
Bhagirath v. The State of Madhya Pradesh	2018 (4) Crimes 380 (SC)	69*	137
Bhagwat v. State of Maharashtra	2018 (4) Crimes 308 (SC)	80	147
Bhagyan Das v. The State of Uttarakhand and Anr.	2019 (2) Crimes 27 (SC)	209	397
Bhanwarlal v. State of Rajasthan	2019 (1) Rajsthan Law Weekly 586	234	456
Bharat Stars Services Pvt. Ltd. v. Harsh Dev Thakur	AIR 2019 SC 718	172	295
Bhivchandra Shankar More v. Balu Gangaram More and others	(2019) 6 SCC 387	264	507
Bholu Shah @ Jameel Shah and anr. v. State of M.P.	2018 Cri.L.J. 4419	75*	143
Bhupendra Singh & another v. Government of India	ILR (2018) MP 1183	252*	484
Bihari Lal v. State of Rajasthan and others	AIR 2019 SC 1995	282*	537
Bilal Hajar alias Abdul Hameed v. State rep. by Inspector of Police	AIR 2018 SC 4780	81*	149
Binay Chand Ekka v. State of M.P. (Through CBI)	ILR (2018) Short Note 50	66	134
Bir Singh v. Mukesh Kumar	(2019) 4 SCC 197	254*	489
Birendra Prasad Sah v. State of Bihar and another	AIR 2019 SC 2496	320	614
Biswajit Sukul v. Deo Chand Sarda and others	(2018) 10 SCC 584.	8	14
C.R. Kariyappa v. State of Karnataka	AIR 2018 SC 4312	73	141
Champa Lal Dhakar v. Naval Singh Rajpur and ors.	2019 (1) ANJ (SC) (Suppl.) 71	188*	311
Chandra Kumar Chandwani & others v. Anil Gupta and another	ILR (2017) MP 1701	112	194
Chhannu Lal Verma v. State of Chhattisgarh	2019 CriLJ 1146 (SC) (3Judge Bench)	184	304
Commissioner, Mysore urban Development Authority v. S.S. Sarvesh	(2019) 5 SCC 144	273	520
Das Motwani (Dr.) v. State of M.P.	ILR (2017) MP SN 102	258*	496
Deepu @ Deepak v. The State of Madhya Pradesh	2018 (4) Crimes 505 (SC)	61*	127
Dev Wati v. State of Haryana	AIR 2019 SC 641	117	200

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Devendra Prasad Singh v. State of Bihar	AIR 2019 SC 1671	278*	530
Devendra Singh v. State of Madhya Pradesh and another	2019 Cri.L.J. 1958	205*	390
Devraj Maratha @ Dillu v. The State of Madhya Pradesh	2019 (2) ANJ (MP) 41 (DB)	287	541
Dharmaji Shankar Shinde and others v. Rajaram Shripad Joshi (Dead) through LRs. and others	AIR 2019 SC 2367	330	629
Dinesh v. State of M.P.	ILR (2017) MP 1544	126*	215
Dr. Amit Kumar v. Dr. Sonila	AIR 2018 SC 5312	26*	57
Dr. Dhruvaram Murlidhar Sonar v. State of Maharashtra and others	AIR 2019 SC 327	216	411
Estate Officer, Haryana Urban Development Authority and another v. Gopi Chand Atreja	AIR 2019 SC 1423	196	324
Firm M/s Modi Kevalchand Through Partners v. Balchand (dead) through Legal Representatives	2019 (2) MPLJ 717	238	462
G. Ramesh v. Kanike Harish Kumar Ujwal and another	2019 (2) Crimes 158 (SC)	322	621
Gagan Kumar v. State of Punjab	AIR 2019 SC 1009	113	196
Gangesh Kumari Kak (Smt.) v. State of M.P. & ors.	ILR (2018) M.P. Short Note 24	58*	124
Gappu Lal Pal v. Director General of Police	(Unreported)	121	206
Gaurav Kumar @ Monu v. The State of Haryana	2019 (1) Crimes 113 (SC)	232	451
Gayatri Rathore v. Yashpal Singh and others	2019 (1) MPLJ 680	261	502
Ghewarchand v. M/s Mahendra Singh	AIR 2018 SC 4857	37	86
Gopalakrishna (Dead) by L.Rs. and others v. Narayanagowda (Dead) by L.Rs. and others	(2019) 4 SCC 592	294	554
Gopaldas Khatri v. Dr. Tarun Dua & anr	ILR (2018) MP 1934	272*	520
Hemant Kumar Chakradhar v. Vinita Chakradhar	2019 (1) ANJ (MP) 110	114*	197
Himanshu v. B. Shivamurthy and another	2019 (1) Crimes 93 (SC)	256	491
Hira Singh and anr. v. Union of India and anr.	(2017) 8 SCC 162	39	94
Hukum Chandra (D) v. Nemi Chand Jain	AIR 2019 SC 60	51	117
ICICI Lombard General Ins. Co. Ltd. v. Mamta Uikey and others	2019 ACJ 1400	240	466
Iffco Tokio General Insurance Co. v. Sohanpal & anr.	2019 ACJ 394	246*	477

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
In Reference v. Jitendra	ILR (2017) MP 1223	9	16
Iqbal Ahamed v. Vice-Chairman, Patel Integrated Logistics Limited and others	2019 ACJ 445 (DB)	251	482
Ishwar Prasad v. State of Madhya Pradesh	ILR (2017) MP 1756	120	205
Jagdish Chand and another v. State of Haryana	2019 (1) Crimes 16 (SC)	82*	150
Jagdish Chander v. Satish Chander and others	AIR 2019 SC 1154	200*	330
Jagdish Singh Kushwah v. Chandrakanta Kushwah and another	2019 (1) MPLJ 686	109*	190
Jagjit Singh v. State of Punjab	AIR 2018 SC 5719 (3 Judge Bench)	24	53
Jahar Singh Lodhi v. Ramkali & ors.	ILR (2017) MP 1462	2*	6
Jamila Begum (D) Thr. LRs. v. Shami Mohd. (D) Thr. LRs.	AIR 2019 SC 72	97	171
Joseph Easwaran Wapshare and others v. Shirley Katheleen Wheeler	(2019) 5 SCC 58	329*	629
Joseph Shine v. Union of India	AIR 2018 SC 4898	32	72
Kalua @ Koshal Kishore v. State of Rajasthan	2019 (2) Crimes 52 (SC)	173*	296
Kamala v. M.R. Mohan Kumar	AIR 2018 SC 5128	12	20
Kamil v. State of Uttar Pradesh	2018 (4) Crimes 301 (SC)	63	129
Kamlesh Gurjar v. State of M.P.	2019 LawSuit (MP) 329	233	453
Karelal and others v. Gyanbai and others	2018 (3) MPLJ 709	45	106
Karuna Kansal v. Hemant Kansal and another	AIR 2019 SC 2341	266	
Kewal Singh Thakur and others v. Oriental Farmers and Builders Pvt. Ltd. and another	2019 (1) MPLJ 638	108*	189
Khemchand Kachhi Patel v. State of M.P.	ILR (2018) MP 747 (DB)	74*	142
Khushwinder Singh v. State of Punjab	(2019) 4 SCC 415 (3 Judge Bench)	226*	437
Kishori Lal & ors. v. Shivcharan & ors.	ILR (2018) MP 1142	5	12
Kripal Singh v. State of Rajasthan	AIR 2019 SC 947	131*	218
Krishan Devi and others v. Oriental Insurance Company Limited and others	2019 ACJ 1366 (SC) (3 Judge Bench)	243	474
Kusumben Indersinh Dhupia v. Subhaben Biharilalji Bhaiya and another	(2019) 3 SCC 569	202*	388
Labhuji Amratji Thakor v. State of Gujarat	AIR 2019 SC 735	118	201

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Lakshmi Sreenivasa Co-operative Building Society v. Puvvada Rama (Dead) by LRs. and others	AIR 2018 SC 3580	148*	252
Lal Singh Marabi v. National Insurance Company Ltd. & ors.	ILR (2017) MP 1619	140*	238
Lalji Chaudhary v. State of M.P.	ILR (2018) MP 1830	289*	548
Lalji v. State of M.P. and others	2019 (2) MPLJ 373	236	458
Laltu Ghosh v. State of West Bengal	AIR 2019 SC 1058	124	211
Laxmi Bai Raghuvanshi (smt.) & anr. v. State of M.P.	ILR (2018) MP 1308	217*	416
Laxmi Verma (Smt.) v. Sharik Khan & ors.	ILR (2017) MP 1978 (DB)	189	311
Laxmi Yadav v. Barelal Yadav	ILR (2017) MP 2006	161	277
Laxminarayan Agrawal and another v. State of Madhya Pradesh	2019 CriLJ 1962	208*	397
M. Arjunan v. State Rep. by its Inspector of Police	AIR 2019 SC 45	84*	158
M. Revanna v. Anjanamma	AIR 2019 SC 933	106	187
M.A. Antony alias antappan v. State of Kerala	2019 CriLJ 1532 (3 Judge Bench)	180*	302
M.P. Mansinghka v. Dainik Pratah Kaal & others	ILR (2018) MP 821	86*	160
M.R. Krishna Murthi v. New India Assurance Co. Ltd. and others	2019 ACJ 1291	245	476
M/s Eureka Builders and ors. v. Gulabchand s/o Veljee Dand Since Deceased by LRs. and ors.	(2018) 8 SCC 67	48*	109
M/s Ratan Lal Gattani Sons v. Shri Parshwanath Digamber Jain Mandir Katni	Unreported	7*	14
M/s. Royal Sundaram Alliance Insurance Company Ltd. v. Mandala Yadagari Goud and others	AIR 2019 SC 1825 (3 Judge Bench)	316*	610
M/s. Shriram Epc Ltd. v. Rioglass Solar Sa	AIR 2018 SC 4539	47*	108
Madan @ Madhu Patekar v. the State of Maharashtra	2019 (1) ANJ (SC) 109	125*	214
Madan Mohan v. State of Rajasthan and another	2018 (2) Crimes 154 (SC)	119	203
Madhav Prasad Aggarwal and another v. Axis Bank Limited and another	(2019) 7 SCC 158	269	516
Magma General Insurance Co. Ltd. v. Nanu Ram alias Chuhru Ram and others	2018 ACJ 2782	94	167

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd. v. Appellate Authority and another	2018 (4) MPLJ 515 (SC)	123*	210
Mahendran v. State of Tamil Nadu	2019 (1) Crimes 191 (SC)	220*	418
Mahesh Dube v. Shivbodh	AIR 2019 SC 938	136	230
Mahesh Soni v. State of M.P.	ILR (2017) MP 2463 (DB)	300	571
Mala Singh v. State of Haryana	AIR 2019 SC 1026	116	198
Manju Devi v. State of Rajasthan	2019 (2) Crimes 193 (SC)	164	284
Manohar v. State of M.P. and another	ILR (2017) MP 2000	259	496
Manoj Kumar v. State of Uttarakhand	2019 (2) Crimes 102 (SC)	174*	296
Maqbool v. State of Uttar Pradesh and another	AIR 2018 SC 5101	85*	159
Md. Rojali Ali and others v. State of Assam Ministry of Home Affairs through the Secretary	2019 (1) Crimes 165 (SC)	213	405
Meeta Shain (Smt.) v. K.P. Shain	ILR (2018) M.P. Short Note 26	60*	126
Mohammad Faizan and others v. State of M.P.	ILR (2018) MP 734 (DB)	79*	146
Mohammade Yusuf v. Rajkumar	ILR (2017) MP 617	43	102
Mohammed Salim (dead) through Legal Represeantatives and others v. Shamsudeen (dead) through Legal Representatives and others	(2019) 4 SCC 130	237	462
Mohammed Zakir v. Shabana and others	2018 (3) Crimes 491 (SC)	65*	134
Mohd. Hasan v. Kaneez Fatima	AIR 2018 MP 262	28*	62
Mohd. Jahin v. Nabbaji	ILR (2017) MP 1534	40*	98
Mohd. Sahid and ors. v. Raziya Khanam (D) Thr. LRs. and ors.	AIR 2018 SC 4724	35*	81
Mohd. Yunus Munshi v. Public in General	ILR (2017) MP 2434	313*	604
Monu @ Lakhan v. The State of Madhya Pradesh	MCRC No. 3386 of 2019 (Unreported)	288	545
Monu @ Saurabh Kumar Chaturvedi v. State of M.P. & anr.	ILR (2018) M.P. 1565	98	176
Motilal v. State of Madhya Pradesh	2018 Cri.L.J. 4493	83	150
Mr. Ali Abbas Daruwala v. Mrs. Shehnaz Daruwala	2018 (3) RCR (Criminal) 106	145*	249
Ms. Eera Through Dr. Manjula Krippendorf v. State (Govt. of NCT of Delhi) and another	2018 (2) Crimes 99 (SC)	144	246
Ms. Priyanka Nagpal v. State (Govt. of NCT of Delhi) and another	2018 (2) Crimes 162 (SC)	143*	246

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Munishamappa and others v. State of Karnataka	(2019) 3 SCC 393	221	418
Murti Bhawani Mata Mandir Represented through Pujari Ganeshi Lal (D) Through LR Kailash v. Ramesh	AIR 2019 SC 679	105	186
Murugan v. State of Tamil Nadu	2018 (2) Crimes 333 (SC)	128	216
N. Saminathan v. M.P. Thangavelu	2019 CriLJ 1160	166*	288
Nandlal v. State of Maharashtra	(2019) 5 SCC 224	298	566
Nanhu alias Ghanshyam Patel v. State of M.P.	2019 CriLJ 2017	210*	398
Narad Patel v. State of Chhattisgarh	AIR 2019 SC 2288	327*	628
Narendra Kumar Jain v. Nirmalchand Jain	2019 (1) MPLJ 579	102	181
National Insurance Co. Ltd. v. Ganga Devi and others	2019 (2) MPLJ 465	248	478
National Insurance Co. Ltd. v. Mannat Johal and others Etc.	AIR 2019 SC 2079	315	605
Nirmala Devi (Smt.) & ors. v. Smt. Bharti devi & ors.	ILR (2017) MP SN 129	323*	622
Nirmala Dhurve (Smt.) v. Ramgopal	ILR (2017) MP 1972	160	275
Nishan Singh and others v. Oriental Insurance Company Ltd. Through Regional Manager and others	2019 (1) MPLJ 535 (SC) (3 Judge Bench)	139	236
Nitin Sirbhaiya v. Divya Badhwani and others	ILR (2017) MP 1860	152	270
Omanakuttan v. State of Kerala	AIR 2019 SC 2314	303	579
Oriental Insurance Company Ltd. v. Narbheram Power and Steel Pvt. Ltd.	2019 (1) MPLJ 509 (SC) (3 Judge Bench)	103	183
P. Radha Bai and other v. P. Ashok Kumar and another	AIR 2018 SC 5013	36	81
Padam Singh & ors. v. Radhelal & ors.	ILR (2018) MP 1168	201	385
Padmesh S/o Devadutta Gupta and others v. Tirupati Natural Resources and Infra Private Limited and another	2019 Law Suit (MP) 330	257	494
Palakom Abdul Rahiman v. Station House Officer Badiadka Police State Kerala and anr.	2019 (2) Crimes 132 (SC)	179	301
Pappi @ Mehboob v. State of Rajasthan	AIR 2019 SC 904	130*	218
Pappu @ Chandra Prakash v. State of Madhya Pradesh	ILR (2017) MP 1724	132	219
Pawan Kumar v. Babulal since deceased through Legal Representatives and others	(2019) 4 SCC 367	268	515
Periyasami and others v. S. Nallasamy	AIR 2019 SC 1426	167	288

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Pimpri Chinchwada New Township Development Authority v. Vishnudev Cooperative Housing Society and others	AIR 2018 SC 3656	34	75
Pintoo @ Lakhan Singh & anr. v. State of M.P.	ILR (2018) MP 1223 (DB)	219*	417
Poona Ram v. Moti Ram (D) Th. LRs.	AIR 2019 SC 813	137	231
Pooranlal v. State of M.P.	ILR (2017) MP 1944 (DB)	186	309
Prabhu Dayal Rajpur v. State of M.P.	2019 (1) ANJ (MP) 140	171	293
Pradeep Bisoi alias Ranjit Bisoi v. State of Odisha	AIR 2018 SC 4787	14*	24
Prahlad v. State of Rajasthan	2018 (4) Crimes 372 (SC)	68*	136
Prakash Chand Daga v. Saveta Sharma and others	2019 ACJ 1 (SC)	88*	162
Pramod Kumar and another v. Zalak Singh and others	AIR 2019 SC 2465	267	514
Prasanna B. v. Kabeer P.K. and another	2019 ACJ 43	241	468
Preeti Jain (Smt.) & ors. v. Manish Jain	ILR (2017) MP 2378	275	523
Priya Prakash Varrier v. State of Telangana	2019 (1) ANJ (SC) 195 (3 Judge Bench)	183*	304
Punjab Wakf Board v. Sham Singh Harike	(2019) 4 SCC 698	262	504
Puranchand and another v. Kishanlal and others	2019 ACJ 1052	247*	478
R. Shrinivasan & ors. v. State of M.P. and anr.	ILR (2017) MP 738	31	68
Radhakishan v. State of M.P.	2019 (1) ANJ (MP) 180 (DB)	185	307
Radhamma v. H. N. Muddukrishna	AIR 2019 SC 643	127	215
Radharani (Smt.) v. Kamlesh Kumar Kathraya & ors.	ILR (2018) M.P. 1408	57	123
Rafiq Qureshi v. Narcotic Control Bureau Eastern Zonal Unit	AIR 2019 SC 2268	318	612
Raghwendra Sharan Singh v. Ram Prasanna Singh (Dead) by LRs.	AIR 2019 SC 1430	155*	272
Rajendra Kumar v. Gomati Devi and another	2019 (1) MPLJ 450	99*	177
Rajesh and others v. State of Haryana	2019 (2) Crimes 199 (SC)	286*	540
Rajesh v. State of Haryana	2019 (1) ANJ (SC)(Suppl) 73	187*	310
Rajpati Yadav v. State of M.P. and others	2019 (2) MPLJ 395 (DB)	214	407
Rajput Road Lines & anr. v. Devendra Kumar Pranami	ILR (2017) MP 1016	6*	13
Raju Jagdish Paswan v. The State of Maharashtra	2019 (1) Crimes 87 (SC) (3 Judge Bench)	211	398
Raju Manjhi v. State of Bihar	AIR 2018 SC 3592	135	226

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Raju v. State of Haryana	AIR 2019 SC 1136 (3 Judge Bench)	194*	322
Rakhi Shukla v. Manoj Shukla	2019 (1) MPLJ 457 (DB)	78*	146
Ram Sewak Prajapati v. Shiv Kumar Yadav & ors.	ILR (2017) MP 1875	197	325
Ramanda @ Yashvant Gond v. State of M.P.	ILR (2017) MP 2489 (DB)	299	569
Ramasamy (Purchaser) v. Venkatachalapathi (Decree-Holder) and another	(2019) 3 SCC 544	204*	390
Ramcharan v. Damodar & ors.	ILR (2017) MP 1882	178	299
Rameshwar v. Govind & anr.	ILR (2018) M.P. 1512	55	120
Ramkrishan Solvex Private Limited (M/s) v. Superintendent of Police & others	ILR (2017) M.P. 1770	115*	198
Ramla and others v. National Issurance Company Limited and others	2019 ACJ 559	250	481
Rasheed Khan v. Shateesh Chandra Bandel	2018 (3) MPWN 6	52	118
Rashmi Chopra and ors. v. The State of Uttar Pradesh and anr.	2019 (2) Crimes 301 (SC)	307	587
Reema Salkan v. Sumer Singh Salkan	AIR 2018 SC 4606	11	19
Reena Hazarika v. State of Assam	AIR 2018 SC 5361	23	50
Reeta Bais (Smt.) v. Vishwapratap Singh Bais	ILR (2017) MP 2441 (DB)	292	
Ripudaman Singh v. Balkrishna	AIR 2019 SC 1625	255	491
Rohitbhai Jivanlal Patel v. State of Gujarat and anr.	2019 (1) Criems 291 (SC)	212	402
Rupali Devi v. State of Uttar pradesh & ors.	2019 (2) Crimes 139 (SC)	306	584
S. Sarojini Amma v. Velayudhan Pillai Sreekumar	AIR 2018 SC 5232	50	111
S.K. Miglani v. State NCT of Delhi	2019 (2) Crimes 290 (SC)	279	530
Sachin Kumar Singhraha v. State of Madhya Pradesh	2019 (1) Crimes 278 (SC) (3 Judge Bench)	231	449
Sadayappan alias Ganesan v. State, Represented by Inspector of Police	AIR 2019 SC 2191	301	573
Sainik Grih Nirman Sehkari Samiti, Jabalpur v. M.P. Rajya Sehkari Awas Sangh Maryadit and others	2019 (1) MPLJ 571	107*	189
Sainik Mining Allied Services Ltd. (M/s) v. Northern Coal Fields Ltd. & ors.	ILR (2018) MP 1925	270	517
Sajjan Singh v. Kantabai alias Baban Bai and others	AIR 2019 MP 67	156*	272

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Samir Ahmed Rafiqahmed Ansari v. The State of Gujarat	2018 (4) Crimes 220 (SC)	53*	119
Sandeep Jain v. Mrs. Nivedita Jain	ILR (2018) MP 1159	27	58
Sandeep Khanuja v. Atul Dande and anr.	(2017) 3 SCC 351	38	88
Sangam Sahakari Grih Nirman Samiti Mydt. v. Smt. Jethibai Purushwani & ors.	ILR (2017) MP 2548	271	518
Santosh Maruti Mane v. State of Maharashtra	2019 CriLJ 1331 (3 Judge Bench)	181*	302
Saraswati Palariya and others v. New India Assurance Co. Ltd. And others	2019 ACJ 42 (SC) (3 Judge Bench)	92*	166
Sarla Devi and others v. Arvind Jain and others	2019 ACJ 1342	242	472
Sasikala Pushpa and ors. v. State of Tamil Nadu	2019 (2) Crimes 279 (SC)	277	528
Satish v. Murlidhar	ILR (2017) MP 1706	101	179
Satishchandra Ratanlal Shah v. State of Gujarat and another	2019 (2) Crimes 1 (SC)	192	318
Satya Raj Singh v. State of Madhya Pradesh	(2019) 3 SCC 615	176*	298
Savatram Rampratap Mills v. Radheyshyam s/o Laxminarayan Goenka (D) thr. LRs. and another	AIR 2018 SC 3916	146	250
Savita and others v. Divisional Manager, Maharashtra State Road Transport Corporation	2018 ACJ 2863	93*	167
Sebastiani Lakra and others v. National Insurance Company Ltd. and another	AIR 2018 SC 5034 (3 Judge Bench)	1	1
Sh. Narendra Kumar Srivastava v. State of Bihar and others	2019 (1) Crimes 49 (SC)	222	422
Shailndra Kumar Jain and others v. Maya Prakash jain and others	AIR 2019 SC 1900	265	511
Shantaben and others v. National Power Transport and another	2019 ACJ 1784	314*	605
Sharad Hiru Kolambe v. State of Maharashtra and ors.	AIR 2018 SC 4595	29	62
Shio Shankar Dubey and others v. State of Bihar	AIR 2019 SC 2275	290	549
Shiv Kumar Kushwah v. State of Madhya Pradesh	ILR (2017) MP 1750	134	224
Shivaraj v. Rajendra and another	2018 ACJ 2755	90	165
Shobha Jain (Smt.) v. State of M.P.	ILR (2017) MP 2555 (DB)	324*	623
Shyam @ Bagasram v. State of M.P.	ILR (2018) MP 1805	285*	540

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Shyam Singh (Mst.) & ors. v. State of M.P.	ILR (2017) MP 1449	195	322
Shyama Patel (Smt.) v. Mehmood Ali & another	ILR (2018) MP 812	95*	170
Siddagangaiah (Dead) through LRs. v. N.K. Giriraja Shetty Dead) Though LRs.	2019 (2) MPLJ 116 (SC)	157*	273
Skol Breweries Ltd. v. Som Distilleries and Breweries Ltd.	AIR 2019 MP 41	203	388
Smt. Baljeet Kaur v. Harjeet Singh	2018 (3) MPWN 8	77	144
Smt. Durga w/o Shri Bherulal Meena v. State of Rajasthan	2019 Law Suit (RAJ) 180 (DB)	310	593
Smt. Kalpana Mudgal v. Vinod Kumar Sharma and others	AIR 2019 MP 78	159*	274
Smt. Shamim v. State (GNCT of Delhi)	AIR 2018 SC 4529	71	138
Smt. Sushila Sharma v. Sunil Malviya	AIR 2019 MP 57	110	190
Sneh Lata Goel v. Pushplata	AIR 2019 SC 824	104*	185
Sooma Devi v. Ramkripal Mishra	ILR (2017) MP 2561	326	626
Sopanrao and another v. Syed Mehmood and others	(2019) 7 SCC 76 (3 Judge Bench)	312	601
Sow. Chhaya v. State of Maharashtra	2019 CriLJ 927	177*	298
State (Govt. of NCT of Delhi) v. Pankaj Chaudhary	AIR 2018 SC 5412	17	29
State by Karnataka Lokayukta Police Station, Bengaluru v. M.R. Hiremath	AIR 2019 SC 2377	276	525
State by the Inspector of Police, Chennai v. S. Selvi and another	AIR 2018 SC 81	18	34
State of Gujarat v. Afroz Mohammed Hasanfatta	2019 (1) Crimes 56 (SC)	207	393
State of Himachal Pradesh and another v. Vijay Kumar alias Pappu and another	AIR 2019 SC 1543	169*	290
State of Himachal Pradesh v. Happy	2019 LawSuit (HP) 393	309	589
State of Himachal Pradesh v. Manga Singh	2019 (1) ANJ (SC) 333	305	580
State of Jharkhand v. Surendra Kumar Srivastava and others	(2019) 4 SCC 214	158*	274
State of Kerala v. Rasheed	2018 (4) Crimes 288 (SC)	19	37
State of M.P. and anr. v. Shri Birani Sons, Indore	ILR (2018) MP 1135	46*	107
State of M.P. and others v. Laxman Prasad Raikwar	2018 (4) MPLJ 657 (FB)	147*	251
State of M.P. v. Keshovrao	ILR (2017) MP 2480 (DB)	304*	580

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
State of Madhya Pradesh v. Chhaakki Lal	2018 (4) Crimes 238 (SC)	30	65
State of Madhya Pradesh v. Harjeet Singh & anr.	2019 (1) Crimes 179 (SC)	228	438
State of Madhya Pradesh v. Kanha @ Omprakash	AIR 2019 SC 713	133	222
State of Madhya Pradesh v. Mohammad Shahid and another	2019 CriLJ 803 (DB)	230	443
State of Madhya Pradesh v. Rakesh Lavaniya	AIR 2019 SC 1597	215	409
State of Maharashtra & anr. v. Sayyed Hassan Sayyed Subhan and others	2018 (4) Crimes 167 (SC)	76*	144
State of Mizoram v. Dr. C. Sangnaghina	AIR 2018 SC 5342	96*	170
State of Orissa v. Mhimananda Mishra	(2018) 10 SCC 516	20*	42
State of Punjab v. Rakesh Kumar	2019 CriLJ 982	170	291
State of U.P. v. Raghuvir and another	2019 (1) Crimes 40 (SC)	64*	134
State of Uttar Pradesh v. Faquirey	2019 (1) Crimes 126 (SC)	223	427
State Represented by Inspector of Police, central Bureau of Investigation v. M. Subrahmanyam	(2019) 6 SCC 357	325	623
State Represented by the Drugs Inspector v. Manimaran	AIR 2019 SC 655	122	209
Subhash Chand v. State of Punjab	AIR 2019 SC 1133	182*	303
Subhash Chandra Sen (dead) through LRs. And others v. Nabin Sain (dead) through LRs.	2019 (1) MPLJ 292 (SC)	54*	120
Sudarsan Puhan v. Jayanta Ku. Mohanty and others	(2018) 10 SCC 552	3	7
Sukhdev Pakharwal v. Smt. Rekha Okhle & anr.	ILR (2018) M.P. 1571	59*	125
Sunil Kumar Gupta and others v. State of Uttar Pradesh and others	AIR 2019 SC 1174	168*	289
Sunita v. Rajasthan State Road Transport Corporation	AIR 2019 SC 994	138	233
Suraj @ Suresh v. State of M.P.	ILR (2017) MP 1475	21*	43
Suraj Kero v. State of M.P. Through S.P.E. Lokayukt	ILR (2017) MP 1237	41	98
Surendra Kumar Tiwari v. State of M.P.	ILR (2018) MP 1826	293*	553
Surinder Kumar Khanna v. Intelligence Officer Directorate of Revenue Intelligence	AIR 2018 SC 3574	141	239

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Surinder Singh Deswal @ Col. S.S. Deswal v. Virender Gandhi	2019 Law Suit (SC) 1245	321	615
Sushil Nigam v. Jahur Khan and another	2019 (2) MPLJ 196	151*	269
Sushila Bai & ors. v. Smt. Rajkumari & ors.	ILR (2017) MP 662	25	55
Swapan Kumar Chatterjee v. Central Bureau of Investigation	2019 (2) Crimes 32 (SC)	165	286
T. Ramalingeswara Rao (Dead) Thr. LRs. and another v. N. Madhava Rao and others	AIR 2019 SC 1777	328*	628
T.P. Murugan (Dead) Through LRs. v. Bojan and Posa Nandhi Represented Through POA Holder, T.P. Murugan	AIR 2018 SC 3601	142	244
Tanu Ram Bora v. Promod Ch. Das (D) through LRs.	AIR 2019 SC 927	150	254
Tejaswini Gaud and others v. Shekhar Jagdish Prasad Tewari and others	AIR 2019 SC 2318	295	560
Thangasamy v. State of Tamil Nadu	2019 (1) Crimes 185 (SC)	227*	437
The New India Assurance Co. Ltd. v. Kiran and others	2019 ACJ 1027	239*	465
Thongam Tarun Singh v. State of Manipur	AIR 2019 SC 2456	283	538
U.P. State Road Transport Corporation v. National Insurance Co. Ltd. and others	2019 ACJ 269 (SC)	91*	166
UCO Bank and others v. Rajendra Shankar Shukla	2018 (4) MPLJ 1 (SC)	44	105
Union of India v. Mubarak alias Muhammed Mubarak	AIR 2019 SC 2428	206	391
United India Insurance Company v. Sanny @ Sanjay and others	2018 ACJ 2764	89	162
Uttam Chand Verma & anr. v. State of M.P. and anr.	ILR (2017) MP 1519	16*	28
V. Ravi Kumar v. State, Rep. By Inspector of Police, District Crime Branch, Salem, Tamil Nadu & ors.	2018 (4) Crimes 509 (SC)	62	127
Varinder Kumar v. State of Himachal pradesh	2019 (1) Crimes 128 (SC) (3 Judge Bench)	253	485
Varun Pahwa v. Mrs. Renu Chaudhary	AIR 2019 SC 1186	153*	271
Venugopal Padayachi v. V. Pichaikaran	(2018) 10 SCC 548	49*	110
Vidyalakshmi @ Vidya v. State of Kerala	2019 (1) Crimes 101 (SC)	218*	417
Vijay A. Mittal and others v. Kulwant Rai (Dead) and another	(2019) 3 SCC 520	260	497

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Vijay Hathising Shah and another v. Gitaben Parshottamdas Mukhi and others	AIR 2019 SC 1119	154*	272
Vijay Mahadeorao Kubade v. State of Maharashtra	2019 (2) MPLJ 529 (SC)	235	456
Vijay Mohan Singh v. State of Karnataka	(2019) 5 SCC 436	302	575
Vijay Raikwar v. State of Madhya Pradesh	2019 (2) Crimes 36 (SC)	191	317
Vikram Johar v. State of Uttar Pradesh and another	AIR 2019 SC 2109	280	532
Vimla Devi and others v. National Insurance Co. Ltd. and others	2019 ACJ 454	249	479
Vinay Sapre v. State of M.P.	ILR (2018) MP 815	67	136
Viran Gyanlal Rajput v. The State of Maharashtra	2018 (4) Crimes 474 (SC)	72*	140
Virendra Singh Rana v. Pratap Singh and others	2019 ACJ 1499	317	610
Wockhardt Limited v. Torrent Pharmaceuticals Ltd.	AIR 2018 SC 5106	33*	74
X Minor Through: His Mother v. State of NCT of Delhi	2019 Law Suit (Del) 1862	311	600
Y.P. Sudhanva Reddy and others v. Chairman and Managing Director, Karnataka Milk Federation and others	2019 (1) MPLJ 316 (SC)	87*	161
Yogendra @ Jogendra Singh v. The State of Madhya Pradesh	2019 (1) ANJ (SC) (Suppl.) 91	224	427
Young Birds v. Bhagwandas	2019(3) MPLJ 223	263*	507

CORRIGENDUM

Readers are requested to make following correction in Note No. 201 of the JOTI Journal, 2019:

In the heading and third line of the placitum of Note No. 201 ‘Section 47 and Order 21 Rule 47’ be read as ‘Section 47 and Order 21 Rule 97’